चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

सरकार इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती

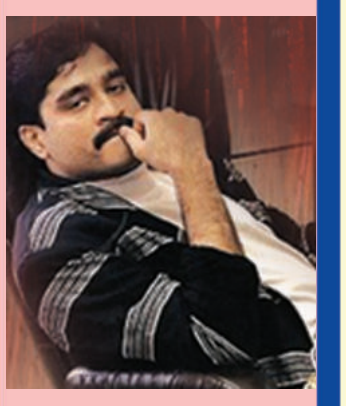

पेज 3

दिग्विजय सिंह का आख़िरी इंटरव्यू

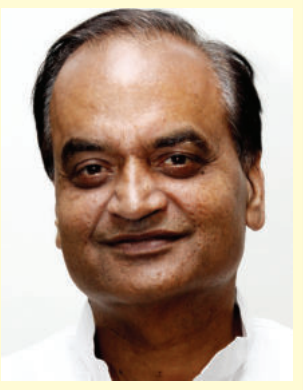

पेज 6

साई की महिमा

पेज 12

वर्ल्ड कप ड्रीम, भारतीय टीम और बीसीसीआई

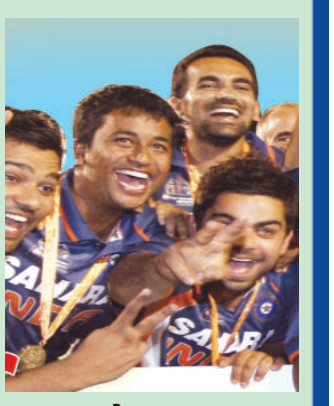

पेज 15

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 5 जुलाई–11 जुलाई 2010

सोनिया गांधी और गुजरात

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भनक भी नहीं लगी और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके चारों ओर बेहद ख़ामोशी से शिकंजा कस दिया. गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में भले ही दो साल से ज़्यादा का वक़्त है, पर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के लिए अपनी सियासत की बिसात बिछा दी है. नरेंद्र मोदी को चित करने के लिए सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में गुजरात की उन तीन ख़ास शख्सियतों हर्ष मंदर, फ़राह नक़वी और मिराई चटर्जी को सदस्य के तौर पर शामिल किया है, जो पिछले कई सालों से गुजरात के दंगा पीड़ितों के हक़ की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की नीतियों की खुली आलोचना भी कर रहे हैं. इन्हीं लोगों के ज़रिए सोनिया गांधी मुसलमानों का भरोसा जीतने का ख्वाब संजोए बैठी हैं.

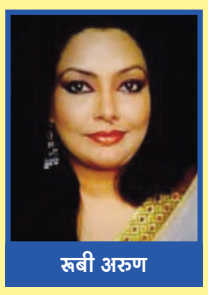

रूबी अरुण

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जंग की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नया एजेंडा है. हालांकि नरेंद्र मोदी सोनिया के इस नए एजेंडे से वाक़िफ़ नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को हथियार बनाकर मोदी के ख़िलाफ़ जंग जीतने का एजेंडा गुजरात में सोनिया गांधी की राजनीतिक जिजीविषा की मुनादी है. इस महत्वाकांक्षी राजनीतिक युद्ध की कमान सोनिया गांधी ने अपने हाथों में रखी है. हथियार बनाया है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को. सियासत की इस बिसात परस सोनिया के मोहरे हैं गुजरात के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अफसर हर्ष मंदर, सामाजिक कार्यकर्ता फराह नक़वी एवं मिराई चटर्जी. सोनिया गांधी के ये तीनों अहम प्यादे गुजरात में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ सोनिया गांधी के जंग का आग़ाज़ करेंगे. साफ़ है कि दंगे और फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामलों में विवादास्पद रूप से चर्चित नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ सोनिया गांधी ने अपनी सियासी धार तेज़ कर दी है, और उन्हें दबोच लेने का इरादा कर लिया है. सोनिया यह समझ चुकी हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस को देश पर बेरोक–टोक शासन करना है तो उन्हें गुजरात से नरेंद्र मोदी का सियासी शामियाना उखाड़ना होगा. इस तरह कांग्रेस अपनी प्रमुख विरोधी, भारतीय जनता पार्टी को भी औकात में ला सकती है. लिहाज़ा सोनिया एक तीर से कई शिकार करना चाहती हैं. पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर ने अभी तक दंगों से जुड़े 2000 से ज़्यादा मामलों को अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए खुलवाया है. अब चूंकि, हर्ष मंदर ने अभी तक दंगों से जुड़े 2000 से ज़्यादा मामलों को कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए खुलवाया है. अब गुजरात के अल्तसंख्यकों का दिल जीतने का यक़ीनन इससे बेहतर तरीका फ़िलहाल सोनिया गांधी को नहीं मिल सकता. वे जानती हैं कि , अगर वे इस दांव से गुजरात के मुसलमानों का भरोसा पाने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर पूरे देश के मुसलमान कांग्रेस के मुरीद हो जाएंगे. और आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस तिलिस्म को तोड़ना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए निहायत चुनौतियों भरा होगा.

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ सोनिया गांधी की युद्ध रणनीति के चौथी दुनिया के पास पुख्ता सबूत हैं. नरेंद्र मोदी की खुली मुख़ालफ़त और सांप्रदायिकता विरोधी काम करने के लिए केंद्र सरकार ने इन तीनों द्वारा संचालित स्वयंसेवी संगठनों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है. हर्ष मंदर इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटी नामक संगठन के लिए भी काम करते हैं और इस संगठन से कांग्रेस का गहरा अनुराग है. हर्ष मंदर इस संस्थान के लिए फंड जुटाने का काम करते हैं और इस ख़ातिर वह अमेरिका स्थित मुस्लिम ज़िहादियों से भारत में अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर अरबों रुपये वसूलते हैं. दावा ये किया जाता है कि दान के नाम पर मिले इन पैसों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के हितों में ही किया जाता है.

पर, सोनिया गांधी महज़ इतना ही करके चुप बैठना नहीं चाहतीं. उनकी कोशिश है कि नरेन्द्र मोदी के पर साधा गशा उनका निशाना अचूक साबित हो. इसके लिए वे सांप्रदायिकता विरोधी क़ानून का भी पूरा इस्तेमाल करना चाहती हैं. उनकी कोशिश है कि सरकार जल्द से जल्द यह क़ानून बनाए ताकी इसका फंदा बनाकर वह नरेंद्र मोदी के गले में डाल सकें. अभी नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ तमाम मामले अदालत में हैं. इस दरम्यान सांप्रदायिकता विरोधी क़ानून बनाने में अगर सरकार सफल हो जाती है तो नरेन्द्र मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो सकता है.

सोनिया गांधी के प्यादे हर्ष मंदर ने गुजरात दंगों के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया था और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अमन बिरादरी नामक संगठन बनाया था. सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक फराह नक़वी अनहद नामक स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हैं और मिराई चटर्जी यही काम स्वतंत्र तरीके से करती रही हैं. ये तीनों सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक नीतियों की मुख़ालफ़त भी करते रहे हैं. फ़राह और मिराई पिछले लंबे अर्से से अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिलाओं के सम्मान और उनकी शिक्षा के मुद्दे पर भी काम करती आ रही हैं. गुजरात के दूर–दराज़ के ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले अशिक्षित मुसलमानों के बीच इनकी पकड़ बन चुकी है. जिन दंगा–पीड़ित परिवारों की इन्होंने मदद की है, वे इनकी हर बात मानते हैं. ज़ाहिर है इन तीनों की मार्फ़त ये सभी कांग्रेस के वोट बैंक में तब्दील हो सकते हैं. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में इन तीनों को शामिल करने के पीछे ये बातें ख़ास रही है.

एक और अहम बात यह भी है कि सोनिया गांधी, नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सियासी जंग तो जीतना चाहती हैं, लेकिन गुजरात में अपने किसी सियासी सिपहसालार पर भरोसा भी नहीं करतीं. इसका राजनीतिक संदेश यह भी जाता है कि सोनिया की नज़र में गुजरात प्रदेश कांग्रेस का कोई नेता इतना योग्य नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ माहौल खड़ा करने का माद्दा रखता हो. पिछली बार जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी के मुक़ाबले प्रदेश स्तर का कोई कांग्रेसी नेता नहीं था. नरेन्द्र मोदी ने भी सीधे–सीधे सोनिया गांधी को ही ललकारा था. ऐसे में मोदी के सामने सोनिया गांधी को ही सीधे मैदान में उतरना पड़ा. फिर भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई. मौज़ूदा वक़्त में कांग्रेस की सबसे बड़ी ग़रज़ भी यही है कि सबसे पहले, गुजरात में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जम कर माहौल तैयार किया जाए, ताकि अगले विधानसभा चुनावों में गुजरात के मतदाताओं का रुख़ कांग्रेस की तरफ़ करने में मोड़ने में उसका इस्तेमाल किया जा सके. हर्ष मंदर, फराह नक़वी एवं मिराई चटर्जी ऐसा माहौल बनाने की भूमिका बख़ूबी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वे राजनीतिक शख़्सीयत नहीं हैं. इसलिए लोग–बाग उनकी बातों पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं. पर, ऐसा भी नहीं है कि इतना भर कर देने से गुजरात में कांग्रेस की दुश्वारियां कम हो गई हों. जिन लोगों को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मुलम्मे में लपेट कर सोनिया गांधी गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना चाहती हैं, ख़ुद उनकी ही साख गुजरात में कुछ अच्छी नहीं है. सोनिया के इस फ़ैसले से उनके कुछ बेहद अजीज़ लोग खुश नहीं हैं. इन लोगों का ताल्लुक भी गुजरात से है, जिनकी गुजरात से जुड़ी अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं. हर्ष मंदर अमन बिरादरी नामक एक स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं और अपने भाषणों में पाकिस्तान की खुली हिमायत करते हैं. वह एक्शन एड नामक अंतराष्ट्रीय संगठन के भारत में कंट्री हेड भी हैं. एक्शन एड पर यह आरोप है कि वह अमेरिका स्थित उन ज़िहादियों से आर्थिक मदद लेता है, जो कश्मीर में जिहाद कर रहे लोगों को मदद करते हैं. एक्शन एड गुजरात में जिस शैली से काम करता है, वह भी विवादास्पद रही है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फाल्दू कहते हैं कि एक्शन एड और हर्ष मंदर भारत में मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. ख़ुफ़िया एजेंसियों ने भारत सरकार को इस बारे में कई बार चेताया भी है, पर सरकार ने जानबूझ कर आंखें बंद कर रखी हैं. आ सी फाल्दू कहते हें कि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी जैसे तूफ़ान का सामना करने के लिए जिस दरख्त का सहारा लिया है, उसकी जड़ों में भी भ्रष्टाचार के दीमक लगे हैं. हर्ष मंदर हों या फराह नक़वी, कोई दूध का धुला नहीं है. सवाल उठता है कि सोनिया गांधी ने भूखे ग़रीब बच्चों का पेट भरने और मुसलमानों के गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए हर्ष मंदर को 100 करोड़ रुपये का अनुदान तो दे दिया, पर इस बात पर ग़ौर करने की ज़हमत क्यों नहीं उठाई कि वे जिसके बूते इतना बड़ा दांव खेल रही हैं उसकी फितरत कैसी है. वे काम कम करते हैं ढोल ज़्यादा पीटते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हर्ष मंदर ने सराय बस्ती इलाक़े में स्वयंसेवा के नाम पर जो गोरखधंधा फैला रखा है, उसका गवाह पूरा शहर है. हर्ष मंदर को एक्शन इंडिया से भी बेशुमार आर्थिक अनुदान मिलता है. दिल्ली सरकार से भी वह संस्था के नाम पर मोटी राशि वसूलते हैं. इसके अलावा हर्ष मंदर को जमायत–ए–उलेमा–ए–हिंद से भी भरपूर पैसा मिलता है. अल्पसंख्यक और ग़रीब बच्चों की शिक्षा के नाम पर हर्ष ने जिस छात्रावास की स्थापना की है, वहां दो साल बीत जाने के बाद भी आज तक बच्चों की पढ़ाई–लिखाई, खेलकूद, काउंसलिंग, ड्रग डी–एडिक्शन एवं रीक्रिएशन जैसी गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकी हैं. बच्चों के बीमार पड़ने पर सही इलाज़ और दवा तक की व्यवस्था नहीं है. जब बच्चों की तबियत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है. न ही इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को उचित मानदेय दिया जाता है. महज़ दो हज़ार से पांच हज़ार के मानदेय पर रखे गए कर्मचारियों से पंद्रह से लेकर बीस घंटे तक काम लिया जाता है. महीनों गुज़र जाते हैं और हर्ष मंदर अपने ही संस्थानों की ओर झांकते तक नहीं. ऐसा आदमी गुजरात में सोनिया गांधी की डूबी हुई नाव को भला क्या किनारे लगा पाएगा? सोनिया गांधी का राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का भरपूर इस्तेमाल का तो इरादा है पर किसी को उनके मंसूबों का अंदाज़ा हो, वे यह नहीं चाहती. इसलिए उनकी सरकार की यह कोशिश है एनएसी के ज़रिए कि वे अपने कामों में बदले तेवर और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ सोनिया गांधी की युद्ध रणनीति के चौथी दुनिया के पास पुख्ता सबूत हैं. नरेंद्र मोदी की खुली मुख़ालफ़त और सांप्रदायिकता विरोधी काम करने के लिए केंद्र सरकार ने इन तीनों द्वारा संचालित स्वयंसेवी संगठनों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है. हर्ष मंदर इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटी नामक संगठन के लिए भी काम करते हैं और इस संगठन से कांग्रेस का गहरा अनुराग है.

सांप्रदायिकता विरोधी कानून के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को भी सोनिया गांधी ने अपनी सूची में सबसे ऊपर जगह दी है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चंद्रशेखर के बाद पुलक चटर्जी!

कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को अप्रत्याशित रूप से मिले एक साल के एक्सटेंशन ने लगातार दो बैचों के नौकरशाहों को इस पद की दौड़ से ही बाहर कर दिया. हालांकि इस फ़ैसले से यह भी स्पष्ट है कि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विश्वास हासिल है. कैबिनेट सचिव के सेवा विस्तार के लिए नियम-क़ायदों को केवल थोड़ा सा घुमाया गया और चंद्रशेखर अब अगले साल जून तक इस पद पर बने रहेंगे. इसके साथ ही लोगों की निगाहें 2011 पर टिक गई हैं. चंद्रशेखर के उत्तराधिकारियों को लेकर अटकलबाज़ियों का दौर अभी से शुरू हो गया है. सूत्रों पर भरोसा करें तो 1974 बैच के आईएएस अधिकारी पुलक चटर्जी के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है. चटर्जी फ़िलहाल वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. सूत्रों का तो यह भी कहना है कि चंद्रशेखर को दूसरी बार सेवा विस्तार देने का मक़सद ही यही है कि चटर्जी वर्ल्ड बैंक के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर वापस लौट सकें. हालांकि ये केवल अटकलें ही हैं और इनकी बिना पर भविष्य में इतना दूर देखना शायद ठीक नहीं हैं. अभी तो यही हक़ीक़त है कि चंद्रशेखर जून 2011 तक देश के शीर्ष नौकरशाह बने रहेंगे, यदि राष्ट्रमंडल खेलों के चलते उनके राजयोग में कोई बाधा नहीं पड़ी तो!

सीएजी की निगाहों में रहेंगे अधिकारी

थोड़े दिनों पहले कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के एक फ़ैसले से नौकरशाहों की बांछें खिल गई थीं. कैट के इस फ़ैसले में कहा गया था कि यदि अधिकारियों को लगे कि उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) में गलतियां हैं तो वे इसकी टिप्पणी ख़ुद ही एसीआर में कर सकते हैं. ज़ाहिर है, अधिकारी इस फ़ैसले से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के एक फ़ैसले ने एक बार फिर उनकी पेशानी पर बल डाल दिए हैं. पीएमओ ने सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) को निर्देश दिया है कि वह नौकरशाहों द्वारा ज़िले में किए गए काम की समीक्षा करे. इसका मतलब यह है कि अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अब इस आधार पर तैयार की जाएगी कि ज़िले के विकास में उनका क्या योगदान है. केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उनके प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाएगी. सीएजी विनोद राय ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में ज़िले में उनके प्रदर्शन को ख़ास अहमियत दी जाएगी. बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती. इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि सीएजी की समीक्षा पर संबद्ध अधिकारी क्या प्रतिक्रिया देता है. सीएजी अपनी समीक्षा से राज्य के मुख्य सचिव को भी अवगत कराएगा. एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के साथ जिस तरह रोज़ नए-नए पक्ष जुड़ रहे हैं, अधिकारी अपनी आंखें खुली रखें, इसी में भलाई है.

सेल को मिला नया चेयरमैन

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को आख़िरकार नया चेयरमैन मिल ही गया. भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (भेल) के डायरेक्टर-फाइनेंस रहे सी एस वर्मा को एस के रूंगटा की जगह नियुक्त किया गया है, जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए थे. हालांकि सूत्रों के मुताबिक़, वर्मा की नियुक्ति में भी कई अड़चनें आईं. इस्पात मंत्रालय के अधिकारी किसी नौकरशाह की नियुक्ति के लिए ज़ोर लगा रहे थे, काफ़ी ज़द्दोजहद के बाद ही वर्मा के नाम को हरी झंडी मिल पाई. इस बीच सेल ने झारखंड में एक इस्पात प्लांट के लिए कोरियाई कंपनी पॉस्को के साथ करार भी किया है. इस्पात सचिव अतुल चतुर्वेदी इस करार के पक्ष में थे और उनकी इच्छा थी कि इसकी प्रक्रिया रूंगटा के पद पर रहते ही पूरी हो जाए. उन्हें शायद यह लगा हो कि रूंगटा के बिना इसमें कहीं अड़ंगा न लग जाए. रोचक बात यह भी है कि रूंगटा के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भी विराम लग गया है. रूंगटा पेट्रोनेट एलएनजी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद की दौड़ में थे, लेकिन वह इस दौड़ में पीछे रह गए. यह बाजी ए के बाल्यान के हाथ लगी, जो ओएनजीसी के डायरेक्टर-एचआर थे. बहरहाल नए चेयरमैन की नियुक्ति के साथ सेल एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है.

dilipcherian@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

अनीता का प्रमोशन

अनीता कौल को पदोन्नति देते हुए मानव संसाधन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया है. अनीता अभी मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थीं. वह कर्नाटक कैडर की 1979 बैच की आईएएस अधिकारी हैं.

सुनील बने अतिरिक्त सचिव

सुनील कुमार को मानव संसाधन मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. इससे पहले कुमार इसी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे. उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था. वह चंडीगढ़ कैडर के 1979 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

रमेश बनेंगे मपेडा निदेशक

व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (मपेडा), कोच्ची में निदेशक (मार्केटिंग) का पद रिक्त पड़ा हुआ है. यह पद कुरुविला थॉमस के फरवरी 2010 में रिटायर हो जाने से खाली हुआ. इस पद के लिए 1999 बैच के आईटीएस अधिकारी एन रमेश सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

मधुकर बन सकते हैं संयुक्त सचिव

मधुकर गुप्ता राजस्थान कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. ख़बर है कि उन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव या इसी के समकक्ष पद के लिए बनाई गई सूची में शामिल किया जा सकता है.

लाल गृह मंत्रालय में

सूत्रों के मुताबिक, 1995 बैच के आईटीएस अधिकारी मुकेश लाल गृह मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं. वह आर एस शर्मा की जगह लेंगे. शर्मा को अप्रैल 2010 में निलंबित कर दिया गया था.

सोनिया गांधी और गुजरात

पृष्ठ 1 का शेष

कलेवरों का नमूना भी पेश कर सकें. लिहाज़ा सांप्रदायिकता विरोधी क़ानून के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को भी सोनिया गांधी ने अपनी सूची में सबसे ऊपर जगह दी है. यहां यह ज़िक्र करना लाज़िमी है कि हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त भी हैं और वह भोजन के अधिकार क़ानून को लेकर भी गुजरात में काम कर रहे हैं. लिहाज़ा सांप्रदायिकता विरोधी क़ानून के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी सोनिया ने अपनी सूची में सबसे उपर की जगह दी है. तो यहां यह ज़िक्र करना भी बेहद लाज़िमी है कि हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त भी हैं. और वे भोजन के अधिकार के क़ानून को लेकर गुजरात में काम भी कर रहे हैं. उनका नारा रहा है-घर-घर चुल्हा ,घर-घर दाना. पर इस संबंध में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कुछ और कहती है. रिपोर्ट के मुताबिक़ हर्ष मंदर को अनुदान तो भरपूर मिला पर उनकी संस्था गुजरात के दंगा-पीड़ितों या भूखे लोगों के घरों में भोजन का इंतज़ाम कराने में कामयाब नहीं रहे. फिर भी भारत सरकार से उन्हें 100 करोड़ रुपयों का अनुदान कैसे मिल गया. इसकी विवेचना की जा रही है.

गुजरात के खाद्य मंत्री नरोत्तमभाई त्रीकमदास पटेल कहते हैं कि हर्ष मंदर जब अधिकारी थे, तब भी काम करने की जगह ढोल ज़्यादा पीटते थे. अब समाजसेवा के नाम पर भी वही सारा प्रपंच फैला रहे हैं. नरोत्तमभाई कहते हैं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस का मूल चरित्र ही कथनी और करनी का फ़र्क़ रहा है. इसलिए हर्ष मंदर से सोनिया गांधी की साठगांठ कोई आश्चर्य पैदा नहीं करती, पर इन सारी कवायदों के बावजूद कांग्रेस गुजरात में नरेंद्र भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. लेकिन पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री एवं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता शंकर सिंह वाघेला

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

कहते हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में ऐसे समाजसेवकों और आम अवाम से जुड़े लोगों को शामिल करके आलाकमान ने कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का संदेश दिया है. जिन हर्ष मंदर और फराह नक़वी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, उन्होंने गुजरात के दंगा पीड़ितों के ज़ख्मों पर मलहम लगाने का काम किया है. यही वे लोग हैं जो दंगे का नासूर भोग रहे बेबस और मज़लूमों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए आए हैं.इन्हीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की कोशिशों का नतीज़ा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्म ढाने से घबराती है. इसलिए सोनिया गांधी का यह क़दम यक़ीनन न सिर्फ़ गुजराती मुसलमानों, बल्कि देश भर के अल्पसंख्यकों के हित में है.

लेकिन बड़ौदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता युसुफ भाई कहते हैं कि दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर गुजरात के हिंदुओं के मन में यह डर बैठा दिया था कि अगर वे नहीं होंगे तो गुजरात के हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल उसी तर्ज़ पर सोनिया गांधी भी काम कर रही हैं. वह अपने तीनों दूतों के ज़रिए गुजरात और देश के दूसरे मुसलमानों को यह भरोसा दिलाना चाहती हैं कि देश में मुसलमानों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार अगर कोई दिलवा सकता है तो वह सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी ही है और भाजपा एवं भाजपाई मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जान के सबसे बड़े दुश्मन हैं. कहने को सोनिया के इस एजेंडे में खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और रोज़गार जैसे अहम मसले शामिल हैं, पर जिस तरीके से सोनिया राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के ज़रिए अपना पासा फेंक रही हैं, उससे यही बात ज़ाहिर हो रही है कि कांग्रेस का मक़सद देश में सांप्रदायिक सौहार्द क़ायम करना नहीं, बल्कि ख़ुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करना ज़्यादा है.

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 17
दिल्ली, 05 जुलाई -11 जुलाई 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9899815169
प्रसार + 91 9868013165
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

पिछले कुछ सालों के दौरान सीबीआई ने 11 देशों से 34 भारतीय अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया.

भारत के भगोड़े

सरकार इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती

राजनीतिक गलियारों में आजकल वारेन एंडरसन को देश से भगाए जाने का मामला गर्म है. एंडरसन को किसने भगाया, क्यों भगाया और किसके कहने पर भगाया, जैसे सवाल कई नेताओं के लिए जी का जंजाल बन गए हैं. लेकिन सवाल अकेले एंडरसन का नहीं है. गुनहगारों की फ़ेहरिश्त में और भी ऐसे कई नाम हैं, जिन्हें आज तक हमारी सरकार पकड़ने में नाकाम रही है. उल्टे उनके प्रत्यर्पण के नाम पर वह आम आदमी की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पानी की तरह बहा रही है. बावजूद इसके एक भी बड़े अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं हो सका है. कुछ ऐसे ही भगोड़े अपराधियों और उनके प्रत्यर्पण के सरकारी प्रयासों पर *चौथी दुनिया* की ख़ास रिपोर्ट.

क्या है प्रत्यर्पण क़ानून?

किसी भी दो देश के बीच एक अपराधी का प्रत्यर्पण तभी संभव है, जब उन दोनों के बीच प्रत्यर्पण संधि हो. प्रत्येक देश का अपना एक प्रत्यर्पण क़ानून होता है. भारत के प्रत्यर्पण क़ानून को भारतीय प्रत्यर्पण क़ानून 1962 के नाम से जाना जाता है. इस क़ानून के अनुसार, किसी भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई संबंधित देश से अनुरोध कर सकती है. इस अनुरोध के साथ उचित दस्तावेज जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट एवं अन्य सूचनाएं भी देनी होती हैं. इसके अलावा सीबीआई इंटरपोल की भी सहायता ले सकती है, जो किसी भगोड़े अपराधी के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है. इस वक़्त भारत की 26 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि और 10 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है. किसी देश के साथ संधि न होने की सूरत में किसी अपराधी का प्रत्यर्पण करा पाना कितना मुश्किल होता है, इसका उदाहरण अबु सलेम और दाऊद इब्राहिम हैं. सलेम का प्रत्यर्पण पुर्तगाल, जिसके साथ तब भारत की कोई संधि नहीं थी, से हुआ था. तब पुर्तगाल ने सीबीआई के सामने कई सारी शर्तें रखी थीं, जैसे कि सलेम को फांसी नहीं दी जा सकती, इस पर एक से अधिक मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. इतना ही नहीं, प्रत्यर्पण से पहले पुर्तगाल के साथ भारत को एक प्रत्यर्पण व्यवस्था पर हस्ताक्षर भी करना पड़ा था.

प्रत्यर्पण संधि : बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, नेपाल (पुरानी संधि, 1963), नीदरलैंड, रूस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, स्पेन, मंगोलिया, तुर्की, जर्मनी, ट्यूनीशिया, ओमान, फ्रांस, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, बहरीन, बुल्गारिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका और मिस्र.

प्रत्यर्पण व्यवस्था : आस्ट्रेलिया, फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड और पुर्तगाल.

शशि शेखर

ब्रिटिश नागरिक हाना फोस्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी मनिंदर पाल सिंह कोहली को ब्रिटेन में अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और यह इसलिए संभव हो सका, क्योंकि भारत ने कोहली का प्रत्यर्पण बिना किसी हील-हुज्जत के कर दिया था. गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी नदीम, जो सालों से ब्रिटेन में रह रहा है, का प्रत्यर्पण आज तक संभव नहीं हो पाया. नदीम इस तरह का अकेला उदाहरण नहीं है. इस फ़ेहरिश्त में सैकड़ों और ऐसे नाम हैं. मुंबई बम धमाकों के पीड़ितों को आज तक इंसाफ़ नहीं मिल सका है. बोफोर्स की गूंज से आज भी सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच जाता है. भोपाल गैस कांड की भेंट चढ़े लोगों के परिजनों की आंखें अब भी नम हैं. लेकिन दाऊद इब्राहिम, ओटावियो क्वात्रोची एवं वारेन एंडरसन जैसे गुनहगारों को अब तक इंसाफ़ के दरवाजे तक नहीं पहुंचाया जा सका. ये ऐसे चंद नाम हैं, जिन्हें सीबीआई वर्षों से तलाश रही है. ऐसा नहीं है कि सीबीआई को इनके ठिकाने का पता नहीं है या इनके प्रत्यर्पण के लिए वह कोई कोशिश नहीं कर रही है. पिछले कुछ सालों के दौरान सीबीआई ने 11 देशों से 34 भारतीय अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया. इसके अलावा 5 साल में (2003-2007 के दौरान) ऐसे अपराधियों के प्रत्यर्पण प्रयासों पर उसने लगभग 77 लाख रुपये ख़र्च किए. फिर भी नतीजा वही ढाक के तीन पात. ऐसे में यह सवाल उठता है कि आख़िर सीबीआई की उक्त तमाम कोशिशें नाकाम क्यों हो जाती हैं? क्या इस देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है? क्या सचमुच हमारी सरकार इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती? या फिर सीबीआई के सारे प्रयास आधे-अधूरे मन से किए जा रहे हैं या इस देश के क़ानून में ही कोई कमी है? भारत के इन भगोड़ों से संबंधित जो दस्तावेज चौथी दुनिया को मिले हैं, उनसे सीबीआई द्वारा किए जा रहे प्रत्यर्पण प्रयासों, उन पर ख़र्च की जा रही भारी-भरकम राशि और उनके नतीजों के बारे में पता चलता है. इन दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं के विश्लेषण से यह साफ़ हो जाता है कि प्रत्यर्पण के नाम पर आम आदमी की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, जो जनता से टैक्स के तौर पर वसूला जाता है, इन प्रत्यर्पण प्रयासों पर कैसे ख़र्च किया जा रहा है.

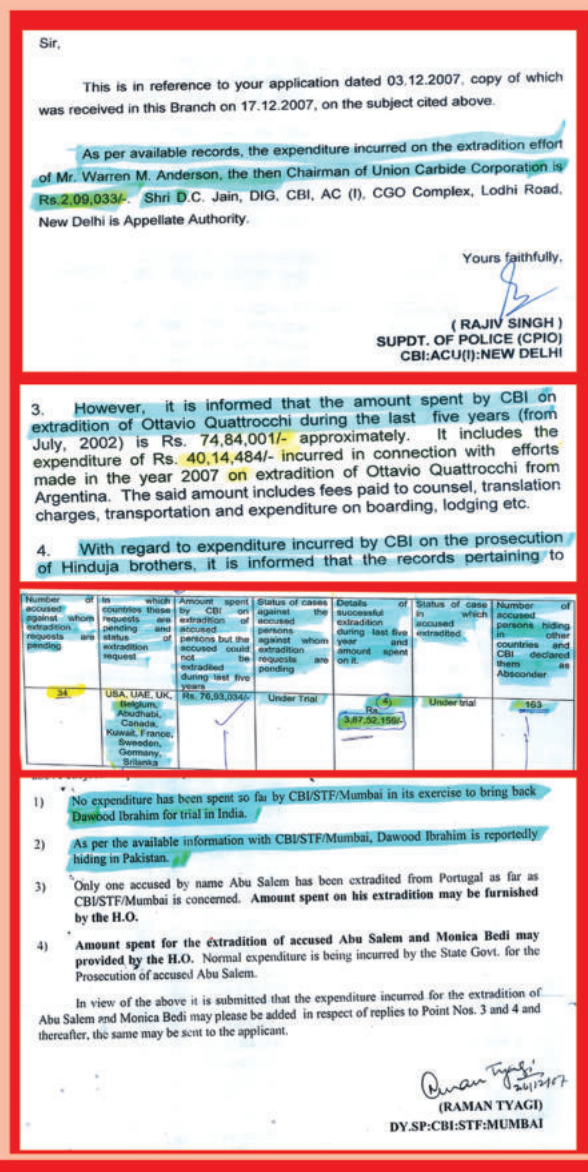

उदाहरण के लिए साल 2003-2007 के दौरान सीबीआई मात्र 4 सफल प्रत्यर्पण करा पाई है, जिनमें प्रमुख नाम अबु सलेम एवं मोनिका बेदी का है. सीबीआई से मिले दस्तावेज के मुताबिक़, इन 4 सफल प्रत्यर्पणों पर लगभग 4 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए गए. वहीं अबु सलेम के वकील अरविंद शुक्ला सीबीआई द्वारा बताए गए इस आंकड़े को अधूरा मानते हैं. शुक्ला कहते हैं कि सलेम के प्रत्यर्पण के संबंध में सीबीआई के बड़े अधिकारियों से मेरी कई बार बात हुई है, जिसमें उन्होंने माना है कि सलेम के प्रत्यर्पण पर 10 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का ख़र्च आया है. ख़ैर सीबीआई की इस शाहख़र्ची और पूरी कवायद का नतीजा क्या निकला. मोनिका बेदी ज़मानत पर रिहा हो चुकी है और सलेम का मामला अदालत में है. नतीजा क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन इतना तय है कि पहले प्रत्यर्पण और अब सज़ा दिलाने के नाम पर आम आदमी की मेहनत की कमाई ऐसे ही उड़ाई जाती रहेगी. प्रत्यर्पण के इस खेल का एक दूसरा पहलू भी है, जो सीबीआई और केंद्र सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े करता है. एक तरफ तो सलेम के प्रत्यर्पण प्रयासों पर करोड़ों रुपये बहा दिए गए, वहीं दूसरी ओर सलेम के ही आका और मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण के लिए आधिकारिक तौर पर अब तक न कोई प्रयास किया गया और न ही एक पैसा ख़र्च किया गया. यह जानकारी ख़ुद मुंबई स्थित सीबीआई/एसटीएफ कार्यालय ने आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में दी है. हालांकि सीबीआई और सरकार दोनों इस तथ्य को स्वीकार करती रही हैं कि दाऊद पाकिस्तान में छुपा हुआ है. एनडीए शासनकाल में भी तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान को वांछितों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें एक नाम दाऊद का भी था. इस मुद्दे पर सीबीआई का बचाव करते हुए पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाल सकते. लेकिन दाऊद के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई और सरकार समय-समय पर अन्य प्रकार से कोशिशें करती रही हैं. अनाधिकृत तौर पर किए जा रहे प्रयासों में भी पैसा ख़र्च होता है, फिर भी सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि दाऊद के प्रत्यर्पण के लिए कितना पैसा बहाया जा चुका है. एक बेहतरीन उदाहरण बोफोर्स कांड का है. सीबीआई के दस्तावेजों के मुताबिक़, इस मामले में मुख्य अभियुक्त ओटावियो क्वात्रोची को भारत लाने के नाम पर साल 2002 से लेकर 2007 के बीच सीबीआई ने 75 लाख रुपये ख़र्च किए. इसके अलावा सीबीआई का यह भी कहना है कि यह मामला कई साल से चल रहा है, इसलिए इतने सालों में ख़र्च की गई रकम का हिसाब उसके पास नहीं है. बहरहाल इन 75 लाख रुपयों में से 40 लाख सिर्फ़ 2007 में अर्जेंटीना में, जब क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई टीम वहां पहुंची थी, ख़र्च किए गए थे. यह रकम वकीलों, दस्तावेजों के अनुवाद और यात्रा आदि मदों में ख़र्च हुई थी. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या हुआ? क्वात्रोची सीबीआई की आंखों के सामने से ग़ायब हो गया और वह हाथ मलती रह गई. तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि सीबीआई द्वारा किए जा रहे सारे के सारे प्रत्यर्पण प्रयास सिर्फ़ दिखावे के लिए किए जाते हैं. या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों में सीबीआई को राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है? क्या सीबीआई सरकार के इशारे पर ही हरकत में आती है? सीबीआई के लिए इन सवालों का जवाब देना उतना ही मुश्किल है, जितना किसी अपराधी का प्रत्यर्पण करा पाना.

shashishekhar@chauthiduniya.com

Sir,

This is in reference to your application dated 03.12.2007, copy of which was received in this Branch on 17.12.2007, on the subject cited above.

As per available records, the expenditure incurred on the extradition effort of Mr. Warren M. Anderson, the then Chairman of Union Carbide Corporation is Rs.2,09,033/-. Shri D.C. Jain, DIG, CBI, AC (I), CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi is Appellate Authority.

Yours faithfully,

(RAJIV SINGH)
SUPDT. OF POLICE (CPIO)
CBI:ACU(I):NEW DELHI

3. However, it is informed that the amount spent by CBI on extradition of Ottavio Quattrocchi during the last five years (from July, 2002) is Rs. 74,84,001/- approximately. It includes the expenditure of Rs. 40,14,484/- incurred in connection with efforts made in the year 2007 on extradition of Ottavio Quattrocchi from Argentina. The said amount includes fees paid to counsel, translation charges, transportation and expenditure on boarding, lodging etc.

4. With regard to expenditure incurred by CBI on the prosecution of Hinduja brothers, it is informed that the records pertaining to

Number of accused against whom extradition requests are pending	In which countries these requests are pending and status of extradition request	Amount spent by CBI on extradition of accused persons but the accused could not be extradited during last five years	Status of cases against the accused persons against whom extradition requests are pending	Details of successful extradition during last five year and amount spent on it.	Status of case in which accused extradited	Number of accused persons hiding in other countries and CBI declared them as Absconder
34	USA, UAE, UK, Belgium, Abudhabi, Canada, Kuwait, France, Sweeden, Germany, Srilanka	Rs. 76,93,034/-	Under Trial	(4) Rs. 3,87,52,159/-	Under trial	163

1) No expenditure has been spent so far by CBI/STF/Mumbai in its exercise to bring back Dawood Ibrahim for trial in India.

2) As per the available information with CBI/STF/Mumbai, Dawood Ibrahim is reportedly hiding in Pakistan.

3) Only one accused by name Abu Salem has been extradited from Portugal as far as CBI/STF/Mumbai is concerned. **Amount spent on his extradition may be furnished by the H.O.**

4) **Amount spent for the extradition of accused Abu Salem and Monica Bedi may provided by the H.O.** Normal expenditure is being incurred by the State Govt. for the Prosecution of accused Abu Salem.

In view of the above it is submitted that the expenditure incurred for the extradition of Abu Salem and Monica Bedi may please be added in respect of replies to Point Nos. 3 and 4 and thereafter, the same may be sent to the applicant.

(RAMAN TYAGI)
DY.SP:CBI:STF:MUMBAI

भोपाल का क़ातिल

दिसंबर 1984 की वह काली रात थी, जब यूनियन कार्बाइड से निकली गैस (मिथाइल आइसोसाइनाइड) ने एक ही रात में हज़ारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया. आज भी भोपाल के लोग उस गैसकांड का दंश झेल रहे हैं, लेकिन इस सबके लिए ज़िम्मेदार वारेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का मालिक आज भी अमेरिका में आज़ाद घूम रहा है. यूनियन कार्बाइड बिक चुका है. भोपाल के लाखों लोग चाहते हैं कि एंडरसन को सज़ा मिले, लेकिन एंडरसन को सज़ा तो दूर की बात, आज तक सीबीआई एंडरसन का प्रत्यर्पण तक नहीं करा सकी. वह भी तब, जब भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है. चौथी दुनिया को मिली सूचना के मुताबिक़, पिछले 25 सालों के दौरान एंडरसन के प्रत्यर्पण प्रयासों पर महज़ 2 लाख 9 हज़ार 33 रुपये ही ख़र्च किए गए हैं. मतलब यह कि सलेम जैसे अपराधी के प्रत्यर्पण पर करोड़ों रुपये और 25 हज़ार लोगों की मौत के ज़िम्मेदार एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए सिर्फ़ 2 लाख रुपये ख़र्च करना आख़िर क्या साबित करता है?

चौथी दुनिया उर्दू के मेहमान

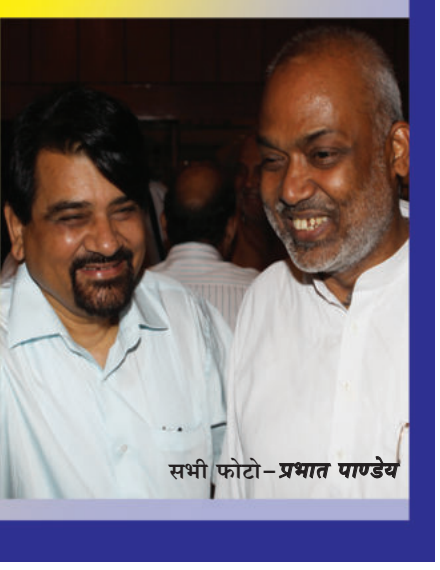

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बच्चों को मिड डे मील के नाम पर ठीक से खाना मुहैया कराने की जगह उसमें भी घपले किए जा रहे हैं.

तरुण गोगोई : सत्ता में लौटने की छटपटाहट

दिनकर कुमार

असम विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने एक साल पहले ही चुनाव प्रचार के ज़रिये माहौल बनाना शुरू कर दिया है. भले ही राज्य की जनता उनके अधूरे वादों को लेकर सवाल पूछ रही है, बावजूद इसके गोगोई नित नए वादे करने में कोई कमी नहीं बरत रहे हैं. बाढ़, भूस्खलन, ग़रीबी एवं बेरोज़गारी जैसी गंभीर समस्याएं अपनी जगह कायम हैं. उग्रवाद की गुत्थी भी सुलझती नहीं दिखाई दे रही है. हाल में गोगोई सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की चौथी साल सालगिरह मनाने के लिए गुवाहाटी में एक समारोह का आयोजन किया, जो पूरी तरह चुनाव प्रचार का मंच बनकर रह गया. मुख्यमंत्री के भाषण से यही संदेश मिला कि असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अब विकास योजनाओं को अधर में ही छोड़ कर चुनावी तोहफ़ों के ज़रिए मतदाताओं को लुभाने में जुट जाएगी. समारोह में दो वक्ताओं ने ख़ास तौर पर संकेत दे दिया कि अब राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है. अब तक मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के धुर विरोधी समझे जाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर कविता ने गोगोई की नेतृत्व क्षमता की दिल खोल कर तारीफ की और कहा कि अगले चुनाव में भी गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस जीत हासिल करके सत्ता तक पहुंचेगी. इसी तरह बोडो नेता हाग्रामा मोतिहारी ने कहा कि असम में विपक्ष बुरी तरह बिखरा हुआ है, इसीलिए आगे भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री तरुण गोगोई होंगे और सरकार में उनकी पार्टी बीपीपीएफ घटक दल के रूप में शामिल होगी. समारोह के माध्यम से गोगोई सरकार ने पिछले नौ साल की अपनी उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया. उधर आम लोग सरकार के दावों से सहमत नहीं हैं. उन्हें लगता है कि गोगोई सरकार भले ही विकास के बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन राज्य की बदहाली लगातार बढ़ती चली गई. असम में हर तरफ पिछड़ापन नज़र आता है. शादिया शहर से लेकर घुबड़ी तक सड़कों की दशा शोचनीय है. ब्रह्मपुत्र से होने वाले भू-कटाव की वजह से डिब्रूगढ़ शहर, माजुली एवं पलाशबाड़ी आदि इलाक़ों का वजूद ख़तरे में है. डिब्रू नदी से होने वाले भू-कटाव के चलते तिनसुकिया ज़िले के रंगागड़ा इलाक़े का वजूद ख़तरे में है. धेमाजी ज़िले में जियादल, गाई एवं ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में बाढ़ की वजह से नागरिकों का जीना दूभर हो गया है. 1998 में बाढ़ के चलते बांध नष्ट होने के बाद लखीमपुर ज़िले के लोग लगातार तबाही का सामना कर रहे हैं. बांध को नए सिरे से बनाने का ढोंग ज़रूर रचा जाता रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के लिए आवंटित होने वाली धनराशि ठेकेदारों, अधिकारियों और मंत्रियों की जेब में चली जाती है, इसलिए आज तक बांध का निर्माण नहीं हो सका.

समारोह के माध्यम से गोगोई सरकार ने पिछले नौ साल की अपनी उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया. उधर आम लोग सरकार के दावों से सहमत नहीं हैं. उन्हें लगता है कि गोगोई सरकार भले ही विकास के बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन राज्य की बदहाली लगातार बढ़ती चली गई.

असम में बेरोज़गारी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है. उग्रवाद के फलने-फूलने के पीछे बेरोज़गारी एक अहम वजह रही है. गोगोई सरकार के नौ साल के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कुछ मुट्ठी भर लोगों को अस्थायी नौकरी देने के सिवा रोज़गार का कोई अवसर मुहैया नहीं कराया गया. शिक्षकों के सैकड़ों पद वर्षों से खाली पड़े हैं, मगर उन पदों पर नियुक्ति ज़रूरी नहीं समझी गई. इसका ख़ामियाज़ा सरकारी पाठशालाओं में पढ़ने वाले कमज़ोर तबके के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है.

बच्चों को मिड डे मील के नाम पर ठीक से खाना मुहैया कराने की जगह उसमें भी घपले किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री गोगोई बीच-बीच में दावा करते रहे हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाएगा, मगर हक़ीक़त यह है कि कर्मचारियों को समय पर पुराना वेतन भी नहीं मिल पाता. गोगोई सरकार के नौ सालों के कार्यकाल में एक भी स्कूल या कॉलेज का सरकारीकरण नहीं किया गया. किसानों को उनकी क़िस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थापना की अनुमति देकर कई जगह किसानों की मुसीबत बढ़ा दी गई. वर्षों पहले राज्य में सिंचाई व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया था. गोगोई शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है. उग्रवाद के मसले को हल करने के नाम पर भी सरकार जनता को छलती रही. अधिक दिन नहीं हुए, जब उत्तर कछार स्वशासी ज़िले में उग्रवादियों और नेताओं के बीच साठगांठ का मामला उजागर हुआ था. विकास मद के एक हज़ार करोड़ रुपये उग्रवादियों, नौकरशाहों और गोगोई मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों ने आपस में बांट लिए. उस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस घपले को उजागर करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी. विपक्ष ने जब हंगामा किया तो मुख्यमंत्री ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई जांच हुई नहीं. स्पष्ट है कि गोगोई सरकार किस तरह उग्रवाद को पालने-पोसने में अपना योगदान करती रही और केंद्र से मिलने वाली राशि जनता के हित में ख़र्च होने के बजाय उग्रवादियों एवं नेताओं की जेबों तक पहुंचती रही. यही वजह है कि दर्जनों उग्रवादी संगठन कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, जो विभिन्न नेताओं के लिए निजी सेना की भूमिका निभा रहे हैं. महंगाई के मामले में भी असम की जनता देश के दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा बोझ वहन कर रही है. बाहर से आने वाले ट्रकों से जगह-जगह अवैध वसूली की जाती है. भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. गोगोई मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने अकूत धन एकत्र कर लिया है. वे अब टीवी चैनल, होटल एवं अन्य उद्योगों में सक्रिय हो गए हैं. कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री गोगोई ने घोषणा की थी कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी संपत्ति का विवरण सरकारी वेबसाइट पर जारी करेंगे, लेकिन आज तक किसी मंत्री ने अपनी संपत्ति का ख़ुलासा करना ज़रूरी नहीं समझा. अब तो मुख्यमंत्री ने ख़ुद साफ़ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी ऐसा क़ानून नहीं है, जो मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ख़ुलासा करने के लिए मजबूर करता हो.

feedback@chauthiduniya.com

जेठमलानी : राजनीति के पारखी या राजनीति पर बोझ?

निर्मल रानी

उत्तर भारत में एक कहावत बहुत प्रचलित है, बेवकूफ लोग कहां पाए जाते हैं, शिकारपुर में. परंतु जब हमें यह पता चला कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ने वाले शिकारपुर में 14 सितंबर 1923 को भारत के नामवर वकील राम जेठमलानी का जन्म हुआ था, तब हमें उक्त कहावत गलत प्रतीत होने लगी, क्योंकि भारत में राम जेठमलानी ने वकालत के माध्यम से अपनी जो पहचान बनाई है, उसके समक्ष देश के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, न्यायविद्, न्यायमूर्ति एवं अफसरशाह आदि सभी कभी न कभी झुकते अथवा समर्पण करते दिखाई देते हैं. हां, यदि जेठमलानी पर कभी कोई तंत्र हावी होता नज़र आया, तो वह मात्र वही तंत्र था, जिसकी उपस्थिति पर युक्ति-उक्ति एवं नीति-अनीति आदि सभी नतमस्तक हो जाते हैं यानी लट्ठतंत्र. आपको याद होगा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने की आवाज़ बुलंद करते हुए राम जेठमलानी चंद्रशेखर के बंगले के सामने धरने पर जा बैठे थे और उस समय चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों के माध्यम से लट्ठतंत्र का सहारा लेते हुए जेठमलानी को अपनी बात समझाने का प्रयास किया था.

इन दिनों यही राम जेठमलानी एक बार फिर सुर्ख़ियों में छाए हुए हैं. इस बार सुर्ख़ियों में उनके छाने का कारण जहां उनसे जुड़ी यह ख़बर है कि वह भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, वहीं उससे बड़ी ख़बर उनके विषय में यह है कि वह पत्रकारों के मुंह से अपने बारे में ऐसा कोई प्रश्न नहीं सुनना चाह रहे हैं, जिसमें उनके राजनैतिक सिद्धांतों, उनकी नीतियों अथवा उनके द्वारा चली जाने वाली दोहरी व दोगली राजनैतिक चालों के विषय में उनसे कुछ पूछा जाए. पिछले दिनों देश के कई जाने-माने टीवी चैनलों ने उनसे साक्षात्कार किया. साक्षात्कार के दौरान जब भी उन्हें पत्रकार ने आईना दिखाने की कोशिश की, वह फौरन भड़क उठे. अपनी 87 वर्ष की उम्र, अपनी क़ाबिलियत एवं वकालत के अपने तुजुर्बे की धौंस दिखाते हुए जेठमलानी ने बार-बार कई पत्रकारों को अपमानित करने की पूरी कोशिश की. एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार को तो उन्होंने उठाकर फेंक देने तक की धमकी दी. उन्होंने प्रत्येक पत्रकार को अज्ञानी व किसी मामले से अनभिज्ञ होने तक की बार-बार बात कही. पत्रकार अपनी सीमाओं को समझते हुए सब कुछ खामोशी से सुनते रहे तथा गंभीर पत्रकारिता का अपना दायित्व निभाते रहे.

प्रश्न यह है कि जेठमलानी की बदसलूकी, झुंझलाहट और तिलमिलाहट हमें उनके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है. क्या 87 वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते वह अपनी सहनशक्ति खो बैठे हैं? जैसा कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के विषय में कहावत के तौर पर कहा जाता है. यदि ऐसा है तो भाजपा को स्वयं यह सोचना चाहिए कि इतने उम्रदराज़ एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होने वाले व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाकर देश की राजनीति पर बोझ लादने का प्रयास आख़िर पार्टी ने क्यों किया?

राम जेठमलानी के व्यक्तित्व को लेकर तमाम विरोधाभासी बातें देश को दिखाई दे रही हैं. लिहाज़ा उनके व्यक्तित्व के विषय में देश को बताना पत्रकारिता का दायित्व है. अपने इसी दायित्व के निर्वहन हेतु जेठमलानी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद मीडिया ने उन्हें साक्षात्कार हेतु कष्ट देना गवारा किया, परंतु जेठमलानी ऐसे प्रश्नों को सुनकर तिलमिला उठते थे, जो उनके राजनैतिक दोगलेपन को उजागर करते थे. उन्हें यह प्रश्न अच्छा नहीं लगता था कि आप तो अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा का चुनाव लड़ने का क्या औचित्य है? दूसरा सवाल जो उन्हें साफ-साफ आईना दिखा रहा था, वह था कि भाजपा तो अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने के लिए उत्सुक रहती है, पर आप तो अफजल गुरु को फांसी देने के विरोधी हैं. ऐसे में उसी भाजपा से राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद अफजल गुरु की फांसी के संबंध में अब आपकी क्या राय है. गुजरात संबंधी कई प्रश्नों पर भी वह ऐसे तिलमिला उठते थे, गोया किसी ने कटे पर नमक छिड़क दिया हो. पत्रकारों के प्रत्येक तीसरे सवाल पर वह अपनी वकालत के अंदाज़ में ही हावी होने की कोशिश करते तथा हर हाल में अपनी ही कही हुई बातों तथा अपने सभी क़दमों को सही ठहराने की कोशिश करते, चाहे इंदिरा गांधी के हत्यारों की वकालत करने की बात हो या अफजल गुरु की फांसी का विरोध, अपने इन क़दमों को वह अपना संवैधानिक अधिकार बताते हैं.

जहां तक राम जेठमलानी की क़ाबिलियत और विधि संबंधी तजुर्बों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से उनके समकक्ष लोग भारत में बहुत ही कम पाए जाएंगे, परंतु इसका यह अर्थ हरगिज़ नहीं लगाया जा सकता कि यदि वह बहुत क़ाबिल या वरिष्ठ हैं तो जनता के समक्ष उनकी कोई जवाबदेही बिल्कुल नहीं है. ख़ासतौर पर ऐसे समय में, जबकि उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया हो. वह पहले भी तीन बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा के सदस्य तथा देश के क़ानून मंत्री भी रह चुके हैं. जेठमलानी एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के अतिरिक्त देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में भी सक्रिय रहने वाले एक व्यक्ति हैं. राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन में संवैधानिक पद इच्छा करने के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का पूरी सहनशीलता से उत्तर देना उनका दायित्व है. मीडिया का भी फर्ज़ है कि वह उनसे या किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछे, जिसे जानने की जनता में उत्सुकता है. परंतु जेठमलानी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रत्येक सवाल का जवाब बदतमीजी एवं दुर्व्यवहार के साथ दिया. साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कभी किसी पत्रकार को कांग्रेस का एजेंट कहा तो कभी किसी को पैसे लेकर काम करने वाला.

प्रश्न यह है कि जेठमलानी की बदसलूकी, झुंझलाहट और तिलमिलाहट हमें उनके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है. क्या 87 वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते वह अपनी सहनशक्ति खो बैठे हैं? जैसा कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के विषय में कहावत के तौर पर कहा जाता है. यदि ऐसा है तो भाजपा को स्वयं यह सोचना चाहिए कि इतने उम्रदराज़ एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होने वाले व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाकर देश की राजनीति पर बोझ लादने का प्रयास आख़िर पार्टी ने क्यों किया? भाजपा को ही यह जवाब भी देना चाहिए कि कहां तो पार्टी अफजल गुरु की फांसी में हो रही देरी को लेकर लगातार कांग्रेस को ऐसे घेरती है, गोया कांग्रेस ही उसे बचाने का प्रयास कर रही हो, परंतु अब तो पार्टी ने स्वयं जेठमलानी जैसे व्यक्ति को राज्यसभा तक पहुंचा

दिया, जो हमेशा अफजल को फांसी देने का विरोध करता रहा. कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व उनकी नीतियों की निंदा कर उन्हें कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करना, कभी गुजरात दंगों की निंदा करना और फिर भाजपा की ही शरण में जाकर राज्यसभा का सदस्य बन जाना, यदि उनकी इस तिकड़मबाज़ी के विस्तार में जाने की कोशिश पत्रकार करे तो उसे भी ज़लील करना. गोया राम जेठमलानी बुढ़ापे की काफी आगे की दहलीज़ में पहुंच चुके ऐसे राजनीतिज्ञ प्रतीत होते हैं, जो अपनी बढ़ती उम्र का शिकार है. उन्हें यह भी भलीभांति मालूम है कि भारतीय अवसरवादी राजनीति में कैसे सक्रिय रहा जा सकता है. इसमें कोई शक नहीं कि उनके अक्खड़पन, जिद्दी स्वभाव और उनके मुंह से जो बात निकल गई, उस पर अड़े रहने की उनकी शैली ने उन्हें यह भी बख़ूबी सिखा दिया है कि यदि भारत में सभी नेता एवं पार्टियां अवसरवादी राजनीति करने से पीछे नहीं हटतीं तो ऐसे में स्वयं अवसरवादी बन जाने में आख़िर हर्ज ही क्या है. खासतौर पर भाजपा जैसी पार्टी में रहकर तो बिल्कुल नहीं. वहां तो पहले भी कभी राम तो कभी दाम की राजनीति की जाती रही है.

feedback@chauthiduniya.com

जहां तक मेरी जानकारी है कि चंद्रशेखर जी के समय में भी हिंदुजा कभी साउथ ब्लॉक नहीं आए थे.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

दिग्विजय सिंह का आख़िरी इंटरव्यू

बांका (बिहार) के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे. वह हमेशा देश के उन जुझारू, कर्मठ एवं ईमानदार नेताओं में शुमार किए जाते रहे, जो आम लोगों के हितों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं. उनके निधन से सिर्फ़ देश और समाज की वह क्षति हुई, जिसकी भरपाई संभव नहीं है. पिछले दिनों उन्होंने चौथी दुनिया के साथ उन्होंने विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. यह उनके जीवन का अंतिम साक्षात्कार था. बतौर श्रद्धांजलि हम उस साक्षात्कार के प्रमुख अंश यहां प्रकाशित कर रहे हैं.

चंद्रशेखर जी की सरकार में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले हुए. उनके दिमाग में अपनी सरकार को लेकर क्या नक्शा था? मतलब, कितना काम वह कर पाए और कौन से प्रमुख काम रह गए?

देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता थी अयोध्या विवाद को सुलझाना और पंजाब में चुनाव कराना. दोनों काम उन्होंने करके दिखाया. आर्थिक रूप से वह दो महत्वपूर्ण काम करना चाहते थे. एक तो नौजवानों को रोज़गार देना, दूसरा वेस्टलैंड यानी खाली ज़मीन को कैसे हरा-भरा किया जाए. दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस छोटे से काल की सरकार में उनके मन में थी, वह था राष्ट्रीय स्वाभिमान. मुझको याद है कि एक बार वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन मैकनमारा हिंदुस्तान आए थे. चंद्रशेखर जी से मिलने. पूंजी, पैसा और अमेरिकी राजनीतिक ताक़त, इन तीनों का इस्तेमाल मैकनमारा अपने शब्दों में कर रहे थे. मैकनमारा की पूरी बात सुनने के बाद चंद्रशेखर जी ने कहा कि हमें जितनी ज़रूरत आपसे है, उतनी आपको हमारी भी है. उन्होंने कहा कि भारत अकेला देश है, जहां से पैसा आपको सही समय पर मिल जाता है. सूद मिल जाता है. अन्य देशों में आपका पैसा डूब जाता है. बाकी फ़ैसला आप स्वयं करें. इसका इतना जबरदस्त दबाव हुआ कि पहली बार आईएमएफ का लोन वित्त मंत्री के गए बिना मिल गया.

सोना गिरवी रखने के मामले में तो उन पर एक बड़ा धब्बा सा भी लगा...

राष्ट्रपति थे उस समय वेंकटरमन जी. उन्होंने कहा कि हमें विदेशी क़र्ज़ के लिए सूद देने का, समय रहते कुछ इंतजाम करना चाहिए. उसी दरम्यान चुनाव भी घोषित हो चुका था. चंद्रशेखर जी का मानना था कि नई सरकार आए, वह फ़ैसला ले, पर वेंकटरमन जी ने कहा कि यह एक चैलेंज है, चूंकि आप पद पर हैं तो इसे स्वीकार करिए. चंद्रशेखर जी ने यह सलाह राष्ट्रपति जी को दी कि और नेताओं से आप इस पर बात कर लें, क्योंकि वे चुनाव में इसे मुद्दा बना देंगे. वेंकटरमन जी ने कहा कि हमने सबको विश्वास में ले लिया है. और कुछ स्मगलिंग का सोना, करीबन 13-14 टन ट्रेजरी के बाहर पड़ा हुआ था. चंद्रशेखर जी ने दिन तय किया कि ठीक है, मैं दस्तखत करता हूं, लेकिन पोस्ट डेट में. 23 मई को आख़िरी पोलिंग होनी थी. उन्होंने 23 मई को पोस्ट डेट में दस्तखत किए. दुर्भाग्य से 21 तारीख को राजीव गांधी की हत्या हो गई और चुनाव टल गया. दिक्कत यह थी कि वेंकटरमन ने अगर कांग्रेस में किसी को विश्वास में लिया होगा तो राजीव गांधी को ही लिया होगा. और वही चले गए. राजीव ने तो किसी को बताया नहीं होगा कि वेंकटरमन से उनकी क्या बात हुई. राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जिनके लिए देश की इज्जत महत्वपूर्ण होती है. हल्ला हुआ, सोना गिरवी, सोना गिरवी. इसका सुखद पहलू था कि चंद्रशेखर जी ने तो 13 टन सोना ही गिरवी रखा, पर जब नरसिम्हाराव जी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री तो उन्होंने 40 टन सोना गिरवी रखा और उसका कोई शोर नहीं. उसमें कहां गई देश की इज्जत?

चंद्रशेखर जी के समय लोगों ने एक अंदाजा यह लगाया कि कुछ पूंजीपतियों से उनके काफी गहरे रिश्ते हो गए थे. मैं कुछ नाम लेता हूं, जिन पर आप कमेंट करें, जैसे हिंदुजा, धीरूभाई अंबानी...

मैंने चंद्रशेखर जी को क़ानून को किनारे करके कोई काम करते हुए कभी नहीं देखा. उनके आलोचक भी आज तक कोई एक उदाहरण नहीं बता पाए या कह सके कि चंद्रशेखर ने चंद्रास्वामी के कहने पर कोई काम किया हो. न ही इसका कोई सबूत मिला कि चंद्रास्वामी के कहने पर उन्होंने कोई काम किया हो. बल्कि उल्टा मैं कहता हूं कि एक बार चंद्रास्वामी विदेश से आ रहे थे. उन पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोई मुकदमा कर दिया था.

बिलकुल गलत. सच पूछिए तो धीरूभाई पर तो उन्होंने गैर जमानती वारंट ही निकाल दिया था. कोई केस-मुकदमा पहले ही चला आ रहा था. उस समय सॉलिसीटर जनरल थे गिरी साहब, वह टर्मीनेंट लॉयर थे. उन्होंने कहा कि इस पर तो मुझसे लीगल ओपीनियन मांगी गई है कि क्या करें. चंद्रशेखर जी ने कहा कि जैसा कानून कहता है, वैसा करो. बाद में वह वारंट नहीं निकल पाया. क्यों नहीं निकला, इस कहानी के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी जानकारी धीरूभाई को हो गई थी और शायद सरकार गिराने में उनकी भूमिका भी हो सकती है.

धीरू भाई की भूमिका थी क्या?

ऐसा उस समय के लोगों का मानना था. ऐसा चंद्रशेखर जी भी मानते थे. कुछ तो पूंजीपतियों का दबाव था. उसमें एक यह दबाव भी हो सकता है. हमसे उन्होंने कई बार यह कहा कि हमें लगता है कि हमारी सरकार गिराने में इन लोगों की भूमिका थी. चंद्रशेखर जी को इसका एहसास होता था.

वीपी सिंह जी के समय हिंदुजा कभी भी साउथ ब्लॉक में नहीं आ पाए, पर चंद्रशेखर जी के समय में सुना मैंने कि अशोक हिंदुजा...

जहां तक मेरी जानकारी है कि चंद्रशेखर जी के समय में भी हिंदुजा कभी साउथ ब्लॉक नहीं आए थे.

बिड़ला एवं गोयनका से कैसा रिश्ता था उनका?

चंद्रशेखर जी संवाद में हमेशा विश्वास करते थे. वह जब पंजाब के आतंकवादियों से बात कर सकते थे तो वह बिड़ला से भी बात करते थे, धीरू भाई अंबानी से भी बात करते थे, हिंदुजा से भी बात करने में कोई परहेज नहीं था, पर मैंने उनके फ़ैसले में कभी उन लोगों का दबाव नहीं देखा.

पर एक इंप्रेशन और है बहुत बड़ा कि चंद्रास्वामी चंद्रशेखर जी के फ़ैसले को प्रभावित करते थे.

मैंने चंद्रशेखर जी को क़ानून को किनारे करके कोई काम करते हुए कभी नहीं देखा. उनके आलोचक भी आज तक कोई एक उदाहरण नहीं बता पाए या कह सके कि चंद्रशेखर ने चंद्रास्वामी के कहने पर कोई काम किया हो. न ही इसका कोई सबूत मिला कि चंद्रास्वामी के कहने पर उन्होंने कोई काम किया हो. बल्कि उल्टा मैं कहता हूं कि एक बार चंद्रास्वामी विदेश से आ रहे थे. उन पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोई मुकदमा कर दिया था. और जब वह आ रहे थे तो लोगों को लगा कि चंद्रशेखर जी के खास आदमी हैं चंद्रास्वामी. इसलिए वह कहेंगे कि उनके आने पर कोई रोक-टोक न लगे, लेकिन सच पूछिए तो उन्हें (चंद्रास्वामी) अग्रिम जमानत लेनी पड़ी.

चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री पद से हटे और चुनाव हार गए. शायद इसके बाद अकेले वह जीते. लेकिन इसके बाद भी जब चंद्रशेखर जी खड़े होते थे, पूरा हाउस खामोश हो जाता था, उनकी बात सुनता था. पर आख़िरी दिनों में वह बड़े निराश थे इस डेमोक्रेटिक सेटअप से.

सच पूछें तो राजीव गांधी के साथ उन्होंने जो संबंध बनाया था सरकार चलाने के लिए और उसमें न्यूनतम साल भर तय हुआ था. लेकिन जिस तरह चार महीने में उनकी सरकार और चार महीने क्यों, पंद्रह दिन, महीने भर में ही राजीव गांधी एक अलग राय रखने लगे. और वह उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे, जो इंदिरा गांधी और चरण सिंह के समय हुआ करता था. चंद्रशेखर जी उससे बहुत आहत हुए. और दूसरा, जिसके लिए वह प्रधानमंत्री बने, उन कामों को नहीं करने दिया गया था. इससे चंद्रशेखर जी आहत थे. और मनमोहन सिंह जी से वह इसलिए आहत थे, क्योंकि मनमोहन सिंह उनकी सरकार के आर्थिक सलाहकार थे. मनमोहन सिंह के चरित्र से प्रभावित होकर ही शायद उन्होंने उन्हें आर्थिक सलाहकार बनाया था, लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, मनमोहन सिंह ने अपनी पॉलिसी ही बदल दी. चंद्रशेखर जी को यह लगा कि एक आदमी अपने जीवन का साठ साल एक तरह से जिया हो और अचानक वह पूरी पलटी खा जाए, यह कैसे संभव है. यह भी उनके लिए चिंता की बात थी.

तो चंद्रशेखर जी किस तरह से देखते थे मनमोहन सिंह के इस परिवर्तन को?

उनकी समझ में नहीं आता था. आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में एक डिबेट हो रही थी. बजट पर ही भाषण हो रहा था तो नरसिम्हाराव ने उठकर कहा कि चंद्रशेखर जी हमने तो आपके ही आदमी को वित्तमंत्री बनाया, यह सोचकर कि यह आपके आर्थिक सलाहकार थे और जो आपकी सोच है, वह उसे यहां भी प्रतिपादित कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी ने उठकर कहा कि यह हमारे आर्थिक सलाहकार थे, वित्तमंत्री थोड़े थे. जिस चाकू से मैं बैंगन काट रहा था, उससे आप दिल की सर्जरी करने लगे. यह तो आपका दोष है, चाकू का दोष थोड़े ही है. हम तो इनसे सलाह ले रहे थे, फ़ैसला करना हमारा काम था, हमारे वित्त मंत्री का काम था. आपने तो उल्टा कर दिया. कभी-कभी मनमोहन सिंह उनके प्रहार से बौखला जाते थे.

चंद्रशेखर जी के दिमाग में शायद कहीं यह था कि एक तरह से मनमोहन सिंह ने डिसऑनेस्टी की है देश से...

उन्हें लगता था कि मनमोहन सिंह ने अपने सिद्धांतों से डिसऑनेस्टी की है. साठ साल तक जिस आर्थिक नीति को चलाया, उसे रिवर्स गेयर में ला दिया. देश का फायदा हुआ, नुक़सान हुआ, अलग बात है. लेकिन उन्हीं के एक आर्थिक सलाहकार जो योजना आयोग के सदस्य थे और बाद में राज्यसभा में लाए गए यानी अर्जुन सेन गुप्ता ने रिपोर्ट दी कि इस देश में 74 करोड़ लोग हैं, जो 20 रुपये से कम पर रोज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. दूसरी ओर दौलत की चकाचौंध भी बीस साल में दिखी है, पर वह दौलत सिमट कर 20 प्रतिशत के पास है. भारत के अंदर भी कई भारत बनते जा रहे हैं. आज तो सिर्फ़ मेरे ही राज्य बिहार की सरकार ने लिखकर भेजा है कि हमारे यहां डेढ़ करोड़ परिवार ऐसे हैं, जो ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. अतः रोटी, चावल, चीनी एवं केरोसिन सरकार मुहैया कराए. डेढ़ करोड़ का मतलब साढ़े सात करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. आठ करोड़ बिहार की आबादी और साढ़े सात करोड़ ग़रीब. चंद्रशेखर जी को दुःख यह लगा कि भाई यह जो एनडीए की सरकार है, वह भी वैसे ही काम कर रही है.

चंद्रशेखर जी ने आपको और आप जैसे दो-तीन लोगों को प्यार दिया, उनको आगे बढ़ाया, कहें तो पैतृक संरक्षण दिया, पर अपने बेटों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया?

वर्ष 2004 में चुनाव हो रहा था. मुझे लगा कि आज मैं उस जगह पर हूं कि उनके एहसान पर अपनी तरफ से कुछ रिटर्न कर सकता हूं, तो मैंने सोचा कि उनके बड़े लड़के पंकज को सीट दे दी जाए. मैंने अटल जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या है, मैं उनके बेटे के प्रचार के लिए जाऊंगा. तब मैं चंद्रशेखर जी के पास गया. चंद्रशेखर जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, परिवार से एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा. पंकज की अपनी हैसियत होती और वह चुनाव लड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह चंद्रशेखर का बेटा है, इसलिए दिग्विजय सिंह टिकट दे रहे हैं तो हमीं को कह दो, हम रिटायर हो जाते हैं. पंकज को चुनाव लड़ना है, लड़ें. हम बलिया छोड़ देते हैं. जिन्हें भी चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़ाया, वे सब लोग अभी तक तो टिके हुए हैं. उनमें से किसी ने भी परिवार के बच्चों को चुनाव नहीं लड़ाया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

खेत-खलिहानों में काम करने या पशुओं को चराने वाले बच्चों के पास अगर पढ़ने लायक समय भी नहीं बचेगा तो जाहिर है कि उनका आने वाला समय अंधकारमय ही रहेगा.

गायब होती वरक कला

चांदी का फ्रॉड वर्क

सुरेंद्र अग्निहोत्री

मिठाई पर चांदी के वरक के नाम पर जहर चढ़ाया जा रहा है. मिठाई खाने वाले को जब बीमारी पूरी तरह जकड़ लेती है, तब उसे पता चलता है कि मिठाई की सौगात रोग लेकर आई है. लखनऊ की नजाकत-नफासत के बीच परंपरा की थाती की याद दिलाते हथौड़ों की धुन चौक की एक तंग गली में गूंजती रहती है. ये हथौड़े विध्वंस के नहीं, बल्कि उन कारीगरों के हैं, जो लजीज मिठाइयों के लिए चमचमाता चांदी का वरक तैयार कर रहे हैं. लखनऊ की यह कला मृतप्राय अवस्था में है. कारीगर नईम कहते हैं, हम अपनी किस्मत को हथौड़ों से पीट रहे हैं.

पुश्तैनी कारोबार के रूप में केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है यह कला. हलीम का कहना है कि पहले यहां आठ-नौ परिवार थे, जिनकी रोजी-रोटी इस काम से चलती थी, लेकिन महंगाई के चलते केवल तीन-चार परिवार ही अब इस काम में लगे हुए हैं. इस काम में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए अब उक्त परिवार भी आने वाली पीढ़ियों को इस काम से दूर ही रहने की सलाह देते हैं. नईम के भाई रफत बताते हैं कि इसके लिए बैंक से कर्ज की कोई सुविधा नहीं है और सरकार की ओर से भी इस संबंध में कोई योजना नहीं है. इस क्षेत्र में व्यवसायियों की अपनी समस्याएं हैं, वहीं कारीगरों की समस्याएं भी कम नहीं हैं. बिलाल 35 वर्षों से यह काम कर रहे हैं. वह बताते हैं कि हमने कई लोगों को यह कला सिखाई, लेकिन इसमें कोई भविष्य न होने के कारण अपने बच्चों को इससे दूर ही रखा. इस काम में कारीगरों को उनके काम के अनुरूप सही मेहनताना नहीं मिल पाता. रफत के साथ काम करने वाले सलीम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं.

सलीम का यह पुश्तैनी काम है, वह पिछले 15 वर्ष से इस काम में लगे हुए हैं. सलीम मुरादाबाद से लखनऊ आए हैं और इसका कारण वहां इस काम की कमी होना बताते हैं. मुरादाबाद के ही शरीफ का कहना है, यहां आपका मेहनताना आपके काम पर निर्भर करता है. पिता कलामुद्दीन की दुकान संभालने वाले सिराजुद्दीन का कहना है कि वह पिछले 40 वर्षों से यह काम कर रहे हैं. यह काम ठेके पर होता है. इससे जुड़े कारीगर जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं. सिराज की दुकान में काम करने वाले शराफत बताते हैं कि दस वर्ष पहले 50 रुपये मजदूरी मिलती थी, लेकिन आज तक मेहनताने में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है. अभी तक मजदूरी 75-100 रुपये तक ही पहुंच सकी है. शराफत दूसरे कामों से संबद्ध मजदूरों को खुद से बेहतर मानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को आरी-जरदोजी के काम में लगाया है. शराफत एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, इस काम में अब पुश्तैनी कारीगर नहीं रहे. बाहर से मजदूर इस काम में आ रहे हैं.

बदलते वक्त ने सब कुछ बदल दिया है. मिलावटखोर भी वरक बनाने के काम में उतर आए हैं. चांदी के वरक में विषैले और आपत्तिजनक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं. यह खुलासा भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने किया है. एल्युमिनियम, निकेल, क्रोमियम, लेड, कैडियम, मैग्नीज जैसी शरीर के लिए घातक धातुओं का प्रयोग इन दिनों चांदी के वरक बनाने में किया जा रहा है. नकली चांदी के वरक से सजी मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री के निरंतर प्रयोग से लोग न्यूरोलॉजिकल, गुर्दा, कैंसर एवं मानसिक रोगों की गिरफ्त में आ रहे हैं. मिलावट रोकने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई मानक निर्धारित नहीं हो सका है. भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने आठ विभिन्न क्षेत्रों से चांदी के वर्क के 180 नमूने लिए, जिनका परीक्षण संस्थान की प्रयोगशाला में किया गया. परीक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 17 नमूनों में चांदी की मात्रा लेशमात्र नहीं थी, जबकि 87 नमूनों में घातक तत्व मिले.

संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मुकुल दास ने बताया कि हमने जब चांदी के नमूनों का परीक्षण किया तो उसमें शरीर के लिए बेहद खतरनाक तत्व मौजूद थे. 55 प्रतिशत चांदी के वरक में निकेल, 54 प्रतिशत वरक में क्रोमियम एवं लेड जैसे विषैले तत्व पाए गए. वरक के नमूनों में 28 प्रतिशत कैडियम, सात प्रतिशत मैग्नीज पाया गया. भारतीय खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम 1951 केवल खाद्य श्रेणी वाले चांदी के वरक की अनुमति देता है, जो 99.9 प्रतिशत शुद्ध हों. इस तरह कानूनन चांदी के शुद्धता मानक पर एक हजार पीपीएम की गुंजाइश है, जिसके चलते चांदी के वरक में सहधातु या विषैले तत्वों की मिलावट को बढ़ावा मिल रहा है. डॉ. मुकुल दास ने बताया कि आम जनता की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के मद्देनजर खाद्ययुक्त चांदी में विषैली धातुओं की मिलावट रोकी जाए. भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से बात की है. अभी इस विषय पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके लिए मानक निर्धारित कर दिए जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

खतरनाक बीमारियों की खान

डॉ. दास कहते हैं कि खाद्य सामग्री के रूप में लेड, क्रोमियम, निकेल, कैडियम एवं मैग्नीज का इस्तेमाल कई खतरनाक बीमारियों की तरफ ले जा सकता है.

लेड: यह बच्चों के लिए सबसे घातक है. इससे बच्चों के मानसिक विकास पर काफी असर पड़ता है. इसके अलावा स्मरण शक्ति पर भी इसका बहुत फर्क पड़ता है. बच्चे पागलपन के शिकार भी हो सकते हैं. चांदी के वरक में इसकी बहुत मात्रा पाई जाती है, जो कैंसर का रोगी बना सकती है.

कैडियम: किडनी पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है. किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं और किडनी के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है.

एल्युमिनियम: खाद्य सामग्री में इस धातु के मिश्रण से न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है. एल्जाइमर्स रोग होने का खतरा रहता है.

असली चांदी के वरक की पहचान कैसे करें

चांदी के वरक को हाथ में रखकर रगड़ने से यदि वह गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि वह उत्तम श्रेणी का है. उत्तम श्रेणी का चांदी का वरक लाभप्रद होता है. चांदी से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, लेकिन यह तभी संभव है, जब हम उत्तम श्रेणी के चांदी के वरक का सेवन करेंगे. भारत में चांदी के वरक का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयों, खीर, हलुआ, सेवई एवं मुगलई पकवान में किया जाता है. इसके अलावा खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर, जैसे चांदी के वरक से लिपटी मीठी सुपारी, छुहारा, सौंफ, इलायची, तंबाकू एवं पान को चांदी के वरक से सजाया जाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, खानपान में इस्तेमाल के लिए देश में प्रति वर्ष दो लाख 75 हजार किलो शुद्ध चांदी को वरक में परिवर्तित कर दिया जाता है. चांदी के वरक को तैयार करने में अखबारी कागज या छपे हुए कागज का प्रयोग खतरनाक है. इसलिए इसे सफेद एवं स्वच्छ पेपरशीट के भीतर रखना चाहिए.

बकरे की खाल में बनता है वरक

चांदी का वरक बनाना लखनऊ के सबसे पुराने कारोबारों में शुमार है. ऐसा माना जाता है कि लगभग 800 वर्ष पहले यह कला लखनऊ आई थी. नवाब वाजिद अली शाह के समय में यह कला अपने चरम पर थी. चांदी के वरक का इस्तेमाल शुरू में आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए किया जाता था और इसका पूरा श्रेय हकीम रुकमाल को जाता है. चांदी के वरक के साथ मुहम्मद हुसैन का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है. हुसैन लखनऊ के पहले कारीगर थे. चांदी के वरक को तैयार करने के लिए चांदी के पतले रोल, जो बनारस से आते हैं, के छोटे टुकड़े काटकर उसे चमड़े से लपेट कर हथौड़े से तब तक पीटा जाता है, जब तक वह अपना सही आकार ग्रहण न कर ले. इस काम में 3-4 घंटे लगते हैं. चांदी का वरक तैयार करने में सबसे अहम भूमिका औजार की होती है. यह किसी पत्थर या लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, बल्कि एक समय यह हिरन की आंत से तैयार किया जाता था, लेकिन बाद में उस पर रोक लग गई और उसकी जगह बकरे की खाल का प्रयोग होने लगा. बकरे की खाल से झिल्ली उतार कर उसे दवाइयों से साफ किया जाता है और फिर उसमें लौंग, इलायची एवं जाफरान जैसे 350 मसालों का घोल डाल कर सुखाया जाता है. इतने मिश्रण से तैयार हुए इस औजार की कीमत 3500 रुपये पड़ती है और यह केवल तीन-चार महीने ही चल पाता है.

खेतों में काम करना बाल मज़दूरी क्यों नहीं?

शिरीष खरे

बाल अधिकारों से जुड़ी लगभग सभी संधियों पर दस्तखत करने के बावजूद भारत बाल मजदूरों का सबसे बड़ा घर क्यों बन चुका है? इसी से जुड़ा यह सवाल भी सोचने लायक है कि बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण कानून, 1986 के बावजूद हर बार जनगणना में बाल मजदूरों की तादाद पहले से कहीं बहुत ज्यादा क्यों निकल आती है? मगर हकीकत इससे कहीं भयानक है. दरअसल बाल मजदूरी में फंसे केवल 15 फीसदी बच्चे ही कानूनी सुरक्षा घेरे में हैं. देश के 1.7 करोड़ बाल मजदूरों में से 70 फीसदी बच्चे खेती के कामों से जुड़े हैं, जो कानून के सुरक्षा घेरे से बाहर ही रहते हैं. इसलिए जब तक खेती से जुड़े कामों को भी बाल मजदूरी मानकर उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक बाल मजदूरी को जड़ सहित उखाड़ फेंकना संभव नहीं हो पाएगा.

आजादी से 39 साल बाद और अबसे 24 साल पहले बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण कानून 1986 के माध्यम से भारतीय बच्चों को खतरनाक कामों से बाहर निकालने के लिए वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई थी. इसके बाद 2006 में इसी कानून में बाल मजदूरी के कई क्षेत्रों और घरेलू कामों को प्रतिबंधित किया गया. कुल मिलाकर तब 16 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं को भी खतरनाक कामों की सूची में शामिल किया गया, मगर इस सूची से खेती से जुड़े कई खतरनाक काम छूट ही गए.

खेत-खलिहानों में काम करने या पशुओं को चराने वाले बच्चों के पास अगर पढ़ने लायक समय भी नहीं बचेगा तो जाहिर है कि उनका आने वाला समय अंधकारमय ही रहेगा. खासतौर से लड़कियों के साथ तो मुसीबतें ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें खेती के कामों के साथ-साथ घर और छोटे बच्चों को भी संभालना पड़ता है. इन बच्चों की हालत भी बाकी क्षेत्रों के बाल मजदूरों जैसी ही है. इसके बावजूद इन्हें बाल मजदूर क्यों नहीं कहा जा सकता है? हालांकि यह एक अजीब स्थिति है, मगर कहीं न कहीं सच भी है कि खेती के क्षेत्र में बाल मजदूरों की भारी संख्या के चलते ही इन्हें बाल मजदूर कहने या मानने से परहेज किया जा रहा है. बाल मजदूरों की इतनी भारी संख्या का दबाव कहीं न कहीं कानून और नीति बनाने वालों पर भी रहता है. यह एक असमंजस से भरा सवाल बना हुआ है कि अगर बच्चों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा?

यह भी एक कड़वा सच है कि परिवार वालों के पास उपयुक्त रोजगार का जरिया और पर्याप्त आमदनी न होने के चलते वे अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं. एक तबके के मुताबिक, इसमें हर्ज भी नहीं है. मगर इसके आगे यह भी गौर करना जरूरी होगा कि अगर बाजारों में हमेशा बच्चों की मांग बनी भी रहती है तो इसलिए कि उनकी मजदूरी बहुत सस्ती होती है. गरीब और बंधुआ परिवार तो बाजारों की मांग के आगे हमेशा झुके रहे हैं. वे अपने बच्चों को दूरस्थ इलाकों में अच्छा पैसा दिलवाने की उम्मीद पर जिन ठेकेदारों के हाथों सौंपते हैं, वे उन्हें शोषण के रास्ते पर धकेल रहे हैं.

कुछ महीने पहले राजस्थान के श्रम विभाग ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को एक पत्र लिखकर सिफारिश की थी कि बाल मजदूरी पर कारगर तरीके से पाबंदी लगाने के लिए श्रम निषेध एवं नियंत्रण कानून में खेती से जुड़े कार्यों को भी जोड़ा जाए. असल में राजस्थान से बहुत सारे बाल मजदूर गुजरात की तरफ पलायन करते हैं. श्रम निषेध एवं नियंत्रण कानून में खेती से जुड़े कार्यों को शामिल न किए जाने से प्रदेश का श्रम विभाग यह मान रहा है कि जहां बाल मजदूरी को बढ़ावा देने वालों को कानूनी आड़ मिल रही है, वहीं वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. बीते साल केवल अगस्त महीने का हाल यह रहा कि उत्तरी गुजरात में कपास की खेती से जुड़े एक दर्जन से भी ज्यादा बाल मजदूर मारे गए. तब इन हादसों के पीछे बीटी कपास में जंतुनाशक दवा के रिएक्शन की आशंका जताई गई थी.

यह भी कहने-सुनने में आता है कि अगर काम खतरनाक नहीं है तो बच्चों से काम कराने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे खेती. हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि खेती से जुड़े काम मुश्किलों से भरे होते ही नहीं हैं. खेतों में भी खतरनाक मशीनों, औजारों, उपकरणों के इस्तेमाल से लेकर भारी-भरकम चीजों को उठाने और लाने-ले जाने के काम होते हैं. खेतों में भी तो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल माहौल में काम करना होता है, जिसमें खतरनाक पदार्थों के मामले, दलाल या मालिकों के काम करने के तरीके, मौसम या तापमान और हिंसा भी शामिल हैं. खेती में भी काम का समय तय नहीं होता. एक बच्चे को खेत में कम से कम दस घंटे तो बिताने ही पड़ते हैं. बुआई और कटाई के मौसम में काम का कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है.

बीड़ जिले की रूपल माने (13) बताती है कि उसे सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खेतों में काम करना पड़ता है. इसी तरह लातूर जिले का सुभाष तौर (14) कहता है कि वह 12-13 घंटे खेतों में रहता है और कई-कई हफ्तों तक ढंग से आराम नहीं कर पाता. यहां तक कि महीनों घर लौटने की इजाजत नहीं मिलती. गौर करने वाला तथ्य यह भी है कि देश भर में 5 से 14 साल तक के 42 फीसदी बच्चे इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं. जब तक इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जाता है, तब तक बच्चों से इसी तरह के काम कराने वालों को खुली छूट मिलती रहेगी.

feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा के उद्देश्यों के बारे में कोई ख़ास संदेह नहीं, संदेह इसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर है.

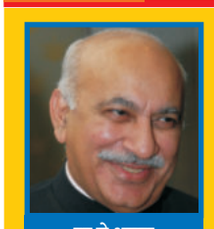

एम जे अकबर

एंडरसन ने भारतीय क़ानून और व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया

भोपाल गैस कांड पर पिछले दिनों अदालत के फ़ैसले के बाद 7 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के मुखिया वारेन एंडरसन को देश से बाहर भेजने का मुद्दा गरमाया, तो सरकार एक विश्वसनीय बहाना तलाश करने लगी. लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए आख़िरकार उसने क़ानून और व्यवस्था के बहाने का सहारा लिया. हम क़ानून और व्यवस्था को व्यवस्था और क़ानून क्यों नहीं कहते? इसकी एकमात्र और स्पष्ट वजह है कि क़ानून व्यवस्था से पहले आता है. क़ानून ही व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है. सभ्य समाज और अव्यवस्था के बीच का अंतर भी क़ानून की मौजूदगी से ही तय होता है. क़ानून का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इतिहास में जातीय समूहों एवं वंश परंपरा के नियमों ने खानाबदोश और बिखरे हुए मानव समाज को संरचनात्मक सह अस्तित्व के दायरे में बांधा. लोकतंत्र के सिद्धांतों ने हमें सामाजिक सह अस्तित्व के शिखर पर पहुंचा दिया, क्योंकि इसने स्वेच्छाचारी फ़ैसलों के बजाय सामूहिक इच्छा को सामाजिक संगठन के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित कर दिया. राजा के नैसर्गिक अधिकारों की अवधारणा अब समाप्त हो चुकी है, इसकी जगह एक चुनी हुई संसद ने ले ली है.

यदि कोई राष्ट्र अपनी ज़मीन पर अपने क़ानून का पालन सुनिश्चित नहीं कर सकता तो उसके लिए व्यवस्था को बचाए रखना भी नामुमकिन है. एंडरसन को सुरक्षित देश के बाहर भेज शासकीय अधिकारियों ने राज्य के मूलभूत दायित्वों से ही मुंह फेर लिया. 1984 के बाद से अब तक पिछले 26 सालों में बहानों और झूठों के सहारे बयान बदलते रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जो न अब तक बदली है और न ही कभी बदलेगी. कोई आश्चर्य नहीं कि एंडरसन ने ऐसी व्यवस्था की खुलेआम खिल्ली उड़ाई, जो उसके सामने घुटनों के बल लेटने को राजी हो गई. उपनिवेशवादी या नव–उपनिवेशवादी संबंधों का सबसे बड़ा आधार अवमानना, उपेक्षा या तिरस्कार ही

होता है. भोपाल के दर्दनाक हादसे की सारी कहानी एंडरसन के उस बयान से ही बयां हो जाती है, जो उसने 7 दिसंबर 1984 को भारत छोड़ते समय दिया था. कुछ वाक्यों में सिमटे अपने इस बयान में एंडरसन ने कहा था, हाउस अरेस्ट हो या न हो, ज़मानत मिले या न मिले, मैं अपने देश जाने के लिए स्वतंत्र हूं...अमेरिका का अपना भी कोई क़ानून है... इंडिया बाइ–बाइ, थैंक्यू.

हाउस अरेस्ट हो या न हो, अमेरिकन कॉरपोरेट जगत के एक स्तंभ को हिरासत में लेने की जुर्रत करने वाले लाठी लिए खाकी वर्दीधारियों की भला क्या बिसात हो सकती है. जमानत मिले या न मिले, लेकिन वॉल स्ट्रीट को अपने इशारे पर नचाने वाले एक शख्स के सामने हमारे देश की अदालत द्वारा दिए गए किसी फ़ैसले, कागज के चंद टुकड़ों की भला क्या औकात हो सकती है. एंडरसन ने तो चुप रहने की सामान्य नैतिकता का भी निर्वाह नहीं किया, उसने इतनी जहमत भी नहीं उठाई. वह तो उन लोगों की खुलेआम खिल्ली उड़ा रहा था, मज़ाक उड़ा रहा था, जो एक औद्योगिक हादसे के जिम्मेदार आरोपी की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. आख़िर यह एक ऐसा हादसा ही तो था, जिसने कुछेक हज़ार ग़रीब भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया था, जबकि कुछेक लाख लोगों को धीरे–धीरे, तिल–तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया था.

अमेरिका का अपना भी एक क़ानून है, एंडरसन के इस बयान से भारतीय व्यवस्था का एक कड़वा सच सामने आ जाता है. वह यह कि यदि आपके संपर्क बड़े लोगों से हैं, तो भारत के क़ानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं. इन संपर्कों के बूते भारतीय क़ानून को मनमाफिक अंदाज में तोड़ा–मरोड़ा जा सकता है. एंडरसन भला भारत के क़ानून की क्यों इज्जत करता. खासकर इसलिए भी कि इस क़ानून की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार लोग ही इसे तोड़ने पर आमादा थे. वह भारतीय क़ानून का तिरस्कार करता रहा, भारतीय शासन व्यवस्था की खिल्ली उड़ाता रहा, लेकिन वही एंडरसन और उसकी यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका में चलने वाली किसी अदालती कार्रवाई की आशंका से ही सिहर उठे. मुकदमे को अमेरिका से भारत स्थानांतरित कराने के लिए यूनियन कार्बाइड ने अपनी पूरी ताक़त लगा दी और भारत से मिले सहयोग के बूते कंपनी ऐसा करने में कामयाब भी रही. इसके बाद तो भारतीय न्यायिक तंत्र के साथ इसके गठजोड़ ने सारी सीमाएं तोड़ दीं.

ब्रिटिश पेट्रोलियम को पता था कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था के पचड़े में पड़ना कितना ख़तरनाक हो सकता है, तभी तो मेक्सिको की खाड़ी में तेल के बिखराव के छह सप्ताह के अंदर ही कंपनी वहां से बाहर निकल गई. पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर बिग ऑयल को 20 बिलियन डॉलर देने के लिए मजबूर कर दिया गया. यह बात सही है कि इस हादसे से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक भी निर्दोष इंसान की जान इसमें नहीं गई थी. सच्चाई तो यह भी है कि बीपी को 75 मिलियन डॉलर से ज्यादा जुर्माना देने की कोई ज़रूरत नहीं थी. 26 साल पहले यूनियन कार्बाइड से पहली बार हर्जाने की मांग की गई थी, तो 15 बिलियन डॉलर की रकम मांगी गई थी. आज की तारीख़ में कंपनी ने क़रीब एक बिलियन डॉलर का हर्जाना अदा किया है, जबकि इस हादसे में 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और एक लाख से ज्यादा लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

मेक्सिको की खाड़ी में हुए हादसे के बाद बराक ओबामा खुद भी थोड़ा फिसल गए. उन्हें लगा कि लोकलुभावन घोषणाओं से वह लोगों को बहलाने में कामयाब हो जाएंगे और दूसरी तरफ बीपी हादसे के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अपनी ओर से क़ोशिश करता रहेगा. एक ओर उनके बयानों की तीव्रता बढ़ती रही (आख़िर इस हादसे को पर्यावरण के लिहाज से 9/11 के समतुल्य माना जा रहा है), तो दूसरी ओर उनके नेशनल गार्ड्स बीपी को बचाने की क़ोशिश में लगे रहे. सुरक्षाकर्मी हादसे से प्रभावित हुए सी–ऑटरों को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए जी–जान से लगे रहे. ओबामा ब्रिटिश पेट्रोलियम के बजाय ब्रिटिश लोगों पर फिकरे कसते रहे. उन्हें शायद यह लगा कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुक़ाबले किसी राष्ट्र को निशाना बनाना ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन ओबामा के इन बयानों से लोगों के गुस्से में कोई कमी नहीं आई.

बीपी हर्जाना भरने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसका विवेक उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे अमेरिका का डर था. यूनियन कार्बाइड को ऐसा कोई डर नहीं था और विवेक तो उसके पास कभी था ही नहीं. मेक्सिको हादसे के बाद बीपी ने घोषणा की है कि वह इस साल अपने शेयरधारकों को बोनस नहीं देगा, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने भोपाल हादसे के ठीक बाद अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया था. इंडिया बाइ–बाइ, थैंक्यू...भारतीय सरज़मीं पर एंडरसन के मुंह से निकले आख़िरी शब्द हैं. बाइ–बाइ का मतलब यहां केवल अलगाव या दूरी बढ़ना ही नहीं है, बल्कि यह तो तलाक़ जैसा है. इस तलाक़ में थोड़े–बहुत गुजारा भत्ते की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जब तक चेक बैंक में न पहुंच जाए, ख़रीदारी न ही करें तो अच्छा है. भोपाल हादसे के इस पचड़े से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता दोषारोपण ही है. आत्म निरीक्षण करना नुक़सानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे पुरानी यादें ताजा होंगी और जख्म एक बार फिर हरे हो जाएंगे. कोई भी धोखा विश्वास की नींव पर ही खड़ा होता है. यूनियन कार्बाइड से ईमानदारी की अपेक्षा तो हमने कभी नहीं की थी. हमें विश्वास था तो अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर, लेकिन निराशा इस बात की है कि यह राजनीतिक व्यवस्था ही हमें धोखा देने के हमेशा नए और अनोखे तरीकों की तलाश करती रहती है.

feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा : भ्रष्टाचार रोकने के उपाय नाकाफ़ी

डॉ. सौमित्र मोहन

मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार और सरकारी धन के अपव्यय को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इस योजना की संरचना में पर्यवेक्षण और निरीक्षण का ख़ास ध्यान रखा गया है. इसके लिए फील्ड में जाकर ज़मीनी हक़ीक़त की जांच–पड़ताल, मस्टररोल का सार्वजनिक निरीक्षण, योजना के अंतर्गत पूरे किए जा चुके एवं चल रहे कामों को सूचनापट्ट पर प्रदर्शित एवं प्रचारित करने और सामाजिक अंकेक्षण पर विशेष ज़ोर दिया गया है. मस्टररोल को सार्वजनिक करने की व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके. लेकिन इसका हर जगह पालन नहीं हो रहा और इससे तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं. काम के लिए की गई मांग और मांग पूरी होने पर घर के सदस्यों के फोटो लगे जॉबकॉर्ड्स की व्यवस्था भी भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर ही की गई है. सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उक्त तमाम भ्रष्टाचार रोधी उपाय शुरुआत में मनरेगा के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा बन गए. स्वर्ण जयंती ग्राम रोज़गार योजना जैसी पहले की रोज़गार योजनाओं के मुक़ाबले मनरेगा में इन उपायों के चलते सरकारी धन में हेरफेर करना मुश्किल था और क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं के लिए यही सबसे बड़ी अरुचि का कारण भी था.

लेकिन मानव स्वभाव हर मुश्किल से बचने का तरीक़ा निकाल ही लेता है. स्वार्थी तत्वों ने मनरेगा में भी भ्रष्टाचार की संभावनाएं तलाश कर लीं और फिर उत्साह के साथ इसके क्रियान्वयन के लिए तैयार होने में भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगा. यदि मीडिया की कुछ ख़बरों पर भरोसा करें तो पर्यवेक्षकों को न केवल बड़ी संख्या में नकली जॉबकार्ड्स के सबूत मिले हैं, बल्कि यह भी पता चला है कि क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाएं और किसी ख़ास क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर दबंग जातीय समूहों ने इन कार्ड्स पर क़ब्ज़ा कर रखा है और इनकी मदद से अवैध रूप से पैसा बनाया जा रहा है. काम कराए बिना ही फ़र्ज़ी मस्टररोल्स बनाने की बात भी सामने आई है. यह तो केवल उदाहरण हैं. भ्रष्टाचारी तत्वों ने पैसे बनाने के ऐसे ही न जाने और कितने तरीके निकाल लिए हैं. फिर नज़रिये की बात भी है. जॉबकार्ड धारकों को काम उपलब्ध कराने को उनके अधिकार के बजाय उपकार के रूप में देखा जाता है. अधिकतर मौकों पर परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जगह का चुनाव भी राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है. मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए ऐसे स्थानों को चुना जाता है, जहां सत्ताधारी दल के समर्थकों की संख्या ज़्यादा हो. सत्ताधारी दल योजना के अंतर्गत काम के अधिकार अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच लॉलीपॉप की तरह बांटता है, लेकिन अन्य दलों के समर्थक बेरोज़गार मज़दूरों को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ता है.

स्वार्थी तत्व फ़र्ज़ी जॉबकार्ड बनाकर मस्टररोल एवं डेली अटेंडेंस रजिस्टर में फ़र्ज़ी एंट्री करते हैं और सरकारी धन पर अपना अवैध क़ब्ज़ा ज़माने में कामयाब होते हैं. अक्सर देखने में आया है कि जॉबकार्ड केवल उन्हीं लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, जो सत्ताधारी दल के समर्थक हैं या फिर अधिकारियों की मुट्ठी गर्म कर सकते हैं. कई इलाकों से सरकारी अधिकारियों द्वारा मज़दूरों की मज़दूरी का एक हिस्सा कमीशन के रूप में काट लेने की ख़बरें भी मिली हैं. योजना के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि मज़दूरों को उनके काम की मात्रा और गुणवत्ता के हिसाब से मज़दूरी मिले, न कि काम के दिनों के आधार पर, लेकिन वास्तव में होता इसका ठीक उल्टा है. अधिकारी खरगोश और कछुए को एक जैसा मानकर मज़दूरों को केवल श्रम दिवस के आधार पर भुगतान कर देते हैं, जबकि यह योजना के प्रावधानों के ख़िलाफ़ है. उद्देश्य यह था कि ज़्यादा काम करने वाले मज़दूर अपने काम के हिसाब से ज़्यादा कमाई कर सकें. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि एक समान मज़दूरी का भुगतान एक व्यवहारिक मजबूरी है, क्योंकि मज़दूरी में अंतर से मज़दूरों के बीच असंतोष पैदा होता है.

कई जगहों से ऐसी शिकायतें भी मिली हैं, जिनमें मज़दूरों ने अधिकारियों के कहे मुताबिक़ काम के घंटों पर आपत्ति जताई है या कुछ दिन काम करने के बाद पहले से तय हुई मज़दूरी पर काम करने से इंकार कर दिया है. ऐसा केवल इसलिए कि मनरेगा एक सरकार प्रायोजित योजना है और मज़दूर कम काम करके अपने हिस्से की निश्चित मज़दूरी लेकर संतुष्ट हो जाते हैं. योजना को क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों ने ऐसी शिकायतें की हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी शिकायतें कम ही सुनने में आई हैं.

मनरेगा के उद्देश्यों के बारे में कोई ख़ास संदेह नहीं, संदेह इसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर है. पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं से सीख लेकर सरकार ने मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए ज़रूर हैं, लेकिन इनका कहां तक पालन हो रहा है, यह संदेह का कारण है. यह भी सच्चाई है कि अब उक्त तरीके नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि स्वार्थी तत्व इनके बीच से पैसे बनाने का रास्ता निकाल चुके हैं.

(लेखक पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति का जंजाल और मुसलमान

मुसलमान ही नहीं, प्रजातंत्र भी ख़तरे में है, शीर्षक से प्रकाशित मनीष कुमार का आलेख तथ्यपरक और जानकारियों से भरा है. कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर राजनीतिक पार्टी मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करती है. मुस्लिम समाज में फैली अशिक्षा, गरीबी और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता. दरअसल, राजनीतिक दलों को यह अंदेशा है कि मुस्लिम कौम एक बार बराबरी की हालत में पहुंच गया तो वह उन्हें मनमाफिक अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. हैरानी की बात तो यह है कि पार्टियां इसके लिए देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करतीं.

–नाजिया हसन, *सासाराम, बिहार.*

काहे का भयमुक्त समाज!

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, यह सभी जानते हैं, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आम लोग अपनी शिकायतों के लिए पुलिस और प्रशासन के बजाय मीडिया के पास पहुंच रहे हैं, यह वास्तव में हैरतअंगेज है. भयमुक्त समाज का दावा करने वाली राज्य सरकार कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग है, यह अब शायद ही किसी से छुपा हो. साथ ही, यह चौथी दुनिया अखबार की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वसनीयता के बारे में भी बताता है. इतने कम समय में चौथी दुनिया ने जितनी प्रगति की है, वह इसकी निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का सबसे बड़ा सबूत है. भरोसे का हलफनामा शीर्षक से छपा आलेख शायद इस राज्य के नौकरशाहों और राजनीतिक आकाओं की आंखों पर बंधी पट्टी हटाने में कामयाब हो.

–प्रतीक पुष्पम, *बदायूं, उत्तर प्रदेश.*

नदी नहीं, ऐतिहासिक विरासत

गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक–सामाजिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है. इसकी अविरल धाराओं में हमारी ऐतिहासिक विरासत छुपी है, लेकिन आज यह जिस हालत में है, उसमें इसे नदी न कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है. हमारी पौराणिक कथाओं में गंगाजल को अमृत का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज इसका पानी पीने क्या, नहाने और कपड़े धोने लायक भी नहीं रह गया. यह हमारे लिए शर्म की बात है. हम यदि अपनी ऐतिहासिक विरासतों को भी संभाल कर नहीं रख सकते तो फिर हम एक सभ्य समाज होने का दावा भी नहीं कर सकते.

–सुमंत बंदोपाध्याय, *हावड़ा, पश्चिम बंगाल.*

गंभीर मामला

भारतीय क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स में न भेजने का बीसीसीआई का फैसला बड़ा गंभीर विषय है. एशियन गेम्स में देश की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है. आदित्य पूजन का आकलन सही है कि भारत अगर इसमें भाग लेता तो एक पदक निश्चित रूप से उसके खाते में होता. लेकिन सच्चाई यही है कि आजकल क्रिकेट केवल पैसों के लिए खेला जाता है. अब यह पैसा चाहे सट्टे से आए या फिर किसी और चोर दरवाजे से, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बीसीसीआई को सिर्फ पैसों से मतलब है. खिलाड़ी भी केवल पैसों के लिए ही खेलते हैं, इसलिए वे भी चुप हैं. देश की गरिमा और प्रतिष्ठा से इनका कुछ लेना–देना नहीं. न्यूजीलैंड का भारत दौरा सिर्फ दो देशों के बीच का खेल है, जबकि एशियन गेम्स एक बड़ा खेल आयोजन है. आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस मामले में हमारी सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए.

–शंकर शर्मा, *चिलमिल, बेगूसराय, बिहार.*

बधाई

सच को उजागर करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती. चौथी दुनिया एक ऐसा मंच है, जो अपनी बात बेबाक लिखता है. पत्रकारिता की कमान अपने हाथ में रखना. साक्षात्कार डॉट कॉम परिवार की तरफ से बधाई.

सुशील गंगवार, *ई–मेल से.*

शुभकामना

चौथी दुनिया दिनोंदिन तरक्की करे, यही हमारी कामना है.

–डीपी मिश्रा, *ई–मेल से.*

अन्नपूर्णा योजना में धांधली

21 जून–27 जून के अंक के मध्य प्रदेश परिशिष्ट में प्रकाशित खबर अन्नपूर्णा योजना का सच सिर्फ एक प्रदेश की खबर नहीं है. यह देश की एक बड़ी समस्या है. लगातार बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में अनाज वैसे भी पूरा नहीं हो पा रहा है, ऊपर से इस तरह की धांधली! अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सभी लोग दाने–दाने के लिए तरस जाएंगे.

–रामेंद्र शुक्ला, *कन्नौज, उत्तर प्रदेश.*

ऑडिट होना ज़रूरी

चौथी दुनिया के 14–20 जून के अंक में संसदीय सत्रों के क्रियाकलापों का ऑडिट होना जरूरी है, लेख पढ़ा. मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि संसदीय सत्रों के अलावा आईपीएल, बीसीसीआई और सभी वित्तीय संस्थानों का कड़ाई से ऑडिट होना और दोषियों को दंडित करते हुए उनकी संपत्ति सील कर देनी चाहिए. भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहे लोगों की नाक में ऑडिट के ज़रिए नकेल कसी जाए तो देश निश्चित तौर पर अर्थ संपन्न हो सकता है.

–डॉ. वासुदेवन शेष, *चेन्नई, तमिलनाडु.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

दिग्विजय सिंह तमाम उम्र याद रहेंगे

संतोष भारतीय

अभी एक महीना भी नहीं बीता. लोधी इस्टेट के पंद्रह नंबर के घर में बैठे हम दिग्विजय सिंह से बात कर रहे थे. हमने देश का पहला इंटरनेट टीवी चौथी दुनिया टीवी शुरू किया है, जिसमें हम भारत के राजनीतिक इतिहास को टीवी पर ला रहे हैं. इंदिरा गांधी के समय के लोग हमारे बीच हैं, जो राजनीतिक घटनाओं के पीछे की कहानी बता सकते हैं. संयोग की बात कि हमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़े लोग आसानी से मिल गए और हमने वहीं से इस सीरीज़ को शुरू कर दिया. दिग्विजय सिंह चंद्रशेखर जी के बेहद करीब थे और उन्होंने कई घटनाओं के केंद्र में रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. संयोग की बात है कि यह इंटरव्यू दिग्विजय के जीवन का आख़िरी इंटरव्यू बन गया. दिग्विजय सिंह भारत के राजनीतिक इतिहास का ख़ुलासा करते-करते ख़ुद भारत के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन गए. इतिहास ने निर्ममता से दिग्विजय सिंह को छीन लिया और उस अध्याय को ही बंद कर दिया, जिसमें अभी महत्वपूर्ण इबारतें लिखी जानी बाकी थीं.

दिग्विजय सिंह उस पीढ़ी के शख्स थे, जो राजनीति में कुछ नया करने के लिए बेचैन रहती है. उनके लगभग हमउम्र राजनीतिज्ञों में नीतीश कुमार, शरद यादव, केसी त्यागी, अरुण जेटली, उमा भारती, वसुंधरा राजे, प्रकाश करात, वृंदा करात, सीताराम येचुरी तथा डीपी त्रिपाठी जैसे लोगों के नाम हैं. इन लोगों की तरह ही दिग्विजय सिंह का सपना था कि देश में आमूल राजनीतिक परिवर्तन आए और इसी कशमकश में उनके मतभेद भी हुए. नीतीश कुमार और शरद यादव के साथ उन्होंने अपनी आख़िरी राजनीतिक पार्टी बनाई और बिहार में सत्ता प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दो साल बीतते-बीतते उनमें मतभेद पैदा हो गया. दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार से अलग भी हो गए. उन्होंने बांका से निर्दलीय उम्मीदवार बन चुनाव लड़ा और लोकसभा में चुन कर आ गए. बांका के लोगों ने उन्हें सारे राजनीतिक लोगों के मुक़ाबले विजयी बना कर भेजा. बिहार में दिग्विजय सिंह ने एक नई राजनीतिक पहल करनी चाही, पर इस सारी लड़ाई में जो ख़ास बात सामने आई कि दिग्विजय सिंह ने कभी नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत हमला नहीं किया, उन्होंने सारा अभियान राजनीतिक तौर पर चलाया. आज तो देखने में आता है कि जैसे ही राजनीतिक रास्ते अलग हुए, व्यक्तिगत हमले शुरू हो जाते हैं. दिग्विजय सिंह राजनीतिक शालीनता, राजनैतिक व्यवहार और राजनीतिक संबंधों की ज़िंदा मिसाल बन कर जिए.

अगर दिग्विजय सिंह नहीं होते तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते. रोमेश भंडारी से दिग्विजय सिंह की अचानक बात होने लगी. रोमेश भंडारी ने दिग्विजय सिंह से चंद्रशेखर जी की वीपी सिंह सरकार के बारे में राय सुन पूछा कि क्या चंद्रशेखर और राजीव गांधी की मुलाकात कराई जा सकती है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्यों नहीं. इस पर रोमेश भंडारी ने दिग्विजय सिंह को अपने साथ कार में लिया और राजीव गांधी के यहां पहुंच गए. उन्होंने दिग्विजय सिंह का परिचय कराया और कहा कि आप चंद्रशेखर जी से मिलने चल सकते हैं क्या, सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है. राजीव गांधी फौरन तैयार हो गए.

राजीव गांधी के पास उस समय मारुति 1000 थी, जो मारुति का नया मॉडल था. राजीव स्वयं ड्राइव करते हुए चंद्रशेखर जी के घर चल दिए. उनके पीछे की सीट पर रोमेश भंडारी और दिग्विजय सिंह बैठे थे. दिग्विजय सिंह बिना सूचना चंद्रशेखर जी के कमरे में राजीव गांधी को लेकर घुस गए. चंद्रशेखर जी का दरबार लगा था, सभी चौंक गए. चंद्रशेखर जी ने सभी को बाहर कर दिया. कमरे में सिर्फ़ चार आदमी रह गए. कोई ख़ास राजनीतिक बात नहीं हुई, पर कोशिश करने की बात तय हो गई और दिग्विजय सिंह को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई. यह चंद्रशेखर जी के

प्रधानमंत्री बनने की ओर पहला क़दम था. दिग्विजय सिंह ने सभी से संपर्क करना शुरू किया.

दिग्विजय सिंह ने मुझे बताया था कि जब वह अजीत सिंह से मिलने गए तो वहां पहले से कुछ लोग बैठे थे. उन्होंने दो घंटे सड़क पर अपनी फिएट में इंतजार किया और इस बीच वह मिताली सिंह की ग़ज़ल, मैं ख़ुशबुओं सी बिखरती रही तुम्हारे लिए हर आईने में संवरती रही तुम्हारे लिए सुनते रहे. उन्हें यह ग़ज़ल इतनी पसंद आई कि जब चंद्रशेखर जी की पचहत्तरवीं सालगिरह उन्होंने अपने घर मनाई तो उन्होंने सबके चले जाने के बाद मिताली से कहा कि क्या वह उन्हें यह ग़ज़ल सुना सकती हैं. मिताली ने भी उन्हें कहा कि उन्हें उनके पास नीचे बैठ कर सुनना पड़ेगा. दिग्विजय सिंह फौरन बैठ गए और मिताली ने उन्हें सामने बैठा कर यही ग़ज़ल सुनाई.

दिग्विजय सिंह चंद्रशेखर जी को अपने पिता जैसा मानते थे. वह जुनून की हद तक चंद्रशेखर जी के समर्थक थे. कुछ भी करने को तैयार रहते थे. चंद्रशेखर जी की पचहत्तरवीं सालगिरह को जिस धूमधाम से दिग्विजय सिंह ने मनाया, वैसा पहले देखने में नहीं आया था. दिग्विजय सिंह का पूरा लॉन मेहमानों से भरा था. अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, वह वहां दो घंटे से ज़्यादा रहे. जार्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव, भैरो सिंह शेखावत, गुजराल साहब, शीला दीक्षित, धूमल, वसुंधरा राजे कौन था, जो वहां नहीं था. भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी सभी दलों की दीवारें ख़त्म हो गई थीं. सभी चंद्रशेखर जी को बधाई दे रहे थे और भूपेंद्र-मिताली से ग़ज़लें सुन रहे थे. सामने पेड़ के नीचे पचहत्तर मोमबत्तियां जल रही थीं. रात बारह बजे पचहत्तर किलो का केक दिग्विजय सिंह लेकर आए. चंद्रशेखर जी ने उसे काटा और दिग्विजय सिंह व भैरो सिंह शेखावत ने गाया, हैप्पी बर्थ डे टू यू.

दिग्विजय सिंह चंद्रशेखर जी की सरकार में वित्त व विदेश राज्यमंत्री रहे. अटल जी की सरकार में रेल राज्यमंत्री और विदेश राज्यमंत्री रहे. उनके पास कार्य कुशलता के अलावा यादों का एक ख़ज़ाना था. क्यूबा के राष्ट्रपति फीडेल कास्त्रो उनके लिए सिगार भेजते थे. इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन उन्हें अपने मित्रों में मानते थे. बेनजीर भुट्टो व नवाज़ शरीफ उनके लगातार संपर्क में रहते थे. एक लंबी सूची है, जो केवल अब सूची ही रह गई है, उनसे संपर्क करने वाला अब नहीं है. दिग्विजय सिंह का घर कभी किसी पार्टी का घर नहीं रहा. उनके मित्रों में सभी दलों के लोग थे. दिग्विजय सिंह दरअसल चंद्रशेखर जी और भैरो सिंह की परिपाटी के नेता थे, जो मित्रता को दल के लेबल से नहीं आंकता. उनके घर हर पार्टी के लोग किसी न किसी आयोजन में अक्सर एक दूसरे से मिल लेते थे. अब उनके न रहने पर बहुत से लोग सालों एक दूसरे से शायद न मिल पाएं और हो सकता है, कुछ तो कभी न मिल पाएं.

दिग्विजय सिंह इतने अच्छे मित्र थे कि कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे उनकी याद में लिखना पड़ सकता है. दिग्विजय सिंह की राजनीतिक यात्रा कितनी लंबी और महत्वपूर्ण होती, इसका अब अनुमान लगाना व्यर्थ है, क्योंकि वह अब हैं ही नहीं, लेकिन अगर भूत में किए गए कामों के आधार पर कहें तो नि:संकोच कह सकते हैं कि वह देश के महत्वपूर्ण पचास लोगों में से एक हमेशा रहते. कुछ लोगों के जाने के बाद उनकी याद कुछ समय तक ज़िंदा रहती है, पर दिग्विजय सिंह के संपर्क में आए लोग उन्हें तब तक याद करते रहेंगे, जब तक वे ख़ुद ज़िंदा रहेंगे.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

दिग्विजय सिंह : बेहतरीन राजनीतिज्ञ-बेहतरीन इंसान

कुरबान अली

दिग्विजय सिंह को सबसे पहले मैंने 1983 के अप्रैल-मई महीने में उस वक़्त देखा था, जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र आंदोलन चल रहा था. वह छात्र नेताओं को लेकर चंद्रशेखर जी और राजनारायण जी के पास आए थे और उनसे छात्र नेताओं की मदद करने का आग्रह किया. दिग्विजय सिंह को दूसरी बार मैंने चंद्रशेखर जी की पदयात्रा के दौरान प्रो. आनंद कुमार, सुधींद्र भदौरिया और डॉ. रजनी कुमारी के साथ देखा. उस समय वह जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे और फुलटाइम राजनीति में आने का मन बना चुके थे. अक्टूबर 1988 में जनता पार्टी का जनता दल में विलय होने और बंगलूर में उसके स्थापना सम्मेलन में वह काफ़ी सक्रिय थे. 1989 में जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई तो वह बांका में जनता दल के उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन चंद्रशेखर जी ने जनता दल संसदीय बोर्ड की बैठक में यह वायदा ज़रूर करवा लिया कि बिहार से राज्यसभा के अगले चुनावों में दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा. इसी आधार पर दिग्विजय सिंह मार्च 1990 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 35 साल की उम्र में सांसद बने.

दिग्विजय सिंह गिद्धौर के एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से संस्कार उन्हें समाजवादी मिले. संतोष भारतीय, हरिवंश और अनुराग चतुर्वेदी द्वारा उन पर लिखी किताब, पड़ाव और मंजिलें में एक लंबे इंटरव्यू में दिग्विजय कहते हैं कि 1964 में बांका से लोकसभा के लिए हुए एक उपचुनाव के दौरान उनका रुझान समाजवादी विचारधारा की ओर हुआ. इस उपचुनाव में मधु लिमए सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय होने के बाद बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और पहली बार इसी उपचुनाव में विजयी होकर वह लोकसभा के सदस्य बने थे. दिग्विजय सिंह की ख्वाहिश थी कि वह बांका से सांसद बनें और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, जिससे मधु लिमए चार बार निर्वाचित हुए थे. उनकी यह ख्वाहिश 1998 में पूरी हुई, जब वह समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए. 1999 में वह दूसरी बार जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते और वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल, उद्योग और वाणिज्य राज्यमंत्री रहते हुए विदेश राज्यमंत्री तक बने. 2004 का लोकसभा चुनाव वह बहुत कम मतों से हार गए थे, लेकिन एक वर्ष बाद ही झारखंड से राज्यसभा के एक उपचुनाव में विजयी होकर सांसद बने.

2009 में वह बांका से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जनता दल (यू) ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया. दिग्विजय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे और अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखते हुए इस चुनाव में विजयी हुए. बिहार की मौजूदा राजनीति, जो केवल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द रह गई है, ऐसे में इन दोनों नेताओं को चुनौती देते हुए दिग्विजय सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत कर इस मिथक को तोड़ा कि केवल लालू और नीतीश के बल पर ही बिहार में राजनीति की जा सकती है. राजनीतिज्ञ होने के अलावा दिग्विजय सिंह एक शानदार इंसान थे. कूटनीति, साहित्य और खेलों में उनकी भारी रुचि थी. दुनिया के बड़े नेताओं से मिलना और उनके साथ आत्मीय रिश्ते बनाना उन्हें बख़ूबी आता था. क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुई अपनी मुलाकातों को वह विस्तार से बताते थे. 1991 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और कुवैत को इराक के क़ब्ज़े से मुक्त कराया, उस समय दिग्विजय सिंह चंद्रशेखर सरकार में विदेश उपमंत्री थे. उस दौरान वह लगभग एक माह तक ईरान की राजधानी तेहरान में रहे. उसी समय स्वर्गीय राजीव गांधी ने ईरान की यात्रा की तो दिग्विजय सिंह के उनके साथ काफ़ी नजदीकी संबंध बने. राजीव गांधी चाहते थे कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक राजीव गांधी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. आगरा शिखर बैठक के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर अगवानी की थी और उनके साथ तीन दिनों तक साये की तरह रहे. एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि परवेज मुशर्रफ आगरा शिखर बैठक के दौरान कश्मीर पर भारत के साथ एक ऐतिहासिक समझौता करना चाहते थे, लेकिन ताजमहल देखने के बाद जब उन्होंने टेलीविजन पर सुषमा स्वराज का बयान देखा तो वह भड़क उठे और नतीजे में आगरा शिखर बैठक विफल हो गई. उपराष्ट्रपति निवास में एक वार्तालाप के दौरान वरिष्ठ पत्रकार एम जे अकबर ने एक बार कहा था कि आगरा शिखर बैठक का पूरा सच दिग्विजय सिंह जानते हैं और उन्हें इस बारे में एक किताब लिखनी चाहिए. दिग्विजय इस बारे में अपना मन बना रहे थे, लेकिन काल के क्रूर हाथों ने अब उन्हें हमसे छीन लिया है और अब वह सच कभी सामने नहीं आ पाएगा, जिसके वह प्रत्यक्षदर्शी थे.

दिग्विजय यारबाश इंसान थे. दोस्तों के साथ गप्प लगाना, संगीत की महफिलें सजाना और बड़ी-बड़ी दावतें करना उनका शौक़ था. 2003 में सूरीनाम में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने भारी रुचि ली थी. वह चाहते थे कि पाकिस्तानी सूफी गायिका आबिदा परवीन इस सम्मेलन में कव्वाली गाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका.

दिग्विजय यारबाश इंसान थे. दोस्तों के साथ गप्प लगाना, संगीत की महफिलें सजाना और बड़ी-बड़ी दावतें करना उनका शौक़ था. 2003 में सूरीनाम में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने भारी रुचि ली थी. वह चाहते थे कि पाकिस्तानी सूफी गायिका आबिदा परवीन इस सम्मेलन में कव्वाली गाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. सूरीनाम से वापसी पर वह लंदन में रुके थे और एक शाम सपरिवार खाने पर मेरे घर पर भी आए. उनके लिए हरिवंश और अनुराग चतुर्वेदी भी उस समय उनके साथ थे. दिग्विजय सिंह की खेलों में भारी रुचि थी. इसी वजह से वह राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने.

जाते-जाते वो मुझे इतनी सज़ाएं दे गया,
उम्र भर दोहराऊंगा इतनी कहानियां दे गया.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

नागलोक के नाम से जाने जाने वाले इस गांव में पहले कई बार सपेरों ने सांप पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई की दूसरी अपील कब करें

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी सूचना की अभिगम्यता प्रदान करने से मना किया गया हो तो आप केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील/ शिकायत दायर कर सकते हैं.

दूसरी अपील कब दर्ज करें

19 (1) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) अथवा धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट समय के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से पीड़ित है, जैसा भी मामला हो, वह उक्त अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर अथवा निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उस अधिकारी के पास एक अपील दर्ज करा सकता है, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का है, जैसा भी मामला हो:

1. बशर्ते उक्त अधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर लेता है. यदि वह इसके प्रति संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से रोकने का पर्याप्त कारण है.

19 (2): जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन किया जाता है, तब संबंधित तीसरा पक्ष आदेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है.

19 (3) उपधारा 1 के तहत निर्णय के विरुद्ध एक दूसरी अपील तिथि के 90 दिनों के अंदर की जाएगी, जब निर्णय किया गया है अथवा इसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:

1. बशर्ते केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इसके प्रति संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण हैं.

19 (4): यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और इसके विरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित एक अपील की जाती है तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.

19 (7): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, मानने के लिए बाध्य होगा.

19 (8): अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित का अधिकार होगा.

(क) लोक प्राधिकरण द्वारा वे क़दम उठाए जाएं, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ पालन को सुनिश्चित करें, जिसमें शामिल हैं

- सूचना तक पहुंच प्रदान करने द्वारा, एक विशेष रूप में, यदि ऐसा अनुरोध किया गया है;
- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो;
- सूचना की कुछ श्रेणियों या किसी विशिष्ट सूचना के प्रकाशन द्वारा;
- अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संदर्भ में प्रथाओं में अनिवार्य बदलावों द्वारा;
- अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान बढ़ाकर;
- धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करना;

(ख) लोक प्राधिकरण द्वारा किसी क्षति या अन्य उठाई गई हानि के लिए शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देना;

(ग) अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों को अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन अस्वीकार करना.

19 (9): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील के अधिकार सहित अपने निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा.

19 (10): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित विधि द्वारा अपील का निर्णय देगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

भारतीय डॉगी सबसे बेहतर

अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं और आप विदेशी नस्ल के कुत्ते को तरजीह देते हैं तो अब उसे तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है. एक सर्वे में इस बात का ख़ुलासा किया गया है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते सबसे बेहतर हैं. इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी राय को बदलें और विदेशी नस्ल के कुत्तों से तौबा करना शुरू कर दें.

पशु कल्याण संगठन पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया (पेटा) ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सबसे लोकप्रिय विदेशी नस्लों के कुतों में कई बीमारियां और विकार होने का ख़तरा रहता है. संगठन के मुताबिक़ आमतौर पर बिकने वाले पग, ग्रेट डेन, बॉक्सर, पॉमेरेनियन को दिल के बड़ा होने, एलर्जी, दांतों की परेशानी सहित कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है.

लेकिन सड़कों पर दिखाई देने वाले भारतीय नस्ल के कुत्तों की प्रतिरोधक क्षमता इन बीमारियों को पास फटकने भी नहीं देती. पेटा की माधुरी देशमुख ने बताया कि कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों से हमारी अपील है कि अगर वे सबसे बढ़िया नस्ल का कुत्ता चुनना चाहते हैं तो आम भारतीय नस्ल के कुत्ते को ही चुनें.

पेटा ने कुछ ही दिन पहले प्राउड टू बी इंडियन के नाम से अपना प्रचार अभियान शुरू किया है, जिसमें फिल्मकार प्रीतिश नंदी भी हिस्सा ले रहे हैं. इस अभियान के ज़रिए लोगों से आवारा कुत्तों को अपनाने की अपील की जा रही है. इन दिनों विदेशी नस्लों के कुत्तों के लिए दुनिया भर में ज़बरदस्त मांग है. दिल्ली में विदेशी नस्ल के कुत्ते काफ़ी लोकप्रिय हैं और पग नस्ल का नाम इनमें सबसे ऊपर है.

पालतू कुत्तों की दुकान चलाने वाले नरेश कोहली कहते हैं कि विदेशी नस्ल के कुत्ते ख़ासे महंगे हैं. जेट ब्लैक पग 18-20 हज़ार रुपये में आता है, जबकि जर्मन शेफर्ड की क़ीमत लगभग 8 हज़ार है. वैसे दुकानदार भी मानते हैं कि विदेशी नस्ल के कुत्ते जल्द बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. कोहली के मुताबिक़ रूस से मंगाए जाने वाले कुत्तों के साथ परेशानी ज़्यादा होती है. सबसे बड़ी दिक्कत मौसम के साथ तालमेल बिठाने में होने वाली परेशानी है.

दिल्ली में पशुओं के डॉक्टर राहुल वर्मा बताते हैं कि भारत में आवारा कुत्ते विदेशी नस्लों के कुत्तों से कहीं मज़बूत और ताक़तवर होते हैं.

सांप और आदमी साथ-साथ रहते हैं

सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे अनायास देखकर लोगों के मुंह से अक्सर चीख निकल जाती है. मगर, एक ऐसा गांव भी है जहां के निवासी इसी सांप के साथ रहते हैं. यह पढ़कर आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन बात सौ फ़ीसदी सच है. आश्चर्य की बात तो यह भी है इस गांव में आज तक एक भी आदमी की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है. इसे आप क्या कहेंगे!

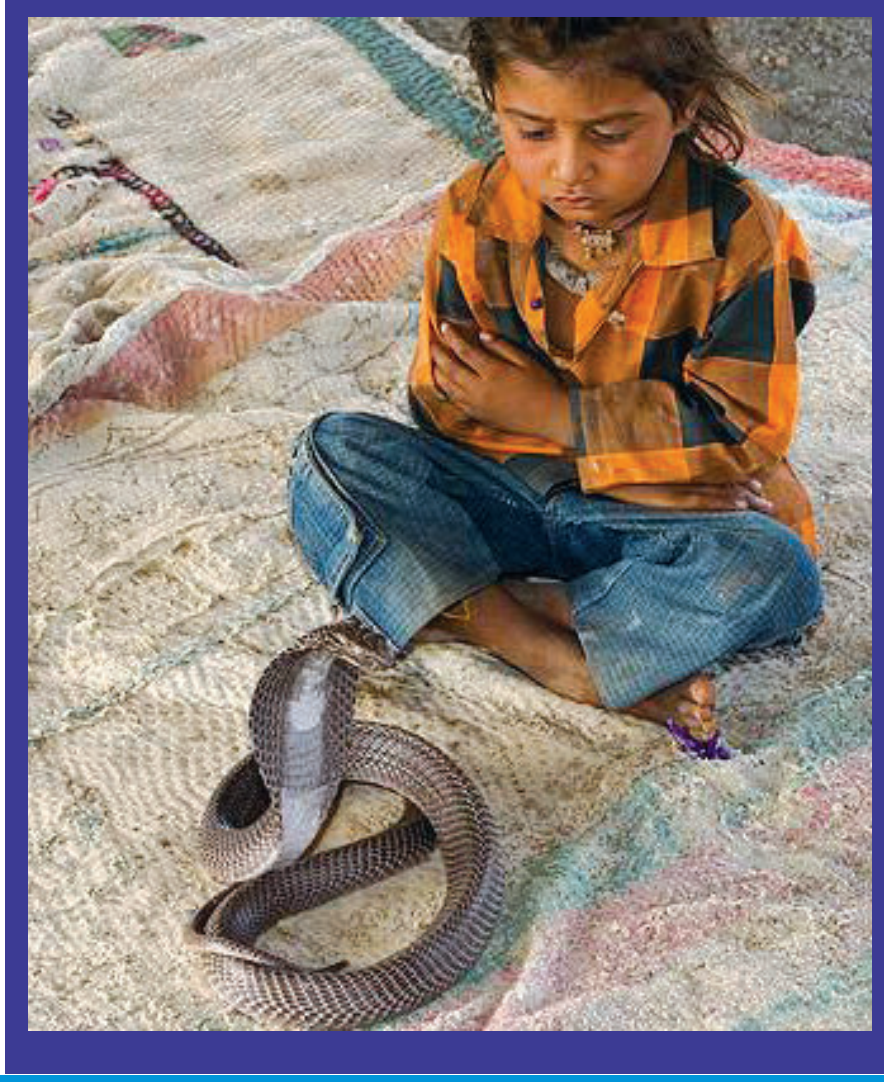

छत्तीसगढ़ में रायगढ़ ज़िला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पुसौर विकासखंड क्षेत्र में स्थित गांव सोडेकेला एक ऐसा नागलोक है, जहां बारिश की बूंदें पड़ते ही गांव के अंदर ही नहीं, बल्कि हर घर में नाग विचरण करने लगता है. ग़ौरतलब है कि ज़िले के इस क्षेत्र में सर्वाधिक नाग व अन्य ज़हरीले सांप पाए जाते हैं. ग्रामीणों के अनुसार यहां कोई भी सांप से नहीं डरता और बच्चे भी उन्हें अपना साथी ही समझते हैं.

ग्रामीणों का मानना है कि इस क्षेत्र पर भगवान शिव की विशेष कृपा है. यही कारण है कि आजकल अन्य क्षेत्रों में जहां नाग के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, वहीं इस क्षेत्र में भारी संख्या में नाग रहते हैं. ग्रामीण इन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं. बारिश की बूंदों के साथ जब ये बाहर निकलते हैं, तो ग्रामीण इनकी पूजा करके इन्हें दूध पिलाते हैं. क्षेत्र केकई ग्रामीण इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं, तो कई दोस्ताना संबंध.

नागलोक के नाम से जाने जाने वाले इस गांव में पहले कई बार सपेरों ने सांप पकड़ने केप्रयास किए, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया. क्षेत्र के लोगों का मानना है कि सपेरे इन सांपों को पकड़कर अपना व्यवसाय करेंगे, जो उन्हें मंजूर नहीं है.

सोडेकेला निवासी लोचन साव का कहना है कि पड़ोसी गांव में भी भारी मात्रा में नाग और अन्य सांप थे, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनको नुकसान पहुंचाने से वहां संख्या कम हो गई. हेमसागर साव व पुनीराम सारथी का कहना है कि ज़िले में इस क्षेत्र में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं. ग्रामीण इसे आस्था का रूप मानते हैं और यही कारण है कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. अन्य ग्रामीणों का भी कहना है कि दुर्लभ प्रजाति केनाग इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिन्हें वे भगवान शिव का रूप मानते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 5 जुलाई -11 जुलाई 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. उपहार-सम्मान मिलने के योग हैं. यात्रा पर जा सकते हैं. अंजान शख़्स के प्रति सावधानी बरतें. परिवारजनों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. खानपान पर विशेष ध्यान रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की दिशा में सफलता के योग हैं. आर्थिक पक्ष और अधिक मज़बूत होगा. निवेश के नए फैसलों के लिए भी समय उत्तम है. सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. यात्रा के प्रबल योग हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय बढ़िया है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. उपहार एवं सम्मान का लाभ मिलेगा. धन, सम्मान, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होगी. रुका हुआ धन वापस मिलेगा और आर्थिक परेशानियां कम होंगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
रुपये-पैसे के लेनदेन में सावधानी बरतें, समस्या आ सकती है. उपहार या सम्मान मिलने का योग है. पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन सुखमय रहेगा. बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, यह परेशानी का कारण बन सकता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
खानपान पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है. यात्रा में विशेष सावधानी बरतें. कार्यक्षेत्र में प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी. रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
यात्रा-देशाटन की दिशा में लाभ मिलेगा. उपहार या सम्मान मिलने की संभावना है. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. पत्नी या माता-पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी. मैत्री संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए लेनदेन में सावधानी अपेक्षित है. शासन-सत्ता से सहयोग मिलेगा. अदालती फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
अधीनस्थ कर्मचारियों एवं उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा. उपहार एवं सम्मान मिलने के योग हैं. किसी अभिन्न मित्र के मिलने से खुशी होगी. रुका हुआ धन वापस मिलेगा. हृदय के मरीज अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
जीविका के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति होगी. मांगलिक दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूरी है. किसी विवाद में न उलझें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
अधीनस्थ कर्मचारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. उपहार-सम्मान के योग बन रहे हैं. सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी. शिक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आर्थिक परेशानियां कम होंगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. आर्थिक मामलों में अपेक्षित सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए वाणी में मधुरता ज़रूरी है. किसी निकट संबंधी से मुलाकात हो सकती है. विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार और घोटालों ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला है, जब इन देशों के मीडिया या नागरिक समाज ने व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की हो.

ज़रदारी का अनैतिक राजनीतिक आचरण

थोड़े दिन पहले की बात है, जब देश के सभी मुख्य अख़बारों ने एक ख़बर को अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा. ख़बर कुछ ऐसी थी, लाहौर उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया और ज़रदारी ने मलिक को माफ़ किया. अख़बारों में इस बात की आलोचना की गई थी कि जिस दिन लाहौर उच्च न्यायालय ने इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक को भगोड़ा घोषित करते हुए उन्हें तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई, उसी दिन देर रात राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी किचन कैबिनेट के सदस्य मलिक को माफ़ी दे दी. ख़बरों का लब्बोलुवाब यही था कि आज के दौर में राजनीति से नैतिकता वैसे ही लगातार ग़ायब होती जा रही है, लेकिन ज़रदारी का यह कदम अनैतिक राजनीतिक आचरण की पराकाष्ठा है.

सिंध हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद मलिक अब सर्वोच्च न्यायालय में जाने की तैयारी में हैं, जहां उनके भविष्य का फ़ैसला होगा. राष्ट्रपति से मिली माफ़ी के बावजूद मलिक क़ानून की नज़रों में अभी भी दोषी हैं. उनके बचाव के लिए कोई रास्ता बचा हो या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि मलिक को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था. मीडिया में पहले भी ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि देश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग–एन (पीएमएल–एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दिया, जिन्हें फ़र्ज़ी डिग्रियां रखने के आरोप में अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था. इसी तरह एक ज़माने में काफी मशहूर हुए एनआरओ की भी अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के रूप में भर्त्सना की जा रही है. आम राय है कि एनआरओ का गठन मुशर्रफ एवं पश्चिमी ताक़तों के बीच एक गठजोड़ का नतीजा था और इसका एकमात्र मक़सद मुशर्रफ की सत्ता को बरकरार रखना तथा पीपीपी की सत्ता में वापसी को सुनिश्चित करना था. बढ़ते भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद एवं राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में अंतर ने देश में राजनीति के स्तर को रसातल में पहुंचा दिया है. दूसरी ओर कई लोगों का यह भी मानना है कि राजनीतिज्ञों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, एक सोची–समझी साज़िश के तहत उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा सके. इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी दुनिया, जिसमें ऐसे राष्ट्र भी शामिल हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था गहरी जड़ें जमा चुकी है, में राजनीति में नैतिकता का सर्वथा अभाव देखा जा रहा है. अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल ने राष्ट्रपति निक्सन को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि मोनिका लेविंस्की प्रकरण के उभरने के बाद बिल क्लिंटन भी महाभियोग से बड़ी मुश्किल से बच पाए थे. जॉर्ज बुश के जमाने में उनके सहयोगियों ने इराक पर अमेरिकी हमले की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अनावश्यक ही सद्दाम हुसैन का हौव्वा खड़ा किया था. ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों पर पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने का आरोप लगा था.

रहमान मलिक

बिल क्लिंटन

मोनिका लेविंस्की

आसिफ अली ज़रदारी

कई अख़बारों और न्यूज चैनलों के मालिक सिल्वियो बर्ल्युस्कोनी के प्रधानमंत्रित्व में इटली के राजनीतिक हालात कई मायनों में पाकिस्तान के हालात से मिलते–जुलते हैं. पिछले अक्टूबर में इटली की सर्वोच्च अदालत ने बर्ल्युस्कोनी द्वारा संसद से पारित कराए गए एक क़ानून को निरस्त कर दिया. इस क़ानून के मुताबिक़, बर्ल्युस्कोनी जब तक पद पर बने रहेंगे, उनके ख़िलाफ़ कोई भी क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी. प्रधानमंत्री का नारी प्रेम जगज़ाहिर है, लेकिन देश में स्वतंत्र मीडिया और तगड़े विपक्ष की मौजूदगी के बावजूद बर्ल्युस्कोनी के स्कैंडल्स उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं. हमारे पड़ोसी राष्ट्र भारत में भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के किस्से काफी आम हैं. कई बार मंत्रियों से लेकर शीर्ष अधिकारियों और उनके निकट सहयोगियों पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और देश की अदालत ने कई बार उन्हें दोषी भी करार दिया है. कई लोगों का तो यह मानना है कि राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के मामले में भारत की हालत पाकिस्तान से भी बदतर है.

भ्रष्टाचार और घोटालों ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला है, जब इन देशों के मीडिया या नागरिक समाज ने व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की हो. इसके बजाय वे व्यवस्था को पूरी तरह बदल देने की मांग करते हैं. निराशा की बात तो यह है कि इससे पाकिस्तान भी अछूता नहीं है. आज देश के क़ानूनविद और संविधान विशेषज्ञ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका की शक्तियों में इज़ाफ़े और मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदल देने की मांग कर रहे हैं. न्यूज चैनलों पर बोलते हुए वे ऐसे बयान देते हैं, जिन्हें हास्यास्पद ही कहा जा सकता है. एक ओर तो वे यह कहते हैं कि मुशर्रफ को देश से बाहर जाने देने के लिए वर्तमान सरकारी तंत्र ज़िम्मेदार है और दूसरी ओर यह मानने से भी गुरेज नहीं करते कि मुशर्रफ का शासन मौजूदा शासन से कहीं ज़्यादा अच्छा था.

यह सही है कि देश की मौजूदा हालत के लिए मुख्य रूप से भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ही ज़िम्मेदार है. सरकार में रहते हुए राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने अपनी ज़िम्मेदारियों का भलीभांति निर्वाह नहीं किया, लेकिन इतिहास पर नज़र डालें तो देश का सैन्य तंत्र हो या न्यायपालिका या फिर नौकरशाही, किसी का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. सत्ता में रहते हुए उक्त संस्थाएं भी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल में नैतिकता के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई हैं. आज हम जिन हालात में जीने को मजबूर हैं, उनके लिए इन्हें पूरी तरह दोषमुक्त नहीं किया जा सकता. देश का शासक वर्ग आपस में इतना बंटा हुआ है कि वह शासन का आदर्श उदाहरण पेश करने में नाकाम रहा है. थोड़े दिन पहले की बात है, जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने माना कि बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते लोगों की दुश्वारियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान में क्रांति जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. मियां शहबाज़ शरीफ की ज़ुबान से निकलते ऐसे बयान यह उम्मीद तो जताते हैं कि वह अपनी और देश की राजनीतिक व्यवस्था की विफलता को समझ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वह राजनीतिज्ञों की इस जमात से अलग हैं.

सरकारी ख़र्चे पर विमान सेवाओं का उपभोग, क़ीमती गाड़ियां, सुरक्षाकर्मियों का लंबा–चौड़ा दस्ता, जिसके लिए पैसा आम जनता की जेब से जाता है और देश–विदेश में महलनुमा घर पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों को बाकी जमात से अलग करता है. बदबूदार गर्मी के दिनों में महंगे सूट पहने उक्त नेता जब ख़र्च में कमी और ऊर्जा की बचत के लिए लंबे–चौड़े बयान देते हैं तो यह हास्यास्पद के अलावा और कुछ नहीं लगता. आर्थिक विकास की दर तेज दिखाने के लिए वित्त मंत्रालय ने पिछले दो सालों के लिए विकास की अनुमानित दर कम कर दी है. नए आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में विकास की अनुमानित दर को थोड़ा–बहुत कम कर देना विश्वसनीय हो सकता है, लेकिन इसे चालीस प्रतिशत कम करना किसी घोटाले का संकेत है. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हमारे आर्थिक प्रबंधकों के नैतिक दिवालिएपन की कहानी बयां करता है, लेकिन सवाल यह भी है कि हम आख़िर किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

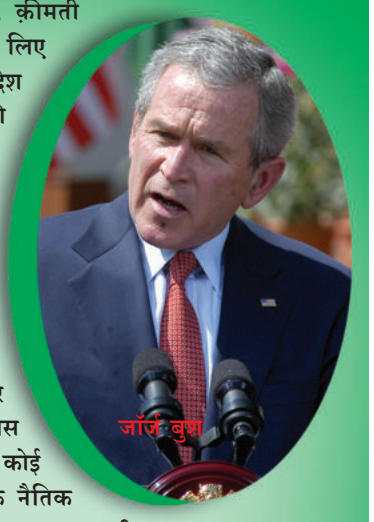

जॉर्ज बुश

नवाज़ शरीफ़

पाकिस्तान को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हमारे आंकड़ों पर वैसे ही कम भरोसा करती हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमी विदाउट डेवलपमेंट नामक वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सत्ता तंत्र पर ऐसे अभिजात्य वर्ग का क़ब्ज़ा है, जो मानव संसाधन के विकास को कोई महत्व नहीं देता. इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि पिछले दो दशकों में आर्थिक विकास की दर ठीकठाक रही है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक विकास के मानकों, जिनमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा, भ्रष्टाचार का स्तर, राजनीतिक स्थिरता आदि शामिल हैं, पर इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है.

रिपोर्ट का एक रोचक पहलू यह है कि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय के मौजूदा स्तर पर दूसरे देशों के मुक़ाबले पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों पर 3.3 प्रतिशत ज़्यादा ख़र्च कर रहा है. यह वही रकम है, जिसे पाकिस्तान को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए ख़र्च करना चाहिए था और जिसकी कमी महसूस की जा रही है. यह स्पष्ट है कि देश का राजनीतिक तंत्र आम लोगों की ज़रूरतों से पूरी तरह नावाक़िफ़ है. दूसरे देशों के राजनीतिज्ञ भी झूठ बोलने और लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन एक बार उनकी कारगुज़ारियां सामने आ गईं तो उनके लिए बचना मुश्किल होता है. पाकिस्तान की हालत इससे ज़रा अलग है. हमारे नेताओं की कथनी और करनी में इतना फ़र्क़ है कि वास्तविकताओं से उनका कोई वास्ता ही नहीं रह जाता. क़ानून का शासन कहीं नज़र नहीं आता और आर्थिक प्रगति की कमज़ोर गति के चलते आम जनता का व्यवस्था से कोई वास्ता ही नहीं रह गया है. देश में लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो इसके लिए राजनीतिज्ञों के अलावा मीडिया और न्याय पालिका को ज़िम्मेदारी लेनी होगी. कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो कार्यपालिका और न्याय पालिका के बीच टकराव को बढ़ावा देना चाहते हैं. सच्चाई यह है कि उक्त दोनों ही संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रहने के लिए अपरिहार्य हैं और यह ज़रूरी है कि दोनों एक–दूसरे की अहमियत समझें तथा किसी के अधिकार क्षेत्रों के अतिक्रमण से बचें. अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए यदि उन्होंने व्यवस्था को पूरी तरह बदल देने का इरादा किया तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा.

आरिफ निजामी

(लेखक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

e देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301

नाटक की ही तरह यह किरदार भी तो सिर्फ़ कुछ देर के लिए खेले जाते हैं. मेरी अपनी असली पहचान तो कुछ और है.

जीवन एक नाटक

आज साई की नश्वर देह भले न हो, लेकिन प्यार बांटने का उनका संदेश असंख्य भक्तों की शिराओं में अब तक दौड़ रहा है.

जीवन के इस नाटक में एक शक्ति मेरे पास और भी है. नाटक में किरदार करते वक़्त कलाकार को तो लिखी स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास यह छूट है कि अपनी स्क्रिप्ट ख़ुद ही लिखूं और जब चाहूं उसे बदल दूं. तभी तो मैंने कहा कि जीवन के इस ड्रामे में हर किरदार निभाते हुए मैं अपनी इस स्क्रिप्ट को बदल सकता हूं. आज अगर पति बन किसी सीन में स्थिति ऐसी है कि मुझे पत्नी पर गुस्सा करना है तो मैं ड्रामा का सीन बदल सकता हूं और गुस्सा न कर मैं उन्हें फूल दे देता हूं.

कभी आपने सोचा है कि आप फिल्में या नाटक देखना इतना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि नाटक एक ऐसा माध्यम है कि जो हमें अनंत के लिए खोल देता है, हमें उमुक्तता देता है, स्वतंत्रता देता है. हम जीवन से भी बड़े एक ऐसे कल्पना लोक में चले जाते हैं जो हमें जीवंतता देता है.

आज हर आध्यात्मिक गुरु हमें समझाता है कि हम अपने अंर्तमन को पहचानें. अपनी सही पहचान करें. मैं कौन हूं, इसका सही अर्थ जानें. लाख कोशिश के बाद भी हम नहीं जान पाते लेकिन शायद फिल्मों और थियेटर को सही रूप में देखें तो पहचानना आसान होता है कि मैं कौन हूं. जी, कहां आध्यात्म और कहां चकाचौंध और ग्लैमर भरी फिल्में. दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं, पर क्यों किसने कहा कि आध्यात्म नीरस, बेरंग, फीका है और माया रंगीन, रसवती और चटकीली है. चलिए थियेटर को लें. जब भी कोई कलाकार थियेटर के लिए या किरदार करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, उससे पहले वह अपने असली नाम, उम्र, व्यवसाय, पोजिशन यहां तक कि अपने शरीर की भी सारी पहचानों को या लबादों को उतारता है. फिर उस किरदार को समझ उसका नाम, उम्र, व्यवसाय लिबास और कई बार तो उस किरदार के लिए अपने शरीर की बनावट में भी परिवर्तन करता है नहीं तो मेकअप का सहारा लेता है और उसी पहचान को जब तक जीता है नाटक चल रहा है तब तक ओढ़े रखता है, और जितना अच्छा कलाकार उतनी ही गहराई से वह उस किरदार में डूब जाता है.

लेकिन हर बार उसको यह ज़रूर याद रहता है कि उसकी अपनी पहचान क्या है. वह किरदार पर किदार निभाता जाता है कि लेकिन याद रहता है कि वह है कौन? ऐसा ही कुछ हमारे जीवन के साथ भी है. लेकिन थोड़ा विपरीत चलते हैं. यहां हमें पहले उन किरदारों की पहचान हो जाती है जो हम जीवन के रंग मंच पर अदा कर रहें हैं. ग़लती यह हो गई कि हमने इन रोल्स को, इन किरदारों को अपनी सही पहचान समझ लिया है. मैं घर पर हूं तो पिता हूं, पति हूं, बेटा हूं, दामाद हूं, चाचा हूं, मकान मालिक हूं, इन सभी किरदारों के लिए अलग-अलग व्यक्तित्व हैं मेरे ही. पिता हूं तो प्यार भी करता हूं, लेकिन अनुशासन भी रखता हूं. पति हूं तो रोमांस भी करता हूं, ध्यान भी रखता हूं, इसी तरह हर किरदार को मैं बख़ूबी निभाता हूं. उसी तरह बाहर निकलकर किसी का बॉस, किसी का कर्मचारी हूं. दोस्तों का दोस्त हूं. देश का वासी हूं. सब के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाता हूं और हर किरदार को बख़ूबी निभाने का प्रयास करता हूं. ग़लती यही हुई कि जीवन के रंगमंच पर खेले जाने वाले इन सभी किरदारों को ही मैंने सच मान लिया, जबकि नाटक की ही तरह यह किरदार भी तो सिर्फ़ कुछ देर के लिए खेले जाते हैं. मेरी अपनी असली पहचान तो कुछ और है. मैं इस शरीर का मालिक, इस प्रकृति का मालिक, अपना स्वयं का भाग्यविधाता चैतन्य शक्ति हूं. मैं तो हमेशा रहूंगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता. मेरा रोल तो सदा ही चलता रहेगा, ये जो बाकी किरदार हैं, कुछ देर के लिए हैं. जीवन के इस नाटक में एक शक्ति मेरे पास और भी है. नाटक में किरदार करते वक़्त कलाकार को तो लिखी स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ता है. लेकिन मेरे पास यह छूट है कि अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिखूं और जब चाहूं उसे बदल दूं. तभी तो मैंने कहा कि जीवन के इस ड्रामें में हर किरदार निभाते हुए मैं अपनी इस स्क्रिप्ट को बदल सकता हूं. आज अगर पति बन किसी सीन में स्थिति ऐसी है कि मुझे पत्नी पर गुस्सा करना है तो मैं ड्रामा का सीन बदल सकता हूं और गुस्सा न कर मैं उन्हें फूल दे देता हूं. सोचें कि सीन किस तरह बदल जाएगा. उसी तरह ऑफिस में बॉस हूं. स्थिति गंभीर हो गई, प्रोजेक्ट की डेडलाइन सामने है लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है. ऑफिस में सब लोग घबराए हुए हैं, सोच रहें हैं कि अब सबको बहुत डांट पड़ेगी, चीख चिल्लाहट होगी, नौकरी भी जा सकती है. एक बार फिर स्क्रिप्ट बदल दो, सब को बुलाकर समझाओ, एमरजेंसी है, सलाह लो, शांत रह कर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता तलाशो. सब लोग एक्सट्रा टाईम लगाने के लिए तैयार होंगे. बिना चीख चिल्लाहट के परिस्थिती निकल जाएगी, सीन बदल जाएगा.

तो जीवन के इन नाटक में अलग-अलग किरदारों को निभाने पर संपूर्ण शक्ति और जज़्बे के साथ कि मैं इन किरदारों को निभाने वाला चैतन्य शाक्तिशाली जीव हूं. मैं हर परिस्थिति को बदल सकता हूं क्योंकि मैं सीख रहा हूं कि स्क्रिप्ट कैसे बदलेगी. साई भक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए कृपया 09999313918 पर एसएमएस करें. ॐ साई राम.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

सिखों के साथ हज़ारों हिंदू श्रद्धालु भी हेमकुंड साहिब में आस्था रखते हैं. हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है.

बिखरा तहलका का पठन-पाठन

अनंत विजय

तरुण तेजपाल देश के ख्यातिप्राप्त पत्रकार हैं. तहलका के बैनर से स्टिंग ऑपरेशन कर काफ़ी शोहरत कमा चुके हैं. अब दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में तहलका पत्रिका निकालते हैं. अंग्रेजी तहलका ने तो कई वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन हिंदी तहलका पत्रिकाओं की भीड़ के बीच अपना स्थान और पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है. कुछ अलग करने की चाहत में तहलका ने हिंदी साहित्य का रुख किया और जून में पठन-पाठन के नाम पर साहित्य विशेषांक निकाला. आमतौर पर जैसा इस तरह की पत्रिकाओं के साथ होता है, तहलका का साहित्य विशेषांक भी उसका शिकार हो गया है. साहित्य विशेषांक के नाम पर निकली इस पत्रिका का कोई साहित्यिक स्वरूप ही नहीं बन पाया है. सब कुछ समेट लेने की चाहत और नामचीन लोगों को बेवजह स्थान देने से पत्रिका का पूरा स्वरूप बिखर गया. अपने संपादकीय में पत्रिका के वरिष्ठ संपादक संजय दुबे ने लिखा है, समाचार पत्रिका के साहित्य विशेषांक के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं. इस अंक में न केवल दस्तावेज और अन्यान्य जैसी बहुपयोगी श्रेणियां मौजूद हैं, बल्कि इसे लोकतांत्रिक और सर्वसमावेशी बनाने की ओर भी विशेष ध्यान रखा गया है. इसमें अनुभवी दिग्गजों को समुचित सम्मान देते हुए साहित्यिक संभावनाओं के नए संकेतों का भी उतनी ही गर्मज़ोशी से स्वागत किया गया है. वरिष्ठ संपादक का यह दावा है तो ठीक, लेकिन इस अंक में कविता और कवियों को लेकर एक उपेक्षा भाव साफ़ तौर पर दिखता है. एक तरफ जहां कहानीकारों और लेखकों को प्रमुखता के साथ छापा गया है, वहीं कवियों और कविताओं को रनिंग मैटर की तरह एक के बाद एक छापकर रस्म अदायगी की गई है. न तो किसी का कोई परिचय दिया गया है और न ही किसी के फोटो छापे गए हैं. या तो पत्रिका के कर्ता-धर्ता यह समझते हैं कि उन्होंने जितने कवियों को छापा है, वे इतने प्रसिद्ध हैं और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. नाम ही काफ़ी है की अगर सोच है तो नाम तो सही छपना चाहिए था. वरिष्ठ कवि विमल कुमार बेचारे विपल कुमार हो गए, शुक्र है कि विफल कुमार नहीं हुए. कई अच्छी कविताएं छपी हैं, लेकिन खराब डिस्पले की वजह से वे उभर नहीं पाईं. चर्चित कवि संजय कुंदन की छोटी कविता, ठीक है आज की नई पीढ़ी की मानसिकता और उसकी सोच को प्रतिबिंबित करती है. गीत चतुर्वेदी की लंबी कविता, जाना सुनो मेरा जाना भी इस अंक की उपलब्धि है. गीत की कविता में एक गहराई होती है, जिसे पढ़कर महसूस किया जा सकता है.

> साहित्य विशेषांक के नाम पर निकली इस पत्रिका का कोई साहित्यिक स्वरूप ही नहीं बन पाया है. सब कुछ समेट लेने की चाहत और नामचीन लोगों को बेवजह स्थान देने से पत्रिका का पूरा स्वरूप बिखर गया. अपने संपादकीय में पत्रिका के वरिष्ठ संपादक संजय दुबे ने लिखा है, समाचार पत्रिका के साहित्य विशेषांक के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं.

आज हिंदी साहित्य में नई पीढ़ी के कहानीकारों की रवींद्र कालिया ने एक फ़ौज खड़ी कर दी है. जैसा कि आमतौर पर होता है कि अगर आप फ़ौज बनाते हैं तो उसमें कई जांबाज़ों के साथ-साथ कुछ सुस्त भी भर्ती हो जाते हैं. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो जंग से बचकर शॉर्टकट से निकल भागने के चक्कर में लगे रहते हैं. हिंदी कहानी की इस नई पीढ़ी में भी तीनों तरह के लोग हैं. कई नए कहानीकार बेहतरीन लिख रहे हैं और उन्होंने हिंदी को एक नई भाषा दी है. क्या कहानी लेखन में नई पीढ़ी को लेकर मच रहा शोर रचनात्मकता है इसे केंद्र में रखकर इस अंक में समकालीन कहानी-कितना ज़ोर कितना शोर शीर्षक से एक लेख छपा है. इसके लेखक दिनेश कुमार ने वरिष्ठ कहानीकारों की राय के आधार पर लेख लिखा है. काशीनाथ सिंह कहते हैं कि युवा लेखक विज्ञापन की ऐसी विधियां जान गए हैं, जिनसे पुराने लेखक अपरिचित थे. वे लोग लेखन पर कम ध्यान देकर विज्ञापन की आधुनिक सुविधाओं का लाभ अधिक उठा रहे हैं. काशीनाथ जी की इस बात में दम है, लेकिन ऐसा पूरी पीढ़ी पर लागू नहीं होता. दिल्ली में कई ऐसे लेखक हैं, जो संपादकों के दरबार में हाजिरी लगाकर साहित्य में अपने आपको स्थापित करने में लगे हैं. उनमें से कई कहानीकारों की कहानियां इस अंक में छपी भी हैं. ज्ञानरंजन भी नई पीढ़ी को बाज़ार की मांग के अनुरूप लिखने वाला करार दे रहे हैं. युवा कहानी में एक नई भाषा और कंटेंट सामने आ रहा है, जिसे ये लोग बाज़ार की देन मानते हैं. मेरा इन वरिष्ठ लेखकों से यही सवाल है कि हिंदी

साहित्य का बाज़ार कितना बड़ा है? कितने लेखकों को हिंदी साहित्य के बाज़ार से फ़ायदा पहुंच रहा है? आज तो हिंदी में यह हालत है कि वरिष्ठ से वरिष्ठ लेखकों की कृतियां एक हज़ार से ज़्यादा नहीं बिक पाती हैं. उधर अंग्रेजी में अद्वैत काला जैसी नई एवं युवा लेखिका का उपन्यास पचास हज़ार प्रतियों से ज़्यादा बिकता है. किस भ्रम और किस मानसिकता में जी रहे हैं हमारे बुजुर्ग साहित्यकार. इस अंक में वंदना राग की कहानी देवा-देवा अच्छी है. दूसरी तरफ उमाशंकर चौधरी की कहानी बेवजह खिंची हुई लगती है. नतीजा यह हुआ कि न केवल कहानी बिखर गई, बल्कि उबाऊ भी हो गई.

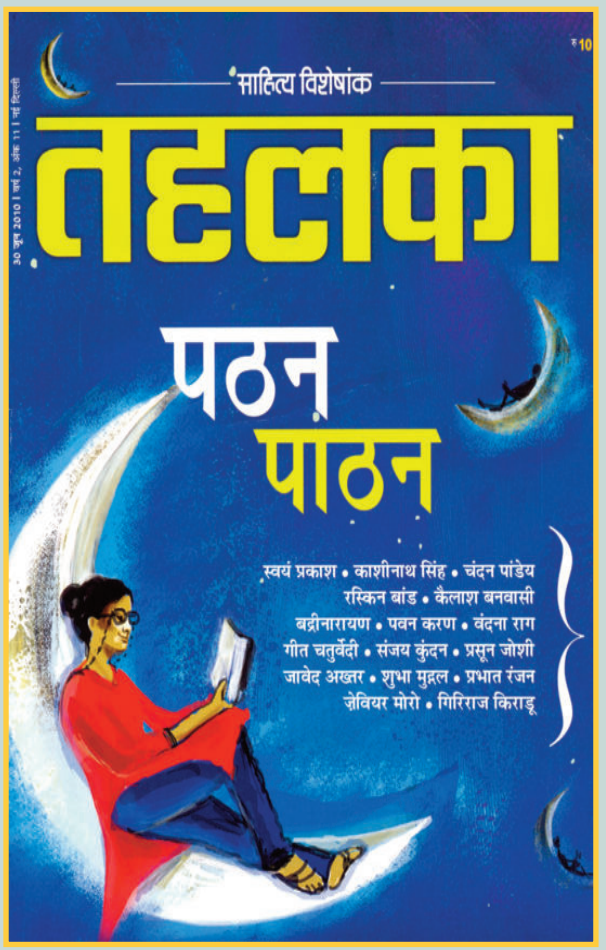

संजय दुबे ने अपने लेख में अपने सहयोगी गौरव सोलंकी को विलक्षण लेखन प्रतिभा बताया है, लेकिन इस अंक में छपी कहानी और कविता में विलक्षणता दिखाई तो नहीं देती.

अपने संपादकीयनुमा लेख में संजय दुबे ने एक और दावा किया है, शायद हिंदी के किसी भी साहित्य विशेषांक के लिए यह पहला प्रयास होगा कि इस अंक में हमने विभिन्न प्रकाशकों, साहित्यकारों एवं समालोचकों आदि से अनुरोध करके, उनसे बात करके तमाम तरह की सर्वेक्षणनुमा जानकारियां भी संकलित की हैं. संजय दुबे ने शायद शब्द लिखकर अपने बचने का रास्ता छोड़ दिया है. उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदी में इस तरह के आयोजन कई बार हो चुके हैं, चाहे वह अवध नारायण मुदगल के संपादन में निकला छाया मयूर का अंक हो, या फिर धीरेंद्र अस्थाना के संपादन में निकला जागरण उदय का अंक. कई बार इस तरह के सर्वेक्षण प्रकाशित हो चुके हैं और इसमें नया कुछ नहीं है. तहलका में नया है तो सिर्फ़ उनमें छपी अशुद्धियां. बेस्ट सेलर में कथा सतीसर को गीतांजलिश्री का उपन्यास बता दिया गया है, जबकि यह चंद्रकांता की कृति है. अन्यान्य पर भी संपादक को गर्व है, लेकिन इसमें विभूति नारायण राय ने कहा है कि गोविंद शुक्ल को मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार... गोविंद मिश्र को गोविंद शुक्ल लिखकर लेखक का अपमान किया गया है. उदय प्रकाश का बड़बोलापन भी यहां है. वह कहते हैं कि 99.9 फीसदी लेखन ऐसा ही है. हिंदी जगत में सबसे चमकदार चेहरे सबसे अयोग्य हैं. मुझे लगता है कि उदय ने जो दशमलव एक फीसदी छोड़ा है, वह अपने लिए छोड़ा है, क्योंकि हिंदी में वही सबसे उत्तम लिख रहे हैं. इसके अलावा भारत भारद्वाज के लेख में भी प्रतीक का प्रकाशन वर्ष 1943 बताया गया है, जबकि उसका प्रकाशन 1945 में शुरू हुआ था. संपादकीयनुमा लेख में निस्वार्थ सहयोग के लिए उपन्यासकार भगवानदास मोरवाल का आभार प्रकट किया गया है. हमें यह नहीं मालूम कि मोरवाल की भूमिका इस अंक में कितनी दूर तक थी, लेकिन अंक की परिकल्पना चाहे जो भी हो, अंक बेहद औसत निकला है. इसने न तो हिंदी साहित्य की किसी विधा में कोई हलचल पैदा की है और न ही इस अंक का कोई स्थायी महत्व है. तहलका के सामने इंडिया टुडे के साहित्य विशेषांक का उदाहरण तो था ही, उसे पार करने की एक चुनौती भी थी, लेकिन चुनौती स्वीकार करना तो दूर की बात, यह अंक इंडिया टुडे के साहित्य विशेषांक के आसपास भी नहीं पहुंच पाया. मुझे यह भी नहीं मालूम कि तरुण तेजपाल की इस अंक में कितनी भूमिका है, लेकिन इतना तो तय है कि संपादक के रूप में उनका नाम छपने की वजह से उनकी ही दृष्टि पर सवाल खड़े होंगे.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

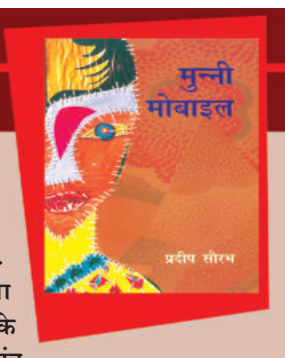

प्रदीप सौरभ

आहिस्ता-आहिस्ता उसका रिश्ता बहुत सच्चा हो गया था...जिसमें कहीं कोई शर्त नहीं थी. न कोई आडंबर, न बनावट. एक खामोशी. वह वक्त भी कुछ और था, वह दौर भी कुछ और. तब प्रेम उच्छृंखल नहीं हुआ करता था, न स्वछंद. वह एक खूबसूरत एहसास था...जिसे आनंद भारती शायद समझ नहीं पाए थे या समझ कर भी समझना नहीं चाहते थे. साहचर्य जनित उस प्रेम का एक ही रंग था-खालिस अपनेपन की गहनता. वह गहनता आनंद भारती का कवच थी. वह गहनता मानसी का वजूद थी.

आनंद भारती अपने माता-पिता से अब भी वैचारिक मतभेद बनाए हुए थे. घर पर रहकर भी उनकी अपनी दुनिया थी. पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक आम जिंदगी बसर करे. पर आनंद भारती के सपनों का आसमान बहुत बड़ा था, जिसके लिए घर के रिश्ते छोटे पड़ने लगे थे. रोज होने वाली कहासुनी को आनंद कई बार भीतर ही भीतर झेलते और कई बार लाइब्रेरी के बाहर बैठे चायवाले को एक छोटी सी पर्ची थमा जाते. पर्ची पर लिखा होता: इस समय घर पहुंच जाइए...निश्चित रूप से. नि:संदेह यह आदेश मानसी के लिए होता और आनंद को याद है कि मानसी ने हमेशा उनके लिखे शब्दों का सम्मान किया.

मानसी कीटगंज में बसे आनंद भारती के घर पहुंचती. खामोश आनंद कई बार उसे सिर्फ बुला लेते और फिर कोई बात नहीं करते. मानसी को सारा हाल आनंद भारती के माता-पिता से मिलता. आनंद भारती के माता-पिता ने मानसी को बेहद स्नेह दिया था. मानसी अंतत: उनके लिए उनकी बेटी की तरह बन गई थी और आनंद भारती जानते हैं कि मानसी और उनके माता-पिता के बीच का वह स्नेहिल रिश्ता आज भी कायम है. अब तक.

ट्रेन पटरियों पर दौड़ती जा रही थी. आनंद भारती की आंखों से नींद कोसों दूर थी. सुबह विश्वविद्यालय परिसर में लेक्चर देना था, इलाहाबाद स्टेशन पर उन्हें कुछ लोग लेने आने वाले थे. कायदन आनंद भारती को कुछ देर सो जाना चाहिए था, ताकि सफर की थकान सफर में ही खत्म कर वह कल तरोताजा रह सकें. पर आनंद भारती जानते हैं, इलाहाबाद उन्हें अब कभी

तरोताजा नहीं बनाता है. फिर भी उनकी धड़कन में बसता है. साल दर साल...न जाने कितने साल गुजर गए. पर लगता है, सब कुछ अभी कल गुजरा हो. कुछ दृश्य आनंद भारती की आंखों में उभर आए. उनकी आंखें पूरी तरह गीली हो गई थीं. घर पर होते तो शायद अकेले में छककर रो लेते. आनंद भारती की भावुकता उनके आसपास के लोगों के लिए असंभव है, पर आनंद जानते हैं कि मानसी ने उन्हें हमेशा समूचे तौर पर जाना है. समझा है.

ऐसा नहीं था कि आनंद भारती मानसी की हर बात को बड़ी तवज्जो देते थे. ऐसा करना तो आनंद भारती की फितरत कभी नहीं रही. कई बार तो आनंद जानबूझ कर मानसी को उपेक्षित कर देते थे. पुस्तकालय आते...अपना काम करते...आसपास के मित्रों से खूब गप्प-गोष्ठी भी करते. पर मानसी की ओर निगाह उठा कर भी नहीं देखते. वह पास आकर कुछ कहने की चेष्टा करती तो सबके सम्मुख उसे प्रताड़ित भी कर देते. पर मानसी ने आनंद भारती से नाराज होना कभी सीखा नहीं था.

अगले अंक में जारी...

हेमकुंड साहिब

आस्था के सहारे दुर्गम रास्ता तय करते हैं यात्री

राजकुमार शर्मा

देवभूमि हिमालय में स्थित सिखों के पावनधाम हेमकुंड साहिब जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को अव्यवस्था के चलते जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है. राज्य सरकार के लाख दावों के बावजूद हेमकुंड यात्रा मार्ग की हालत बेहद खराब है. घाघरिया से आगे दो स्थानों पर ग्लेशियर को काट कर रास्ते का निर्माण तो कर दिया गया, किंतु वहां रेलिंग न होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं.

सिखों के साथ हज़ारों हिंदू श्रद्धालु भी हेमकुंड साहिब में आस्था रखते हैं. हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है. रोज़ाना दो से तीन हज़ार श्रद्धालु मत्था टेकने गोविंदधाम से हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं, जिनमें चार सौ से पांच सौ तक दोपहिया वाहन शामिल हैं. हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गोविंदधाम से 19 किलोमीटर पर्वतीय मार्ग की पैदल यात्रा करनी पड़ती है. इस मार्ग की हालत बेहद खराब है. पैदल एवं खच्चर सवार यात्रियों को एक साथ चलना पड़ता है. हर वक़्त खाई में लुढ़कने का भय बना रहता है. विगत वर्ष खाई में गिरने के कारण लगभग दो दर्जन यात्रियों की मौत हो गई थी. इस वर्ष भी पुलना गांव के पास सुखविंदर नामक महिला यात्रा के दौरान घोड़े से गिर पड़ी, लेकिन पहाड़ की ओर गिरने के कारण उसकी जान बच गई. श्रद्धालुओं को गोविंदघाट से घाघरिया तक हर दो किलोमीटर बाद दुर्गम रास्ते से होकर गुज़रना पड़ता है. घाघरिया से आगे का लगभग 6 किलोमीटर मार्ग बेहद ज़ोखिम भरा है. कई जगह मार्ग की चौड़ाई मात्र तीन से साढ़े तीन फीट है. हर वर्ष प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेलिंग लगा दी जाती है, किंतु इस बार रेलिंग नहीं लगाई गई. ज़रा सी धक्कामुक्की श्रद्धालुओं को मौत के मुंह में धकेल सकती है. गोविंदघाट से आगे बढ़ते ही संचार माध्यम जवाब दे जाते हैं. हेमकुंड साहिब में यात्रियों को न तो मोबाइल की सुविधा मिलती है और न ही लैंडलाइन की. इलाके में मात्र दो सेटेलाइट फोन उपलब्ध हैं, जिनके संचालक यात्रियों से 50 रुपये प्रति काल वसूलते हैं. पूरे मार्ग में कहीं कोई अस्पताल नहीं है. केवल रास्ते में कहीं-कहीं प्राथमिक उपचार बॉक्स ही उपलब्ध कराए गए हैं. यदि यात्रा मार्ग में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो घायलों को छह घंटे बाद ही डॉक्टर के दर्शन हो सकते हैं. हेमकुंड साहिब के दर्शनार्थ

> हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है. रोज़ाना दो से तीन हज़ार श्रद्धालु मत्था टेकने गोविंदधाम से हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं, जिनमें चार सौ से पांच सौ तक दोपहिया वाहन शामिल हैं. हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गोविंदधाम से 19 किलोमीटर पर्वतीय मार्ग की पैदल यात्रा करनी पड़ती है.

दोपहिया वाहन सवार तीर्थ यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. हर समय खुले आसमान में यात्रा करने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. राज्य के पुलिस महानिदेशक सुभाष जोशी ने बाइकर्स पर रोक लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र भी लिखा था, लेकिन उनकी अपील बेअसर सिद्ध हुई. हर वर्ष दर्जन भर से अधिक बाइकर्स अपनी मनमानी के चलते काल के गाल में छलांग लगा लेते हैं. पूरी यात्रा स्थानीय लोगों की मनमानी एवं लूट की शिकार हो रही है. सूबे के पर्यटन मंत्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ प्रशासन के मत्थे मढ़ दिया.

यात्रा मार्ग खाद्य सामग्री एवं पेयजल के नाम पर सरासर लूट हो रही है. चार से पांच गुना ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं.

जोशीमठ में 25 रुपये में मिलने वाली पानी की बोतल यहां 50 रुपये में बेची जा रही है. खाद्य पदार्थों में मिलावट भी की जा रही है. प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

निक ने अपने प्यारे नन्हें कार्टून दर्शकों के लिए खासतौर से वाइब्रेंट, कलरफुल और खूबसूरत रेनकोट्स तैयार किए हैं.

निक के रेनकोट्स

ऐनिमेटेड कार्टूंस स्पोंजबॉब और डोरा स्किन वाले रेनकोट्स ख़ासतौर से सुपर स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें अपने फनी दोस्त हर जगह अच्छे लगते हैं.

आप चिंता कर रहे होंगे कि बारिश का मौसम आने वाला है और तब आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. खासकर जब बच्चे साथ होंगे. इसलिए जरूरी है कि आप इसके लिए पहले से इंतजाम कर लें. बच्चों के लिए तो व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि निक ने अपने प्यारे नन्हें कार्टून दर्शकों के लिए खासतौर से वाइब्रेंट, कलरफुल और खूबसूरत रेनकोट्स तैयार किए हैं. निक के नन्हें दर्शकों के रेनकोट्स भी खास होंगे. ऐनिमेटेड कार्टूंस स्पोंजबॉब और डोरा स्किन वाले रेनकोट्स खासतौर से सुपर स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें अपने फनी दोस्त हर जगह अच्छे लगते हैं. यानी स्पोंजबॉब और डोरा बच्चों के साथ पानी में खेलते नजर आएंगे. उक्त स्पेशल रेनकोट 2 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बिग, शॉर्ट, टॉल और स्मॉल साइज में उपलब्ध हैं. डोरा रेनकोट्स 510 रुपये से लेकर 630 रुपये की रेंज में गर्ली पिंक, ब्यॉइश ब्लू, टफ ग्रीन, रैविशिंग येलो, सीरीन व्हाइट एवं हार्ट रेड आदि वाइब्रेंट रंगों में उपलब्ध हैं. जबकि स्पोंजबॉब फैंस के लिए कलरफुल स्पोंजबॉब रेनकोट्स 170 रुपये से लेकर 420 रुपये तक में उपलब्ध हैं.

बच्चों के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि वे अपने फेवरिट ऐनिमेटेड कैरेक्टर की स्किन में वाटर चैंप बन जाएं. तो बारिश में बच्चों के साथ बाहर जाने से क्या कतराना. बस निक के ये कलरफुल रेनकोट साथ ले जाएं. निक के अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में स्पोंजबॉब स्क्वायर पैंट्स, निंजा हिटोरी, डोरा-द एक्सपोलरर के ऐनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वर्ष 2006 में शुरू होने के बाद अब बाजार में निक के पंद्रह श्रेणी के चिल्ड्रेन प्रोडक्ट्स आते हैं. उक्त सभी प्रोडक्ट देश के सभी रिटेल स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध हैं.

जल हो शुद्ध तो जीवन है सरल

हिंदुस्तान यूनी लीवर लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए प्योरइट कॉम्पैक्ट वाटर प्यूरीफायर लांच किया है. यह उबले हुए जल के समान सुरक्षित जल का समाधान उपलब्ध कराएगा. कंपनी ने यह नया वाटर प्यूरीफायर उन ग्राहकों को लक्ष्य करके लांच किया है, जो अब तक एक वाटर फ्यूरीफायर लगाने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे. प्योरइट कॉम्पैक्ट के साथ कंपनी विश्वस्तरीय सुरक्षा मानक उपलब्ध करा रही है, जिनका किसी भी स्थान पर और किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत जैसे विकासशील देशों में जहां 80 प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल की वजह से होती हैं, वहां प्योरइट कॉम्पैक्ट उपभोक्ताओं को पीलिया, अतिसार, हैजा एवं टायफाइड जैसी जलजनित बीमारियों से पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता है. इसकी अनूठी तकनीक बिना पानी उबाले, बिना बिजली यानी रनिंग वाटर के सभी प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों एवं अशुद्धियों को समाप्त कर देती है. प्योरइट जर्मकिल तकनीक न सिर्फ हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करती है, बल्कि उन सभी खतरनाक विषाणुओं का नाश भी करती है, जो इस श्रेणी के अन्य प्यूरीफायर्स नहीं कर पाते. प्योर इट कॉम्पैक्ट में चार स्तरीय शुद्धीकरण प्रणाली विद्यमान है. यह आपको ऐसा जल उपलब्ध कराती है, जो उबले हुए जल के समान सुरक्षित होता है. इसका माइक्रोफाइबर मेश दिखाई देने योग्य सभी गंदगी निकाल देता है. इसका कॉम्पैक्ट कार्बन ट्रैप अशुद्धियों, परजीवियों एवं अन्य कार्बनिक अशुद्धियों को निकाल देता है. जर्मकिल प्रोसेसर सभी हानिकारक विषाणुओं को समाप्त कर देता है और पॉलिशर अच्छे स्वाद वाला पानी उपलब्ध कराता है.

प्योरइट में अनूठा ऑटो शट ऑफ मैकेनिज्म भी मौजूद है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जब जर्मकिल लाइफ समाप्त हो जाए, तब स्वचालित रूप से निकलने वाले जल की आपूर्ति बंद हो जाए. प्योरइट का निर्गत जल (आइटपुट वॉटर) एंवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए) एवं यूएसए की कठोर जर्मकिल प्रक्रिया के लिए तयशुदा मानदंडों की पूर्ति करता है, जो विश्व की सबसे सख्त नियामक एजेंसियों में हैं. एक बेहद कम समयावधि में प्योरइट को तीन मिलियन गृहस्थों द्वारा अपनाया जा चुका है. प्योरइट कॉम्पैक्ट की कीमत कंपनी ने 1000 रुपये तय की है और यह देश के सभी अग्रणी रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध है.

सुख भरे पलों की हिफाजत

महिलाओं को अक्सर बच्चे के जन्म के पहले और बाद में यह चिंता सताती है कि उनके शरीर में आने वाले बदलाव सौंदर्य को प्रभावित करेंगे. इससे बचने के लिए वे कोई भी नुस्खा आज़माने को तैयार रहती हैं, जिससे बच्चे के जन्म के बाद भी उनका फिगर और खूबसूरती बरकरार रहे. वीएलसीसी के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ने इस ओर काफी काम किया है और ऐसी महिलाओं की समस्या दूर करने की भरपूर कोशिश भी. कंपनी ने प्री और पोस्ट नैटल केयर के अंतर्गत दो नई प्रोडक्ट रेंज लांच की है. इसने प्री नैटल यानी बच्चे के जन्म के पहले की श्रेणी में स्ट्रेच मार्क कंट्रोल लाइट ऑयल एवं स्ट्रेच मार्क कंट्रोल क्रीम तैयार की है. उक्त प्रोडक्ट एक्सपेक्टिंग मदर्स को गर्भावस्था में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स और ड्राइनेस से निजात दिलाने में कामयाब होंगे. पोस्ट नैटल यानी बच्चे के जन्म के बाद के लिए वीएलसीसी की पर्सनल केयर रेंज में टोनिंग एवं फर्मिंग मसाज ऑयल और स्ट्रेच मार्क फेडिंग एवं टोनिंग क्रीम पेश की गई है. प्री नैटल स्ट्रेच मार्क कंट्रोल लाइट ऑयल का 100 मिली पैक 395 रुपये में उपलब्ध है. यह स्ट्रेच मार्क पड़ने से रोकता है, ड्राई स्किन को मॉस्चराइज करता है और त्वचा को नर्म बनाकर खुजली होने से रोकता है.

प्री नैटल स्ट्रेच मार्क कंट्रोल क्रीम का 100 मिली ट्यूब 425 रुपये में उपलब्ध है. यह क्रीम त्वचा के लचीलेपन को बढ़ाती है. हल्की और जल्दी सूखने वाली यह क्रीम एलोवेरा, शीया बटर एवं विटामिन ई से भरपूर है. इससे त्वचा में जलन कम होती है और स्ट्रेच मार्क न के बराबर पड़ते हैं. पोस्ट नैटल टोनिंग एवं फर्मिंग मसाज ऑयल का 100 मिली पैक 395 रुपये में आता है, जो बच्चे के जन्म के बाद स्किन टाइट करके स्ट्रेच मार्क खत्म करता है. डिलीवरी के बाद त्वचा को रिजेनरेट करके रिस्ट्रक्चर करता है और उसके लचीलेपन को बढ़ाकर त्वचा को टोन एवं फर्म करता है. पोस्ट नैटल स्ट्रेच मार्क फेडिंग एवं टोनिंग क्रीम का 100 मिली ट्यूब 425 रुपये का है. डिलीवरी के बाद त्वचा को पहुंचे नुकसान को यह क्रीम ठीक करती है. इसके हीलिंग और रिजेनरेशन गुणात्मक तत्व से खराब हो गए टिश्यू ठीक हो सकते हैं. यह कोलाजेन एवं फाइब्रोब्लास्ट के निर्माण में सहायक है, जिससे स्ट्रेच मार्क आसानी से गायब हो सकते हैं. एलोवेरा जेल, सेसम ऑयल, पैंथेनॉल एवं अल्पाइन मिंट के साथ यह त्वचा को रिवाइटलाइज करती है और उसे वापस अच्छी कंडीशन में लाती है.

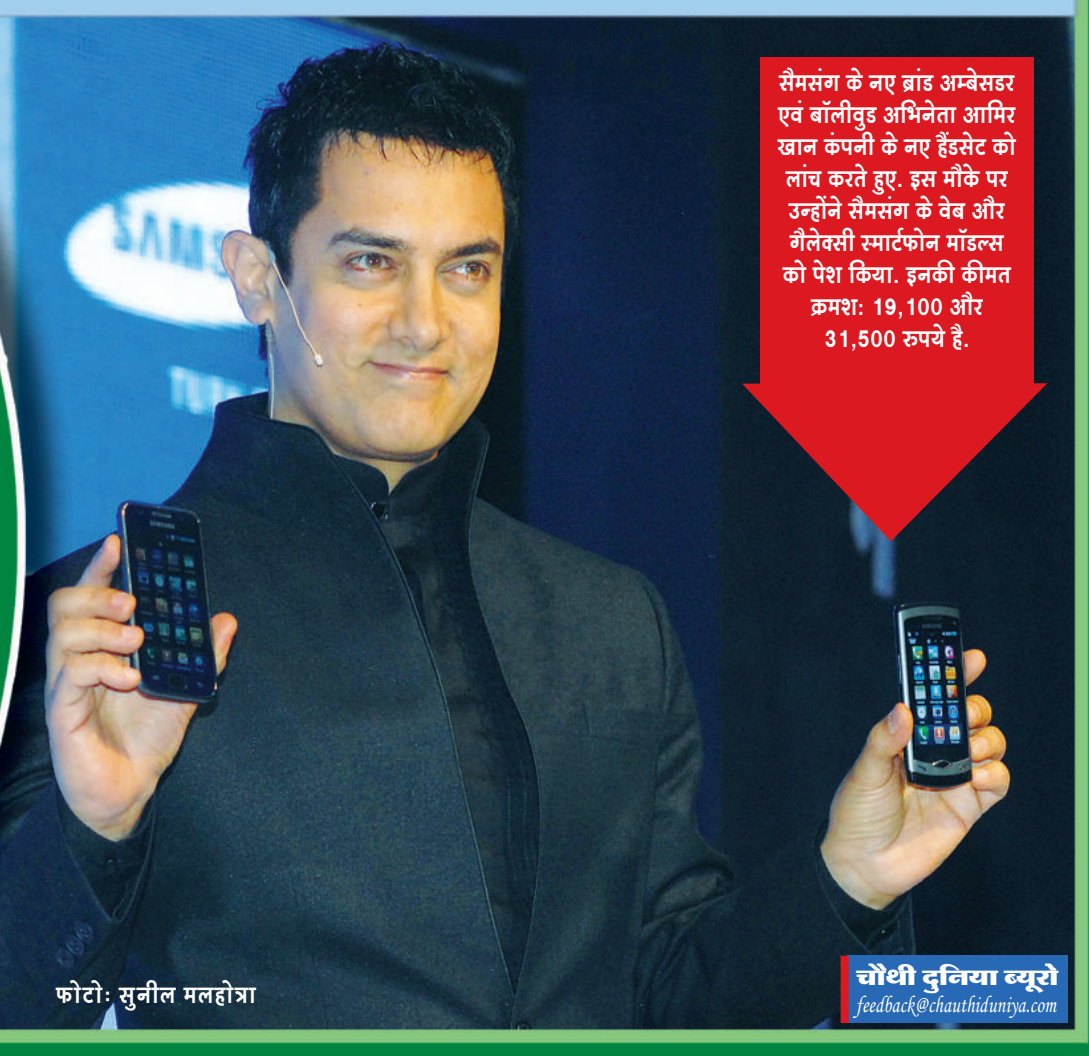

सैमसंग के नए ब्रांड अम्बेसडर एवं बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान कंपनी के नए हैंडसेट को लांच करते हुए. इस मौके पर उन्होंने सैमसंग के वेब और गैलेक्सी स्मार्टफोन मॉडल्स को पेश किया. इनकी कीमत क्रमशः 19,100 और 31,500 रुपये है.

फोटोः सुनील मलहोत्रा

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

एशिया कप के लिए टीम चुनते समय चयन समिति के अध्यक्ष के श्रीकांत ने कहा था कि खिलाड़ियों के चयन में सबसे ज़्यादा ध्यान फिटनेस का ही रखा गया है.

वर्ल्ड कप ड्रैम, भारतीय टीम और बीसीसीआई

आदित्य पूजन

आख़िरकार, भारत ने एशिया कप जीत ही लिया. पंद्रह साल के लंबे अंतराल के बाद यह टूर्नामेंट जीतकर भारत ने एशियाई टीमों के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी. इससे जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की यादें कुछ धूमिल हुईं तो क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर भी नई उम्मीदों का संचार हुआ. लेकिन क्या टीम इंडिया वनडे क्रिकेट के इस महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है? शायद नहीं. खिलाड़ियों की खराब फिटनेस से लगातार जूझ रही इस टीम का हालिया प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा है जिससे ज़्यादा उत्साहित हुआ जा सके. गेंदबाज़ी, बल्लेबाज़ी या क्षेत्ररक्षण, खेल के किसी भी विभाग में टीम के खिलाड़ी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए हैं. बीसीसीआई की हालत यह है कि उसके अधिकारी वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों से ज़्यादा आईपीएल के घोटाले से चिंतित हैं. कोशिश यही की जा रही है कि इस घोटाले का सारा दोष लीग के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी के सिर मढ़ कर मामले को दबा दिया जाए, जबकि इसमें कई नेताओं, अभिनेताओं, बोर्ड के कई अन्य अधिकारियों और खिलाड़ियों तक की संलिप्तता की ख़बरें आ चुकी हैं. वर्ल्ड कप के लिए टीम का स्वरूप अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन बोर्ड को इसकी कोई चिंता नहीं. वह तो आईपीएल के चौथे सीजन में खिलाड़ियों की नीलामी का स्वरूप क्या हो, इसकी चिंताओं में व्यस्त है. बोर्ड के नाकारा रवैये को देखकर डर इस बात का है कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना कहीं एक बार फिर बालू की भीत बनकर ही न रह जाए.

2007 के वर्ल्ड कप में भारत सुपर-8 के दौर में भी नहीं पहुंच पाया था. इसके बाद बोर्ड ने टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी और नए एवं युवा खिलाड़ियों को मौका देने की योजना बनाई. योजना यह थी कि 2011 के वर्ल्ड कप से पहले 25-30 खिलाड़ियों का एक पूल तैयार किया जाए, लेकिन इसके करीब साढ़े तीन साल बाद अब भी हालत यही है कि 25-30 खिलाड़ियों का पूल तो क्या, टीम के पहले पंद्रह खिलाड़ियों के नाम भी तय नहीं हैं और बीसीसीआई के नाकारा अधिकारियों एवं चयन समिति के अधैर्य के चलते विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर अधर में नज़र आ रहा है.

कहां हैं गेंदबाज़

किसी भी टीम की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मज़बूत गेंदबाजी आक्रमण, ताकि विपक्षी टीम के दस विकेट निकाले जा सकें, लेकिन भारतीय टीम इस मामले में अक्सर पीछे रह जाती है. क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर हर्ष भोगले ने कुछ दिन पहले कहा था कि तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण के लिहाज़ से अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों को रॉक बैंड कहा जाए तो टीम इंडिया को विशुद्ध शास्त्रीय संगीत. इसकी वजह भी है. पाकिस्तान के शोएब अख्तर, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल जॉनसन, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन आदि गेंदबाज़ों के बीच एक बड़ी समानता है. ये न केवल गेंद को स्विंग कराने में सक्षम हैं, बल्कि पिच गेंदबाजी के अनुकूल न हो तो गेंद की तेज़ी से भी बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकते हैं. इनकी मौजूदगी से विपक्षी टीमों में एक खलबली मची रहती है और इन्हें केंद्र में रखकर रणनीतियां बनाई जाती हैं. भारत के पास फ़िलहाल ऐसा कोई गेंदबाज़ नहीं है. ज़हीर ख़ान की अगुवाई में भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण को हद से हद मध्यम गति का ही कहा जा सकता है. पिछले चार-पांच सालों में आरपी सिंह, एस श्रीसंत, इशांत शर्मा एवं इरफान पठान जैसे गेंदबाज़ों ने थोड़ी-बहुत उम्मीद ज़रूर जगाई, आज वे टीम का हिस्सा भी नहीं हैं. उनकी जगह एशिया कप और उससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर अशोक डिंडा, अभिमन्यु मिथुन, उमेश यादव सरीखे नए गेंदबाज़ों को मौका दिया गया, लेकिन बीसीसीआई के रवैये को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इनमें से कोई विश्व कप तक टीम में बना रह पाएगा या नहीं. बोर्ड की चयन समिति का रवैया कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों तक टीम में बने रहने के बाद यदि कोई गेंदबाज़ चोटिल हो जाए या उसकी फॉर्म उसे दगा दे जाए तो उसे टीम से बाहर कर किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है.

वर्ष 2010 में टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन

बल्लेबाज	मैच	कुल रन	औसत	50/100
सुरेश रैना	16	482	48.20	1/2
रोहित शर्मा	9	440	55.00	2/1
विराट कोहली	16	598	46.00	1/5
युसूफ पठान	7	129	25.80	0/0
रवींद्र जडेजा	16	297	37.12	0/2
गेंदबाज	**मैच**	**विकेट**	**औसत**	**सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन**
आशीष नेहरा	9	13	31.69	4/40
प्रवीण कुमार	6	9	25.22	3/53
एस श्रीसंत	8	9	52.22	3/49
अशोक डिंडा	5	3	76.00	2/44

अनिश्चित बैटिंग ऑर्डर

टीम इंडिया का सबसे मज़बूत पक्ष इसकी बल्लेबाज़ी को माना जाता है. यदि टीम में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी हो, नंबर तीन पर गौतम गंभीर, फिर युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी हों तो इसे न मानने की कोई वजह भी नहीं दिखती, लेकिन भारतीय टीम की समस्या इसके बाद ही शुरू होती है. बैटिंग ऑर्डर में नंबर छह और सात का प्रश्न टीम-मैनेजमेंट के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है. सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, युसूफ पठान और रवींद्र जडेजा को आज़माया ज़रूर गया है, लेकिन इनमें से किसी की बल्लेबाज़ी में वह निरंतरता नहीं है, जिस पर भरोसा किया जा सके.

जिम्बाब्वे त्रिकोणीय श्रृंखला में सुरेश रैना की कप्तानी में जब बल्लेबाज़ों की इस यंग ब्रिगेड को ज़िम्मेदारियां सौंपी गईं तो टीम दबाव में बिखर गई. शॉर्ट पिच गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ इनकी कमज़ोरी पहले ही जगज़ाहिर हो चुकी है. सच्चाई यह है कि नए बल्लेबाज़ों की यह जमात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज़ों में से कोई चोट या किसी अन्य वजह से टीम से बाहर हो जाता है. जिम्बाब्वे दौरे के बाद एशिया कप में तेंदुलकर, युवराज और बाद में वीरेंद्र सहवाग की ग़ैर मौजूदगी में भारत का मज़बूत बैटिंग ऑर्डर एक बार भी तीन सौ के आंकड़े के पार नहीं पहुंच पाया.

फिटनेस की समस्या

एशिया कप के लिए टीम चुनते समय चयन समिति के अध्यक्ष के श्रीकांत ने कहा था कि खिलाड़ियों के चयन में सबसे ज़्यादा ध्यान फिटनेस का ही रखा गया है. वनडे मैचों में भारतीय बल्लेबाज़ी की रीढ़ माने जाने वाले युवराज सिंह को इसी आधार पर टीम से बाहर रखा गया था, लेकिन ताज़्ज़ुब की बात यह है कि इसके बावजूद टीम की फिटनेस के स्तर में कोई सुधार नज़र नहीं आया. चोटिल होने के बाद सलामी बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग को टूर्नामेंट के बीच में ही वापस लौटना पड़ा, जबकि तेज़ गेंदबाज़ आशीष नेहरा भी खराब फिटनेस के चलते अपनी लय पाने के लिए जूझते रहे. हालांकि फाइनल मुक़ाबले में उनकी धारदार गेंदबाज़ी ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इससे पहले उन्हें एकाध मैच से बाहर भी रहना पड़ा. खिलाड़ियों की खराब फिटनेस का असर टीम की फील्डिंग में भी देखने को मिला. टी-20 वर्ल्ड कप में टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के लिए कोच गैरी कर्स्टन ने खिलाड़ियों की कमज़ोर फिटनेस को सबसे बड़ा कारण बताया था, लेकिन न तो बीसीसीआई और न ही खिलाड़ियों पर इसका कोई असर पड़ता दिख रहा है.

बीसीसीआई और उसकी चयन समिति

देश में क्रिकेट के संचालन के लिए एकमात्र ज़िम्मेदार संस्था बीसीसीआई है, लेकिन इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि यह हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती रहती है. इस साल टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सेमी फाइनल से पहले ही बाहर हो गई तो बोर्ड पहले टीम के कप्तान और फिर खिलाड़ियों को कसूरवार ठहराने की कोशिश करने लगा. धोनी को कप्तान पद से हटाने की चर्चा होने लगी. इसका चारों ओर से विरोध होने लगा तो बीसीसीआई के अधिकारी बगलें झांकने लगे. वे यह क़बूल करने से बचते रहे कि टीम के खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह आईपीएल का थकाऊ शेड्यूल और दोषपूर्ण टीम चयन था. यह आलम तब है, जबकि चयन समिति के सदस्यों को उनके काम के बदले पैसे मिलते हैं. इसके बावजूद उनके ढीले-ढाले रवैये के चलते भारतीय क्रिकेट को बार-बार शर्मसार होना पड़ता है. टीम चयन में पेशेवर अंदाज़ की बात तो दूर, कोई स्थायी सोच भी नज़र नहीं आती. जिम्बाब्वे दौरे के लिए वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर उपलब्ध नहीं थे, तो दिनेश कार्तिक और मुरली विजय की जोड़ी को मौका दिया गया. फिर कार्तिक की जगह नमन ओझा को आज़माया गया, लेकिन भारत अच्छी शुरुआत के लिए तरसता ही रहा. एशिया कप के दौरान सहवाग चोटिल हो गए तो फिर कार्तिक को बुलावा भेजा गया, जबकि कार्तिक बार-बार असफल होते रहे हैं. इसी तरह नंबर सात पर ऑल राउंडर की भूमिका के लिए भी रिवॉल्विंग चेयर का खेल बदस्तूर जारी है. कभी रवींद्र जडेजा तो कभी युसूफ पठान और कभी इरफान पठान को मौका मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वे टीम में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझ सकें, उन्हें बाहर कर दिया जाता है. यही हाल तेज़ गेंदबाज़ों का है. नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौतियों से तालमेल बैठा सकें, इससे पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. खिलाड़ियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक सीमा है. यदि इससे टीम के संतुलन और स्थिरता पर बुरा असर पड़ रहा हो तो ऐसी प्रतिस्पर्द्धा का भला क्या फ़ायदा?

बीसीसीआई के काम करने का तरीका ही यही है. खिलाड़ियों का चयन कोटा सिस्टम के आधार पर होता है. इसमें उनकी योग्यता और प्रदर्शन का उतना महत्व नहीं होता, जितना कि उनकी पहुंच का. बोर्ड के अधिकारी वैसे तो हमेशा ख़बरों में बने रहने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में टीम का प्रदर्शन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता और शोरशराबा मचता है तो वे अपने बिलों में घुस जाते हैं. टीम के प्रदर्शन से ज़्यादा चिंता उन्हें आईपीएल की लगी रहती है. इसकी वजह यह है कि आईपीएल में ज़्यादा पैसा है. ऐसे में उनसे पेशेवर अंदाज़ की उम्मीद करना भी बेमानी है. बोर्ड और उसकी चयन समिति के इस गैर ज़िम्मेदार रवैये का नतीजा यह है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब करीब छह महीने ही बचे हैं, लेकिन टीम इंडिया की नैया अभी भी मंझधार में ही है.

aditya@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 5 जुलाई–11 जुलाई 2010

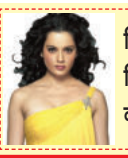

फिल्म लव सेक्स और धोखा के बाद बाला जी का अगला प्रोजेक्ट है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो अपने स्टाइल और लुक्स की वजह से पहले ही लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर चुकी है.

सेंसर बोर्ड, फिल्में और राजनीति-3

मापदंड बदलने की ज़रूरत

राजेश एस कुमार

गांधी जी ने एक बार सेंसरशिप को अपने अंदाज़ में परिभाषित करते हुए कहा था, इफ यू डोंट लाइक समथिंग, क्लोज़ योर आइज़. साउथ फिल्मों का सेंसर बोर्ड इस फलसफे के दोनों पहलुओं का इस्तेमाल करता है. अपने मुताबिक़ आंखें खोलता और बंद करता है. शायद इसीलिए इसे आएदिन क़ानूनी तमाचे पड़ते रहते हैं. ताज़े मामले में पांच साल की लंबी लड़ाई के बाद काधल आरंगम को प्रदर्शन की अनुमति मिल ही गई. इस फ़ैसले ने एक बार फिर से सेंसर बनाम निर्माता-निर्देशक विवाद को हवा दे दी है. वर्ष 2004 में पूरी हो चुकी वेलू प्रभाकरण निर्देशित फिल्म काधल आरंगम को तमिल सिनेमा की सबसे सेक्सी फिल्म का दर्जा दिया गया है. चेन्नई सेंसर बोर्ड ने फिल्म को न्यूड सीन्स और ओपन सेक्स को बढ़ावा देने वाले कंटेंट के चलते अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद वेलू ने दिल्ली ट्रिब्यूनल को फिल्म दिखाई. शोभा दीक्षित की अध्यक्षता में फिल्म देखी गई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा. इस तरह कई कमेटियों के चक्कर काटने के बाद फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार हो पाई है.

हम साउथ सिनेमा में सेंसरशिप की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अश्लील फिल्मों का सबसे बड़ा बाज़ार यही है. पोर्न वेबसाइट पर अगर इंडियन पोर्न कंटेंट होता है तो वह यहीं का होता है. यहां की संस्कृति और फिल्मों में उत्तेजकता हमेशा से ही हावी रही है. मल्लू शब्द भी यहीं की उत्पत्ति है. एक आंकड़े के मुताबिक़, यहां रोज़ लगभग 50 एडल्ट फिल्में बनती हैं और उनकी शूटिंग खुले बीच एवं फॉर्म हाउसों में होती है. कई अभिनेत्रियां किसी पेपेराज़्ज़ी, सेक्स स्कैंडल और एमएमएस कांड में लिप्त मिलती हैं. अभिनेत्री खुशबू तो अक्सर अपने बेबाक बयानों के चलते विवादित रहती हैं. यहां सेक्स और हिंसा के बिना फिल्म बनाना नामुमकिन है. (हालांकि कुछ फिल्म निर्माता इसके अपवाद भी हैं) ऐसी जगह सेंसरशिप क्या इतनी आसान है कि कुछ फिल्मों के चंद दृश्य काटने से उसकी ड्यूटी पूरी हो जाए. कुछ मामलों का ज़िक्र करते हैं, जहां सेंसर अपनी कैंची की धार दिखा रहा था. राम गोपाल वर्मा के सहायक रह चुके समीर की फिल्म दोगम नादांथाथू को बेडरूम और चुंबन दृश्यों के चलते ए सर्टिफिकेट दिया गया. कावेरी नदी जल विवाद पर बनी फिल्म थाम्बीवुड्यन को चेन्नई सेंसर बोर्ड ने प्रमाणपत्र देने से मना कर दिया. इसी तर्ज पर मद्रास हाईकोर्ट ने कमल हासन की फिल्म दशावतारम में कुछ विवादित धार्मिक प्रसंगों के चलते आपत्ति जताई थी. कमल की कामेडी फिल्म मुंबई एक्सप्रेस को एक गाने के चलते ए सर्टिफिकेट देने की कोशिश की गई. जहां का सिनेमाई मिज़ाज़ ही ऐसा है और सिनेमा को टीवी, इंटरनेट एवं पायरेसी से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, वहां चंद फिल्में सेंसर करने से क्या फ़र्क़ पड़ता है. अगर सचमुच बोर्ड एवं सरकार की मंशा यह है कि समाज से हिंसा और अश्लीलता को कम किया जाए तो वे फिल्मों के बजाय उन सभी माध्यमों को बैन करें, जिन पर हिंसा और अश्लीलता का प्रदर्शन होता है और उसे बढ़ावा मिलता है. यह बुनियादी तथ्य सेंसर की समझ से बाहर है कि सवा अरब की आबादी वाले इस देश में सिर्फ़ 15,000 थिएटर हैं, जबकि इंटरनेट एवं टेलीविजन चैनलों की पहुंच की कोई सीमा नहीं है. वहां रात होते ही सेक्स एवं हिंसा का कॉकटेल शुरू हो जाता है. ऐसे में बोर्ड को इतना तो समझ में आता ही होगा कि जनता एकबारगी टिकट लेकर सिनेमाघर ज़्यादा जाती होगी या घर में बैठकर टीवी एवं इंटरनेट पर समय गुज़ारती होगी. इस बात पर भी ग़ौर करने की ज़रूरत है कि यह हिंदी सिनेमा नहीं है, जहां थोड़ी सी अश्लीलता और धार्मिक विवाद आग लगा देते हैं. कई बुनियादी मसले हैं, जिनके साथ सेंसर बोर्ड अपना तारतम्य नहीं बैठा पाता. काधल आरंगम का किस्सा भले ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जीत हो, पर इस सब के बीच दर्शकों की सुध किसी को नहीं है, जिनके लिए यह सारा तामझाम बनाया जाता है. समाज बोल्ड हो चुका है. जितनी तेज़ी से समाज की सोच का दायरा बढ़ा है, सेंसर उतनी ही तेज़ी से संकीर्ण हुआ है. अब रामायण की जगह रियल्टी शो और कायमचूर्ण एवं दंत मंजन के विज्ञापनों की जगह एक्स एवं एडिक्शन डियोड्रेंट के अश्लील विज्ञापन चल रहे हैं. बोर्ड एवं सरकार को विजय आनंद से सबक लेने की ज़रूरत है, जो बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने कहा था कि पोर्न फिल्में लगभग हर जगह खुलेआम बिक रही हैं और देखी जा रही हैं. इनसे लड़ने का यही तरीका है कि बोर्ड इस तरह की फिल्मों को क़ानूनी मान्यता देकर सिनेमाहाल में दिखाए. अगर किसी समस्या को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते तो उसे ग़ैरक़ानूनी तरीके से होने से रोक तो सकते हैं. साउथ सिनेमा का अपना मिज़ाज़ और चटकीला रंग है. इसलिए हिंदी सिनेमा की तर्ज पर सेंसरसिप नहीं चल सकती. यहां की संस्कृति, दर्शकों की मानसिकता और इंटरटेनमेंट वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है. इसके आधार पर ही मापदंडों को बदला जाए. तब जाकर सेंसरशिप के सही मायने निकल कर सामने आएंगे. वरना वेलू जैसे जागरूक निर्देशक क़ानूनी चुनौतियां देते रहेंगे और सेंसर बोर्ड अपनी फ़ज़ीहत कराता रहेगा.

rajeshy@chauthiduniya.com

कंगना बनी मोना

रितिक रोशन के साथ राकेश रोशन की होम प्रोडक्शन फिल्म काइट्स में बेहतरीन डांस करके कंगना रनावत ने प्रमाणित कर दिया है कि वह बॉलीवुड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. राकेश रोशन के बाद उन पर नज़र पड़ी है मिलन लुथरिया की. फिल्म लव सेक्स और धोख़ा के बाद बाला जी का अगला प्रोजेक्ट है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो अपने स्टाइल और लुक्स की वजह से पहले ही लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर चुकी है. इन दिनों प्रोडक्शन हाउसों में कॉमेडी एवं रोमांटिक फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, वहीं बाला जी ने इससे बिल्कुल अलग 1970 के दौर के मुंबई शहर में उभरते हुए अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने का साहस किया है. इसमें अंडरवर्ल्ड के किंग सुल्तान (अजय देवगन) के उदय के बाद उसके परास्त होकर गिरने और उसके साथी शोहेब (इमरान हाशमी) द्वारा उसकी गद्दी छीनने की कहानी है. फिल्म को सत्तर के दशक वाले रोमांस, स्मगलिंग, कैबरे और माफिया राज का तड़का दिया गया है. उस दौर में जिन महिलाओं को अंडरवर्ल्ड की हवा लगी, वे निडर हुआ करती थीं. इस फिल्म में ऐसी ही महिला का रोल अदा किया है कंगना रनावत ने, जो रेहाना के किरदार में अजय देवगन की प्रेमिका बनी हैं. वह इस फिल्म में उभरती हुई बालीवुड अदाकारा का किरदार निभा रही हैं, जिसकी शक्ल मशहूर ख़ूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से मिलती है, और सुल्तान मधुबाला के साथ एकतफा प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उस जैसी दिखने वाली रेहाना से ही शादी कर लेता है. यानी कि इस फिल्म में एक्शन एक्टर अजय के साथ रोमांस करेंगी कंगना. मिलन कहते हैं कि उन्हें कंगना इस रोल के लिए बहुत पसंद आई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत अलग है और अलग-अलग मेकअप से वह हर रोज़ अलग-अलग लुक देती है. उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, जो एक्सपोजर से अश्लील नहीं, बल्कि ग्लैमरस लगती है. किरदार के साथ न्याय हो सके, इसके लिए कंगना ने पश्चिमी देशों और बॉलीवुड के उस दौर के फैशन को काफी स्टडी किया है. कंगना के कॉस्ट्यूम मानोशी नाथ और रूशी शर्मा द्वारा डिजाइन किए गए हैं. उन्होंने ड्रेस डिजाइन करने से पहले कंगना के किरदार को अच्छी तरह से समझा और फिर बाल, एक्सेसरीज और कॉस्ट्यूम के स्केच बनाए. कंगना का लुक कुछ इस तरह बनाया गया, जिसमें वह परफेक्ट मोना लगती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रिव्यू

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई

लव, सेक्स और धोख़ा के बाद एकता कपूर एक और अलग फ्लेवर वाली स्क्रिप्ट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पर फिल्म बनाने की राह पर हैं. इस फिल्म में अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनावत एवं प्राची देसाई हैं. फिल्म का बैकड्रॉप 1970 का है, जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां चरम पर थीं. माना जा रहा है कि फिल्म की कहानी मुंबई के उस वक्त के गैंगस्टर शेख इब्राहिम कासकर से प्रेरित है, जो एक सामान्य स्मगलर से बड़ा गैंगस्टर बन गया था. फिल्म में दाऊद का रोल इमरान हाशमी ने निभाया है और हाज़ी मस्तान का अजय देवगन ने. बाला जी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म को रेट्रो चिक स्टाइल में ग्लैमरस और पावरफुल अंदाज़ में ट्रीटमेंट दिया गया है. फिल्म में कंगना रनावत और प्राची देसाई दोनों क्राइम सुप्रीमो की प्रेमिकाओं के रूप में नज़र आएंगी. फिल्म में हाज़ी मस्तान की ज़िंदगी बहुत रंगीन होती है. उसकी पर्सनालिटी में कई शेड्स होते हैं, जैसे स्मार्ट स्मगलर, सफल डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्मों का प्रोड्यूसर एवं राजनेता आदि. माना जाता है कि 1985-86 में बना दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ उसने ही बनाया था. पेशा कोई भी हो, प्यार तो होता ही है, उसका भी दिल ख़ूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला पर आ गया, लेकिन जब उसका एकतरफा प्यार रंग नहीं ला पाया तो उसने नई अभिनेत्री सोना, जो मधुबाला की तरह दिखती थी, से शादी कर ली. अनुमान है कि फिल्म अच्छी होगी, पर इस कहानी को निर्देशक मिलन लुथरिया किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी पहली फिल्म कच्चे धागे अलग पटकथा और ट्रीटमेंट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल नहीं दिखा पाई थी. हालांकि दीवार: लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम, टैक्सी नंबर 9211 में उन्होंने बढ़िया काम कराया, पर एक बार फिर उनकी फिल्म हैट्रिक बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का संगीत प्रीतम ने दिया है. फिल्म अपने प्रोमोज के चलते रिलीज से बहुत पहले से ही चर्चित है. वजह है इस फिल्म को दिए गए रेट्रो ट्रीटमेंट लुक्स, साथ में क्राइम और रोमांस का तड़का.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 5 जुलाई-11 जुलाई 2010

www.chauthiduniya.com

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे

किसी टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट की तरह भाजपा-जदयू के रिश्ते की कहानी उलट-पलट हो रही है. नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार ने मोर्चा क्या खोला, राजनीतिक विश्लेषकों ने फायदे और नुक़सान की माप-तौल करनी शुरू कर दी. कुछ तो यह भी कहने लगे कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा. बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन बचेगा या टूट जाएगा, इसका आकलन किया जाने लगा. इन अटकलों के बीच इन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का समझौता भी चल रहा है. इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की असली कहानी क्या है, इसे गहराई से समझने की जरूरत है.

मनीष कुमार

बिहार की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है. नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली है, जिससे बिहार में किसी भी दूसरी पार्टी के लिए चुनाव में जीत हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा. अगर नीतीश कुमार की रणनीति सफल हो जाती है तो आने वाले कई सालों तक बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन का राज कायम हो जाएगा. जिस तरह 1947 से 1977 तक कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, बिहार में वैसी ही व्यवस्था कायम हो जाएगी. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया. बिहार की गठबंधन सरकार के दोनों दल आपस में ही भिड़ गए. शुरुआत से ही दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई और स्थिति बेक़ाबू न हो जाए, इसलिए पटना में जारी जंग को दिल्ली से ठंडा किया गया. जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने आकलन के बाज़ार को यह कहकर ठंडा कर दिया कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को कोई ख़तरा नहीं है. भाजपा और जदयू की दोस्ती पहले की ही तरह जारी है.

हैरानी की बात यह है कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच नरेंद्र मोदी के असली राजनीतिक विरोधी लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान पूरे खेल से गायब रहे. नीतीश कुमार के मोदी विरोध की वजह क्या है? नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वह नरेंद्र मोदी या किसी और की वजह से अपनी सरकार को ख़तरे में डालने का जोखिम कतई नहीं उठा सकते. फिर वह ऐसा करके क्या साबित करना चाहते थे? अगर भाजपा से इस स्तर पर वैचारिक विरोधाभास है, अगर उन्हें कट्टर हिंदूवाद से इतनी ही नफरत है, तो वह उनके साथ मिलकर सरकार क्यों चला रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? बिहार में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जदयू और भाजपा के बीच जो नूराकुश्ती हुई, उसे गहराई से समझना ज़रूरी है. पहले भाजपा ने एक विज्ञापन के माध्यम से मुसलमानों के बीच यह संदेह फैलाने की कोशिश की कि गुजरात के मुसलमान दूसरे राज्यों के मुसलमानों से ज़्यादा ख़ुश हैं. बाद में मालूम चला कि विज्ञापन में दिखाई गई लड़कियां उत्तर प्रदेश की हैं. मतलब यह है कि विज्ञापन बनाने वालों को पूरे गुजरात में एक भी खुशहाल मुसलमान नहीं मिला, जो भाजपा के इस विज्ञापन में दिखने के लिए तैयार हो. इसलिए उत्तर प्रदेश से खुशहाल मुसलमानों की तस्वीर इंपोर्ट की गई. विज्ञापन को लेकर जमकर हंगामा हुआ. नीतीश कुमार ने रात्रिभोज निरस्त कर भाजपा को बेइज्जत करने की भी कोशिश की. नीतीश कुमार ने ऐसा तेवर दिखाया कि मोदी विरोध का सारा श्रेय खुद ले गए. समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा न होता तो मीडिया और बिहार की जनता के बीच रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव मोदी विरोध का झंडा बुलंद करते, नीतीश कुमार को मोदी का दोस्त बताकर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कांफ्रेंस तो की, लेकिन उसका मुसलमानों पर असर नहीं हुआ. रामविलास पासवान भी सिर्फ़ बयानबाजी करते नज़र आए. नीतीश कुमार इस रणनीति से भाजपा के असली विरोधियों को हाशिए पर ले जाने में सफल रहे हैं. कोई यह भी नहीं पूछ पाया कि नीतीश कुमार और रामविलास पासवान गुजरात दंगों के दौरान केंद्रीय मंत्री थे. अगर नीतीश कुमार मुसलमानों के इतने ही हिमायती हैं तो गुजरात दंगे के दौरान वह रेलमंत्री क्यों बने रहे? उन्होंने रामविलास पासवान की तरह इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया या फिर गोधरा जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों और यादवों को एकजुट करके बिहार पर कई सालों तक राज किया. नीतीश कुमार की रणनीति यह है कि मुस्लिम वोटबैंक बिखर जाए, ताकि लालू प्रसाद यादव का एम-वाई समीकरण फिर से जीवित न हो सके. लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपने शासनकाल के दौरान दंगा नहीं होने दिया, लेकिन वह मुसलमानों के विकास के लिए कुछ नहीं कर सके. नीतीश कुमार ने न सिर्फ़ दंगे को रोका, बल्कि विकास, कानून-व्यवस्था देने की अच्छी कोशिश के साथ-साथ मुसलमानों को न्याय भी दिलाया. यही वजह है कि परिस्थिति नीतीश कुमार के पक्ष में है. अगर वह ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक ऐसा अध्याय शुरू हो सकता है, जिसे वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है. दुनिया भर में 30 से ज़्यादा ऐसे देश हैं, जहां प्रजातंत्र तो है, लेकिन वहां एक ही पार्टी का शासन कई सालों से चला आ रहा है. इन देशों में गरीबी है, बेरोज़गारी है, जनता समस्याओं से जूझ रही है. वहां चुनाव भी होते हैं, दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां जब भी चुनाव होते हैं, सत्तारूढ़ दल ही हमेशा जीतता है. इन देशों की जनता पढ़ी-लिखी है और जागरूक भी. चुनाव में कोई धांधली भी नहीं होती है, फिर भी चुनाव का नतीजा हमेशा एक ही होता है. विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पातीं. प्रजातंत्र का यह रूप अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका के अलावा यूएसए और कनाडा में भी मौजूद है. इन दोनों देशों में ऐसे कई राज्य हैं, जहां एक ही पार्टी का वर्चस्व कई सालों से चला आ रहा है. अमेरिका के कोलंबिया में 1973 से डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती आई है. 1927 से अब तक शिकागो की मेयरशिप पर डेमोक्रेटिक पार्टी का क़ब्ज़ा है. कनाडा के एल्बर्टा राज्य में 1971 से प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही है. राजनीति शास्त्र में ऐसे पार्टी सिस्टम को वन पार्टी डोमिनेंट के नाम से जाना जाता है. वन पार्टी डोमिनेंट एक ऐसा पार्टी सिस्टम है, जहां सिर्फ़ एक पार्टी ही सरकार बनाती है और विपक्ष हमेशा विपक्ष ही बना रहता है. कुछ देशों में क़ानूनन विपक्ष मौजूद तो है, लेकिन वह इतना कमज़ोर और बेअसर होता है कि सत्तारूढ़ दल को चुनौती नहीं दे पाता. ऐसा नहीं है कि इन देशों या राज्यों में प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हैं. जैसे कि जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर कनाडा के सस्काचेवान राज्य में टॉमी डगलस की सरकार, ये सब लोकप्रियता के बल पर लगातार सरकार में बने हुए हैं. किसी भी प्रजातंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष का अपना स्थान होता है. बहुदलीय व्यवस्था में हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने-अपने विचार जनता के सामने रखती है. जिस पार्टी की विचारधारा को जनता समर्थन देती है, वह चुनाव जीत जाती है. जनता जिस विचारधारा के ख़िलाफ़ होती है, उसे वोट नहीं मिलता और वह पार्टी हार जाती है. अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी दूसरे दलों के एजेंडे और विचारधारा को ही हाईजैक कर ले तो विपक्ष क्या करे. सत्तापक्ष विपक्ष को असरहीन बनाने और उसे हाशिए पर ले जाने के लिए ऐसी ही परिस्थिति को जन्म देता है, जिसमें वह पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका खुद ले लेता है. वह अपनी नीति और विचारधारा के समर्थकों के साथ-साथ अपने फैसले का विरोध करने वाली जनता को भी साथ लेने में सफल हो जाता है. भारत में आज़ादी के बाद से 1977 तक ऐसा ही हुआ था. कांग्रेस की सरकार लगातार राज करती रही. इस कालखंड में कांग्रेस पार्टी में समाजवादी, कट्टर हिंदूवादी, वामपंथी और मजबूत क्षेत्रीय नेता मौजूद थे. सरकार चलाने वाले भी कांग्रेसी और सरकार का विरोध करने वाली भी कांग्रेस ही थी. इसलिए दूसरी किसी पार्टी का न तो विस्तार हो सका और न ही केंद्र में कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टी जन्म ले सकी.

भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने बिहार में ऐसा ही किया है. नरेंद्र मोदी का विरोध कर नीतीश अपनी सेकुलर इमेज बनाए रखने में कामयाब रहे. मुसलमानों के बीच नीतीश ने अपनी साख बनाई और हिंदू वोटरों के बीच भाजपा ने अपनी साख बना ली. भाजपा और जदयू आपस में झगड़ कर अपनी-अपनी पार्टियों को फायदा पहुंचाने में कामयाब रहे. बिहार में विरोधी पार्टियों का सबसे बड़ा हथियार सेकुलरिज्म है. नीतीश ने इस चाल से विरोधियों के सबसे मजबूत हथियार को ही बेअसर करने की कोशिश की है. वह भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रहे हैं, साथ ही भाजपा के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी का विरोध भी कर रहे हैं. यह कैसे भुलाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश ने मोदी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा था. उन्होंने यह दावा किया था कि वह नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं देंगे. यही वजह है कि नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिला, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही पंजाब की रैली में वह मोदी के साथ हाथ मिलाते दिखे. वही विवादित फोटो इस बार बिहार के अखबारों में छपी है. सामाजिक जीवन में हम दुश्मन के दोस्त को दुश्मन और दुश्मन के दुश्मन को दोस्त मानते हैं. बिहार की राजनीति में सालों से चली आ रही इस कथनी को गलत साबित करने की रणनीति तैयार की गई है. कई सालों के चुनावों के अनुभवों से यह साबित हो चुका है कि बाबरी मस्जिद, आरक्षण, सांप्रदायिक दंगों को लेकर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मानते हैं. नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि सत्ता में बरक़रार रहने के लिए मुस्लिम वोटों की उन्हें जरूरत पड़ेगी. वह यह भी जानते हैं कि मुस्लिम वोट अगर उनके ख़िलाफ़ चला गया तो वह चुनाव हार भी सकते हैं. यही वजह है कि नीतीश नरेंद्र मोदी के विरोध का नारा बुलंद कर रहे हैं. नीतीश कुमार मुसलमानों के वोटबैंक में अगर सेंध मारने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका जीतना तय है. वह बिहार में दोस्त के दुश्मन को भी दोस्त बनाने में कामयाब हो जाएंगे.

manish@chauthiduniya.com

मैंने कोशिश की थी कि पार्टी में सब मिलकर काम करें और सब कुछ ठीक से चलता रहे.

उनकी मौत की खबर से मुझे गहरा आघात लगा. दिग्विजय बाबू राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देते थे.

श्रद्धांजलि

दिग्विजय सिंह (1955-2010)

दिग्विजय सिंह के निधन की ख़बर सुनते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई. लगभग सभी दल के नेताओं ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया, जिसकी भरपाई मुश्किल है. दिग्विजय सिंह सबसे बेहतर संबंध बनाकर रहते थे, चाहे वह उनका विरोधी ही क्यों न हो. देश और अपने राज्य बिहार का दुनिया भर में सम्मान दर्ज कराने में दिग्विजय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है. बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर गांव में 14 नवंबर 1955 को दिग्विजय सिंह पैदा हुए थे. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमए और दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल की शिक्षा ली थी. वह जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे. छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले दिग्विजय सिंह केंद्र में विदेश, सूचना और प्रसारण व रेल मंत्रालयों में राज्यमंत्री के पद पर भी रहे. राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी उनकी खास रुचि थी. इसी रुचि के कारण वह 1999 से भारतीय शूटिंग संघ के अध्यक्ष थे. और इसी रुचि की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर वे लंदन भी गए थे, जहां वे अस्वस्थ हुए और उनका निधन भी हो गया. दिग्विजय सिंह तीन बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे. वह 1990 में पहली बार राज्य सभा के लिए चुने गए थे. पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने ही उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी से बगावत कर बांका से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और चुनौतीपूर्ण जीत हासिल की थी.

बिहार के बांका जिले से निर्दलीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के निधन से देश सदमे में है. राजनेताओं ने दिग्विजय सिंह के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है. जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव दिग्विजय सिंह को याद कर बेहद भावुक हो जाते हैं. कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के अंदर हालात से लड़ने की अद्भुत क्षमता थी. वे किसी भी हाल में हार मानने वाले इंसान नहीं थे. शरद यादव और दिग्विजय सिंह का साथ काफी लंबा रहा है. तमाम वादे जुड़ी हैं, जो शरद यादव को विचलित कर रही हैं. शरद शादव कहते हैं कि मौजूदा वक़्त में देश को दिग्विजय सिंह सरीखे नेताओं की बेहद ज़रूरत है. ऐसे में उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

-शरद यादव, *राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड*

जदयू से ही राज्य सभा सांसद एन के सिंह भी दिग्विजय सिंह से जुड़ी स्मृतियों में खोए हैं. दिग्विजय सिंह का ज़िक्र करते हुए उनकी आवाज़ से उनकी तकलीफ साफ़ झलकती है. कहते हैं कि आज की राजनीति में ऐसे साफ़ और बेबाक दिल वाले राजनीतिकों की कमी है. दिग्विजय सिंह न सिर्फ एक उम्दा राजनेता थे बल्कि बेहतरीन इंसान भी थे. ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई. यही कारण था कि उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा तो शानदार जीत हासिल की. दिग्विजय सिंह का असमय चले जाना सामाजिक क्षति भी है.

-एन के सिंह, *राज्य सभा सांसद*

दिग्विजय सिंह की चर्चा करते हुए समाजवादी नेता जया जेटली की आवाज़ भर्रा जाती है. पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. वे याद करती है उन दिनों को जब प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस के साथ मिल कर दिग्विजय सिंह सामाजिक क्रांति की रूप-रेखा तैयार किया करते थे. कहती हैं कि जॉर्ज साहब दिग्विजय सिंह की सलाह को खूब अहमियत दिया करते थे. देश-दुनिया के मसलों-मसायल पर दोनों के बीच बहस का दौर चलता था. दिग्विजय सिंह बेहद संज़ीदा इंसान थे. उनका चले जाना सबकी निजी क्षति है.

- जया जेटली, *समाजवादी नेता*

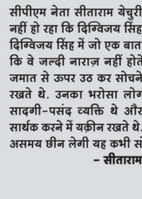

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को अभी भी यक़ीन नहीं हो रहा कि दिग्विजय सिंह नहीं रहे. बताते हैं कि दिग्विजय सिंह में जो एक बात सबसे ख़ास थी वो ये कि वे जल्दी नाराज़ नहीं होते थे. हमेशा दल और जमात से ऊपर उठ कर सोचने और करने में यक़ीन रखते थे. उनका भरोसा लोगों को जोड़ने में था. सादगी-पसंद व्यक्ति थे और हमेशा कुछ न कुछ सार्थक करने में यक़ीन रखते थे. बीमारी उन्हें इस तरह असमय छीन लेगी यह कभी सोचा न था.

- सीताराम येचुरी, *सीपीएम नेता*

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय दिग्विजय सिंह के निधन की ख़बर से हतप्रभ हैं. बताते हैं कि दिग्विजय सिंह का व्यक्तित्व हमेशा ही अपने साथियों के लिए भी प्रेरणादायक रहा है. उनके अंदर एक खिलाड़ी का उत्साह था. उसी ऊर्जा से लबरेज़ थे वे. उन्होंने वित्त, विदेश और रेल मंत्रालयों को बखूबी संभाला था, पर 1999 में जब वे शूटिंग संघ के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी रचनात्मकता का नायाब परिचय दिया था. उनकी यह क्रियाशीलता रोजमर्रा के कामों में भी दिखती थी. अभी उन्हें देश के लिए बहुत कुछ करना था. देश भर के लोग उनके निधन से आहत हैं. अभी भी भरोसा करना मुश्किल है कि दिग्विजय सिंह सरीखा ज़िन्दादिल इंसान हमारे बीच नहीं रहा.

- सुबोध कांत सहाय, *केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री*

दिग्विजय सिंह के निधन की ख़बर पर तो सहसा भरोसा ही नहीं हुआ पर काल ने हमलोगों के बीच से संभावनाओं से भरे एक राजनेता को छीन लिया. उनसे सहमत हुआ जा सकता था या फिर असहमत पर उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था. मैंने कोशिश की थी कि पार्टी में सब मिलकर काम करें और सब कुछ ठीक से चलता रहे. हाल के दिनों में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था. मेरे साथ दिग्विजय सिंह के अच्छे संबंध थे. हमलोगों ने राजनीति और सरकार में मिलकर काम किया है. मैं उन्हें उसी रूप में याद करता हूं. दिग्विजय जी एक बेहतरीन इंसान थे. पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए वह कहते हैं कि दिग्विजय जी हमलोगों के संपर्क में 1996 में उस समय आए जब समता पार्टी व चंद्रशेखर जी की पार्टी में नजदीकी बढ़ी थी. उन्होंने कहा कि दिग्विजय जी के निधन से बिहार व देश को काफी नुकसान हुआ है. वह बिहार के लिए हमेशा सोचते रहते थे. अभी हाल में ही जब उन्होंने संसद में बिहार का मुद्दा उठाया तो मैंने उन्हें बधाई दी थी. अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी उनकी गहरी पकड़ थी. भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अभी दिग्विजय जी की उम्र ही क्या थी.

-नीतीश कुमार, *मुख्यमंत्री, बिहार*

दिग्विजय बाबू हमेशा नैतिकता व मूल्यों की राजनीति पर भरोसा करते थे. राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया. अपने राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उन्होंने ईमानदारी से आम लोगों की सेवा की और यह स्थापित करने की कोशिश की कि जरूरतमंदों की मदद कर संतुष्टि का अहसास किया जा सकता है. मोदी ने कहा कि छात्र जीवन से ही मेरा उनके साथ अच्छा रिश्ता रहा है. दिग्विजय बाबू असमय हमलोगों से बिछुड़ गए. इनमें असीम संभावनाएं थीं. दिल्ली में बिहार के हक की लड़ाई लड़ने में वह हमेशा आगे रहे. जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपने बुलंद इरादों व आवाज़ से सदन में बिहार के मान-सम्मान की रक्षा की. सरकार में रहकर व एक सांसद के तौर पर भी उन्होंने जो काम किए उसे भूलाया नहीं जा सकता है.

- सुशील मोदी, *उप मुख्यमंत्री, बिहार*

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमता के ख़िलाफ़ जो लड़ाई छेड़ी वह अधूरी रह गई. लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी मौत की ख़बर से उन्हें गहरा आघात लगा. दिग्विजय बाबू राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देते थे. वह समाजवादी विचारधारा के प्रखर राजनेता थे. उन्होंने सरकार में रहकर जो काम किया उससे देश व दुनिया में उनकी छवि बनी. सार्वजनिक जीवन में वह शुचिता के हिमायती थे. लालू प्रसाद मानते हैं कि अभी देश व बिहार को दिग्विजय बाबू की बहुत ज़रूरत थी. पर वह समय से पहले हमलोगों को छोड़कर चले गए. वह हमेशा ग़रीबों के हित की लड़ाई लड़ने की बात करते थे. उनकी राय थी कि बिहार के विकास में ही देश का विकास छिपा है. वह हमेशा बिहार के बारे में सोचते थे.

-लालू प्रसाद, *अध्यक्ष, राजद*

दिग्विजय जी ने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया. एक मंत्री, एक सांसद व एक नागरिक के रूप में वह हमेशा ग़रीबों की लड़ाई लड़ते रहे. वह हमेशा कहते थे कि नेताओं की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है. लाचार, ग़रीब व मजबूर आम इंसान नेताओं को आशा भरी निगाहों से देखता है. इसलिए नेताओं की भी ज़िम्मेदारी है कि जहां तक संभव हो ईमानदारी के साथ आम जनता का कष्ट दूर करने का प्रयास करें. रामविलास पासवान मानते हैं कि दिग्विजय बाबू के निधन से बिहार व देश ने एक मजबूत सिपाही खो दिया है. दिग्विजय जी अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते थे. राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मामलों में उनकी सोच बहुत ही सुलझी हुई थी. प्रदेश व देश के हित में वह कड़वी बात भी कहने से नहीं हिचकते थे. उनकी मौत से मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी नुकसान हुआ.

-रामविलास पासवान, *अध्यक्ष, लोजपा*

भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वह हंसता मुस्कराता चेहरा अब बस स्मृतियों में ही रहेगा. दिग्विजय भाई के न रहने से जो राजनीतिक व सामाजिक शून्यता पैदा हुई उसे भरना मुश्किल होगा. बिहार के लिए कुछ करने की उनके दिल में बड़ी इच्छा थी. जब भी उन्हें सरकार में रहने का मौका मिला उन्होंने राज्य हित में कई फैसले किए. उनका मानना था कि सब लोगों को मिलकर इस पिछड़े प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. संसद में भी दिग्विजय भाई ने कई मौकों पर बड़ी ही साफगोई से बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया. वह संबंधों को निभाना जानते थे. मूल्यों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया. वह सुलझे विचारों के एक प्रगतिशील नेता थे.

-ललन सिंह, *सांसद*

मेरे पास शब्द नहीं है. दिग्विजय बाबू को खोकर ऐसा लगता है कि ग़रीबों के लिए लड़ने वाला वीर हमलोगों के बीच से चला गया. हमेशा उनकी कोशिश रहती थी कि बिहार को आगे ले जाने का प्रयास होता रहे. बातचीत में बिहार को लेकर उनका दर्द उभर जाता था. हमलोग साथ आए ताकि बिहार व देश को लेकर दिग्विजय बाबू के दिल में जो सपना है उसे पूरा किया जा सके पर काल ने समय से पहले उन्हें हमलोगों से जुदा कर दिया. वह सबका ख्याल रखते थे यही कारण है कि उनके शुभचिंतकों व दोस्तों की संख्या बहुत है.

-नागमणि, *पूर्व सांसद*

चौथी दुनिया
दिल्ली, 5 जुलाई–11 जुलाई 2010

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

हिना अपनी पहचान खुद बनाने के लिए भोजपुरी फ़िल्मों में क़दम रखा. अब उनकी मंशा है कि वह भोजपुरी फ़िल्मों में खास मुकाम हासिल करें.

जागरण में गिन्नी का जलवा

विकास कुमार

हर ताला खुले, हर खुशियां मिले, एक जयमाता की चाभी से ... बेबी गिन्नी के सुरीले गले से ये बोल फुटते ही जहां दर्शक एवं श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहीं इस बाल कलाकार के पिता व जागरण सम्राट के नाम से मशहूर सरदार धर्मेंद्र सिंह के अरमान भी पूरे होते दिखाई पड़ते हैं. मां गुरमीत कौर भी काफी खुश हैं. कला और भक्ति के संगम से सफलता और शोहरत पाने वाले इस परिवार को माता ने क्या नहीं दिया? बहुत धन की लालसा है नहीं शोहरत इतनी है कि धर्मेंद्र सिंह जागरण सम्राट के नाम से मशहूर हैं वहीं बेबी गिन्नी की गिनती उत्तर बिहार की एक प्रमुख सेलिब्रिटी के रूप में होती है. सोनू निगम, उदित नारायण, विनोद राठौर, लखवीर सिंह 'लक्खा' जैसे उम्दा कलाकारों के साथ मंच की शोभा बढ़ा चुके हैं. सरदार धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री की प्रतिभा के बारे में जो सपना देखा था, बेबी गिन्नी ने उस सपने को हक़ीक़त में बदल दिया है तभी तो छोटी–सी उम्र में ही उसके कई भक्ति एलबम बाज़ार में धूम मचा रहे हैं. समस्तीपुर शहर के बंगाली टोला निवासी धर्मेंद्र सिंह ने देश के सभी प्रमुख छोटे–बड़े शहरों में अपनी गायकी का जादू बिखेर चुके हैं.

कहते हैं कि कला की बारीकियां विरासत में मिलती है और उसे संवारते हैं कला के कद्रदान. ये बातें गायक कलाकार पिता–पुत्री पर बिल्कुल सटीक बैठती है. मंच व कैसेट से निरंतर सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले धर्मेंद्र सिंह के पिता स्व. यशवंत सिंह भी किसी जमाने में प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी एचएमवी के गायक कलाकार हुआ करते थे.

मां के दरबार में छैला बिहारी, तृप्ति शाक्या, कल्पना, देवी जैसे कलाकारों के साथ अपने फन का जलवा दिखाने में पहले केवल सरदार धर्मेंद्र सिंह ही रहते थे, लेकिन बाद में जब उनकी पुत्री बेबी गिन्नी पर विरासत का आशीर्वाद सिर चढ़कर बोलने लगा तो आज गिन्नी के बगैर भगवती जागरण सूना सा लगने लगता है. कम उम्र की बड़ी गायिका गिन्नी पिता के साथ–साथ बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और नेपाल में कई कार्यक्रम कर चुकी है. धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि गायकी उन्हें विरासत में मिली है और सफलता का सारा श्रेय पूर्वजों को जाता है. वह कहते हैं कि विरासत में मिली गायकी को ऊंचाई देने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं और इसी का नतीजा है कि उनकी बेटी गिन्नी भी उनके साथ लगभग सभी कार्यक्रमों एवं एलबमों में माता का गुणगान करती है. भगवती जागरण में गिन्नी के माइक थामते ही श्रोताओं की भीड़ खिंचती चली आती है. कड़ी मेहनत से मुकाम तक पहुंचे धर्मेंद्र–गिन्नी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. बजरंगबली को गुरु मानने वाले धर्मेंद्र का कहना है कि उनकी पूंजी प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों से मिलने वाला प्यार है. कला की बारीकियों की समझ और कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता का ही परिणाम है कि जागरण सम्राट के एक के बाद एक भजन एलबम लांच होते जा रहे हैं. पूनम सीरीज से मैया मेरे घर आना तथा तेरा सुंदर सा दरबार रिलीज होने के बाद टी–सीरीज से उन्हें ऑफर मिला और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. टी–सीरीज के बैनर तले निकला भक्ति एलबम जग की तू रानी माई महारानी ने खूब धमाल मचाया. एलबम की सफलता का श्रेय धर्मेंद्र मां भगवती को देते हैं. इसके अलावे तेरा सुंदर सा दरबार, ओ मेरी मइया आई लव यू आदि उनके प्रमुख और मशहूर एलबमों में से है. श्याम भक्त हनुमान धर्मेंद्र–गिन्नी का आने वाले एलबम का नाम है, जिसकी प्रतीक्षा उन्हें बेसब्री से है. बता दें कि अपने एलबम के लिए धर्मेंद्र स्वंय ही गीत लिखते हैं तथा धुन भी तैयार करते हैं. धर्मेंद्र–गिन्नी के कुछ प्रचलित गीतों में यूं तो दर हैं लाखों जग में तुमसा नहीं कोई डेरा मां–जन्नत भी तो फीकी लगती तेरे दर पे आकर मां..., करके चोला लाल मईया आना..., लाली–लाली चुनरी है...', आदि प्रमुख हैं. चार हज़ार से अधिक स्टेज शो कर चुके जागरण सम्राट का कहना है मां के दरबार में जो कोई भी आए, शुद्ध और सच्चे मन से आए. मां की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अत: मन की शुद्धि के लिए भजन जरूरी है. चौथी दुनिया के पाठकों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जाम पे जाम क्या पीते हो, रात पीयो सुबह उतर जाएगी, मेरी मां के नाम का जाम पी के देख, सारी जिंदगी सुधर जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

भगवती जागरण में गिन्नी के माइक थामते ही श्रोताओं की भीड़ खिंचती चली आती है. कड़ी मेहनत से मुकाम तक पहुंचे धर्मेंद्र–गिन्नी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. बजरंगबली को गुरु मानने वाले धर्मेंद्र का कहना है कि उनकी पूंजी प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों से मिलने वाला प्यार है.

हिना भोजपुरी में हिट

बॉलीवुड में सिर्फ़ वही टिक सकता है जो या तो किसी गॉडफादर के साथ हो या फिर स्टार फैमिली से ताल्लुक रखता हो.

हिना ने फ़िल्म फन कैन बी डेंजरस समटाइम और घुटन से अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पानी मांगते नज़र आई. हालांकि हिना को इन दोनों फ़िल्में से काफी उम्मीद थी. मगर, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. इससे हताश हिना कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास में चली गईं और कुछ दिन बाद हिना ने फ़िल्मों में फिर से वापसी की. इस बार उसने अपनी वापसी हिंदी फ़िल्मों के बजाए भोजपुरी से की. वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि आजकल बॉलीवुड में टिकना सबके बस की बात नही हैं. यहां सिर्फ़ वही टिक सकता है, जो या तो किसी गॉडफादर के साथ हो या फिर स्टार फैमिली से ताल्लुक रखता हो. इनमें से दोनों विकल्प उनके पास है नहीं. इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाने के लिए भोजपुरी फ़िल्मों में क़दम रखा. अब उनकी मंशा है कि वह भोजपुरी फ़िल्मों में खास मुकाम हासिल करें. हाल ही में फ़िल्म अजब देवर के गजब भोजाई में उनकी भूमिका खासी सराही गई थी. उन्होंने कई और फ़िल्मों के प्रोजेक्ट साइन किए हैं, लेकिन वह अभी इन प्रोजेक्ट का खुलासा करने से बच रही हैं. सूत्रों की मानें तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने भोजपुरी फ़िल्मों की एक नई डील साइन की है. जिसमें भो जपुरी के सुपरस्टार रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ दो फ़िल्मों के अलावा कई बड़े बैनर की फ़िल्में शामिल हैं. जल्द ही ये फ़िल्में शूटिंग के लिए फ्लोर पर चली जाएंगी. उनकी पिछली सफलताओं को देखकर तो यही लगता है कि वह भोजपुरी हीरोइनों को कड़ी टक्कर देने वाली हैं. वैसे उनकी ख्वाहिश हिंदी फ़िल्मों में काम करने की भी है, लेकिन फिलहाल वह भोजपुरी फ़िल्मों से ही खुश हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 5 जुलाई-11 जुलाई 2010

www.chauthiduniya.com

मध्यप्रदेश

आर्थिक उपनिवेश बन गया है

भोपाल गैस त्रासदी 1984 पर आए अदालती फ़ैसले के संदर्भ में आज पूरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जनविरोधी करतूतों पर चर्चा चल रही है, लेकिन यह चर्चा सतही और बेमानी है. एक भयंकरतम औद्योगिक दुर्घटना से हमने आज तक कोई सबक नहीं लिया है और न ही इन कंपनियों के कपट को भली प्रकार समझा है.

विनय दीक्षित

दुनिया में 1990 का दशक एक परिवर्तनकारी दौर रहा है. इसी समय में समाजवादी सोवियत संघ का विखंडन हुआ और कई समाजवादी देशों ने ख़ुशी-ख़ुशी पूंजीवाद को अपना लिया. चीन भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा. दुनिया के मज़दूरों, एक हो जाओ का नारा लगाने वाले समाजवादी, कम्युनिस्ट संगठन और देश कमज़ोर हो गए, क्योंकि इनके नारे से प्रेरणा लेकर दुनिया के सरमाएदारों, एक हो जाओ का नारा बुलंद करते हुए आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रणेताओं ने भारत जैसे दुनिया के कई विकासशील, ग़रीब एवं पिछड़े देशों को विकास और संपन्नता का सपना दिखाते हुए अपने परंपरागत समाजवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था से भटकाया.

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने विदेशी सत्ता से संघर्ष करते समय देश की जनता को समाजवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था का पाठ सिखाया था और जनता ने भी समाजवाद के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी. इसीलिए आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने यहां की अर्थव्यवस्था को समाजवादी आधार वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप दिया था. नेहरू युग के बाद इंदिरा युग में भारत घोषित तौर पर समाजवादी राष्ट्र बनने के लिए वचनबद्ध हुआ और देश की अर्थव्यवस्था ने समाजवादी रूप लेना शुरू किया, लेकिन पूंजीवाद की माया बड़ी विकट है. भ्रष्ट और अक्षम सरकारी तंत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र को तहस-नहस कर डाला और ज़्यादातर सार्वजनिक उपक्रम कुप्रबंधन के कारण घाटे में चले गए. सरकारी सेवाएं भी घाटे के कारण महंगी होने लगीं और श्रमिक आंदोलन निरंकुश एवं लोभी होने के कारण ग़ैर जिम्मेदार होते गए. इस कारण जनता में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र अपनी साख खोते गए. नतीजा यह हुआ कि घाटे और क़र्ज़ के बोझ वाली अर्थव्यवस्था 1991 में इतनी चरमरा गई कि भारत को विदेशों से क़र्ज़ लेने के लिए अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा. इस घटना ने देशवासियों को भावनात्मक रूप से विचलित कर दिया और तभी वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के मसीहा बनकर उभरे. उन्होंने आर्थिक सुधारों के नाम पर भारत में घोर पूंजीवादी आर्थिक नीतियों एवं अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ें जमाने का खुला अवसर दे दिया. बाद में अस्थिर और कमज़ोर सरकारों के दौर में तो विदेशी पूंजीवाद भारत पर बुरी तरह हावी हो गया. 1998 से 2004 तक देश में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मनमोहन सिंह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और भी मज़बूत बनाया, क्योंकि भाजपा शुरू से ही समाजवादी अर्थव्यवस्था की विरोधी और पूंजीवाद समर्थक विचारधारा की पोषक रही है. भाजपा शासन के बाद एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन सरकार सत्ता में आई और मनमोहन सिंह संयोग से देश के प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे.

बतौर प्रधानमंत्री 2004 में सरकार के पहले बजट के दौरान उन्होंने कहा था कि आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा देने की ज़रूरत है. उनका यह कथन सही था, क्योंकि आर्थिक सुधारों के दौर में आम जनता, ख़ासकर श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी और जीवन में आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी, लेकिन मानवीय चेहरा देने के नाम पर मनमोहन सिंह ने पूंजीवाद को बढ़ावा देते हुए देश में विदेशी पूंजी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए और कुछ कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं. इससे अर्थव्यवस्था के प्रति जनता में बढ़ते असंतोष को दूर करने में सरकार को कुछ सफलता ज़रूर मिली, लेकिन अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी के दबाव के कारण इतनी अस्त-व्यस्त हो गई कि सरकार उस पर क़ाबू नहीं रख सकी. यही कारण है कि बाज़ार में महंगाई दिनोंदिन बढ़ रही है और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी उस पर क़ाबू नहीं पाया जा सका है. शेयर बाज़ार में आश्चर्यजनक तरीके से उछाल और गिरावट आती है और सरकार तमाशा देखती रहती है. छोटे और मझोले शेयरधारक रोज़ लुटते हैं. शेयर बाज़ार के खेल में कई छोटे-बड़े बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी लुट चुकी हैं. जनता की लूट का यह पैसा कहां जाता है, यह सभी को मालूम है, लेकिन इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. अर्थव्यवस्था के जानकार भली प्रकार जानते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कल्पना पर आधारित है. इन कंपनियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के पूंजीवाद समर्थक देशों की सरकारों से मिलकर दुनिया में इस नई व्यवस्था को छल, बल और कपट से लागू कराया. विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का परोक्ष क़ब्ज़ा है. ये वैश्विक संगठन इन्हीं कंपनियों के हित में काम करते हैं और दुनिया के विकासशील एवं ग़रीब देशों पर नई आर्थिक नीतियां और नई अर्थव्यवस्था लागू करने के लिए दबाव डालते हैं. यूरोप के देशों ने समुद्र में नौ-परिवहन में महारत हासिल करने के बाद 15वीं सदी में नई दुनिया की खोज का अभियान दुनिया भर में अपने उपनिवेश कायम करने और दुनिया की संपत्ति पर क़ब्ज़ा करने के लिए ही चलाया था. अमेरिका इसी अभियान की खोज है और इसके बाद अमेरिका पर यूरोप की गोरी नस्लों का कब्जा हो गया. अफ्रीका और एशिया में भी इनके पांव फैले और अड्डे कायम हो गए. अफ्रीका में शुरू में खनिज और वन संपदा का दोहन न कर पाने के कारण यूरोपीय देशों ने मेहनतकश और ताक़तवर अश्वेतों को गुलाम बनाकर उनका व्यापार किया था. बाद में अफ्रीकी देशों पर क़ब्ज़ा करके वहां की संपदा लूट ली गई. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर ही आई थी, लेकिन जल्दी ही इस कंपनी ने तिज़ारत के साथ सियासत करना शुरू कर दिया और फिर भारत पर अपना क़ब्ज़ा जमा कर भारतीय संपदा की लूट मचा दी. आज 21वीं सदी में दुनिया में राजनीतिक उपनिवेश बनाने की ज़रूरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कतई नहीं है, क्योंकि उपनिवेश बनाकर वहां शासन करने की ज़िम्मेदारी भी आ जाती है. उक्त कंपनियां तो बिना उपनिवेश बनाए देशों पर अपना क़ब्ज़ा कर रही हैं और उन देशों की अर्थव्यवस्था को अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार संचालित भी कर रही हैं. भारत में यही हो रहा है.

जिस यूनियन कार्बाइड कारखाने से हुई गैस रिसाव की दुर्घटना का शोर मचाया जा रहा है, वह हमारे अपने शासकों और प्रशासकों की ग़लती की देन है, लेकिन दुर्घटना की सज़ा आम जनता को मिली है. राज्य सरकार के प्रचलित क़ानूनों के अनुसार भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने की स्थापना ही अवैध और अनियमित थी. शहर के बीचोबीच घातक उत्पादों का उत्पादन करने वाला कारखाना नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन कार्बाइड के देशी-विदेशी प्रबंधकों के दबाव के कारण सरकार ने इस अवैध कारखाने को भी मान्यता दी और इससे तैयार होने वाले उत्पादों की एक बड़ी ख़रीददार राज्य सरकार ही बनी. गैस कांड के बाद जो कुछ हुआ, उस पर बहुत शोर मचाया जा चुका है और आंसू बहाए जा चुके हैं, लेकिन इससे हमने कोई सबक नहीं लिया है. दूसरी ओर मानवता के ख़िलाफ़ क्रूर अपराध करने वाली कार्बाइड कंपनी को अपने किए पर कोई अफ़सोस नहीं है. मात्र 750 करोड़ डॉलर में 15 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत और लाखों स्थायी बीमारों का समझौता लोकतांत्रिक सरकार ने कर लिया. यह कोई अजूबा नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फ़ितरत का एक नमूना है. ये अपने स्वार्थ और मुनाफ़े के लिए हमेशा क्रूर और निर्मम बनी रहती हैं. नैतिकता की इनकी अपनी परिभाषा होती है. संयुक्त राज्य अमेरिका इन कंपनियों का सबसे बड़ा संरक्षक देश है, लेकिन वहां भी इन कंपनियों ने अपने लाभ और लोभ से प्रेरित होकर

(शेष पृष्ठ 18 पर)

ज़हरीली गैस फॉसजिन इस्तेमाल होती थी?

यूनियन कार्बाइड के भोपाल कारखाने में प्रतिबंधित ज़हरीली फॉसजिन गैस का इस्तेमाल होता था और दो-तीन दिसंबर 1984 की रात गैस त्रासदी के समय कारखाने से अन्य ज़हरीली गैसों के साथ फॉसजीन गैस का भी रिसन हुआ था? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके उत्तर आज तक न तो सरकार ने दिए हैं और न ही यूनियन कार्बाइड कारखाने के किसी ज़िम्मेदार अधिकारी ने इनका उत्तर देना ज़रूरी समझा है.

लेकिन, सच किसी के छिपाये नहीं छिपता है. गैस त्रासदी के बाद कारखाने में बचे कचरे और मलवे को नष्ट करने से पहले सीएसआईआर जैसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था और कुछ अन्य रसायन विश्लेषण प्रयोगशालाओं में इस कचरे का रासायनिक अध्ययन किया गया, तो पता चला कि इस कचरे में फॉसजिन गैस के अवशेष भी मौजूद हैं. इसके अलावा 25 दिसंबर 1981 को इस कारखाने में हुई गैस रिसाव की घटना में अशरफ अली नामक एक कर्मचारी की मौत हुई थी, तब भी यह अंदेशा लगाया गया था कि अशरफ की मौत फॉसजिन गैस के संपर्क में आने से हुई थी, लेकिन इस घटना को दबा दिया गया और राज्य सरकार ने भी इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया. तानाशाह हिटलर के शासनकाल में नस्ल विरोधी भावनाओं के कारण यहूदियों और नाजी विरोधियों के सामूहिक नरसंहार के लिए गैस चैम्बर में फॉसजिन गैस का इस्तेमाल किया जाता था. गैस चैम्बर में फॉसजिन गैस छोड़कर सैकड़ों लोगों को कुछ ही मिनटों में मौत की नींद सुला दिया जाता था. गैस त्रासदी के बाद से भोपालवासियों को यह सवाल कचोट रहा है कि दो-तीन दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड कारखाने से कहीं फॉसजिन गैस का रिसाव तो नहीं हुआ था. भोपाल गैस त्रासदी के प्रभाव में आए लाखों लोग आज भी विभिन्न बीमारियों के शिकार हैं, चूंकि आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि गैस रिसाव में किन ज़हरीली और घातक गैसों का रिसाव हुआ था और इनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है. इसलिए आज तक गैस पीड़ितों के सही इलाज की कोई सही दवा नहीं हो सकी है. एक जानकार का कहना है कि गैसकांड के बाद इलाज के लिए कुछ एंटीडोट इंजेक्शन भोपाल लाए गए थे और इनका कुछ लोगों पर इस्तेमाल भी किया गया था, जिनके अच्छे नतीजे निकले, लेकिन बाद में इन इंजेक्शनों के उपयोग पर रहस्यमय तरीके से रोक लगा दी गई, इस कारण इनका प्रयोग ज़्यादा गैस पीड़ितों पर नहीं किया गया. हो सकता है कि एंटीडोट इंजेक्शनों की सफलता से यह पोल खुल जाती कि कार्बाइड से रिसी गैस किस प्रकार की थी और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है. यह भी सवाल है कि क्या यूनियन कार्बाइड ने कीटनाशकों के उत्पादन में इस्तेमाल के लिए फॉसजिन गैस के इपयोग के बारे में सरकार से अनुमति ली थी या बिना अनुमति के ही इस गैस का इस्तेमाल और भंडारण किया जा रहा था. मीडिया द्वारा सरकार के ज़िम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में कई बार पूछा गया, लेकिन अधिकृत तौर पर उत्तर देने में सभी ने अपनी असमर्थता ज़ाहिर कर मीडिया से दूरी बना ली.

ज़िला प्रशासन जब तक तालाबों की स्थिति को शहर में सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं करता तब तक सतना शहर के लिए पानी उपलब्ध करवा पाना असंभव है.

कटनी बारूदी विस्फोटों के ज़रिए अवैध उत्खनन का सबसे बड़ा केन्द्र है. आदिवासियों की भूमि पर अवैध क़ब्ज़े और अवैध उत्खनन की शिकायतें आम हो चुकी हैं.

सार –संक्षेप

पूरा गांव सीमेंट कारखाने को लीज़ पर

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार जनहित की हर प्रकार से कुर्बानी दे रही है. एसीसी सीमेन्ट कारखाने के लिए राज्य सरकार ने कटनी ज़िले के विजयराघवगढ़ विकासखण्ड के आदिवासी बहुल ग्राम मेहगांव को पूरी तरह लीज़ पर दे दिया है. अब कारखाने के प्रबंधक इस गांव में सदियों से बसे आदिवासियों को उजाड़ने में लगे हुए हैं. गांव वालों को उजाड़कर कारखाने के लिए ज़मीन खाली कराने के उद्देश्य से एसीसी के प्रबंधक अब दबंगों का सहारा लेकर भोले-भाले गांव वालों को डरा धमकाकर अपना घरबार छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. कई ग़रीब कमजोरों ने तो डर के कारण गांव में बने अपने झोपड़े खुद ही गिराने शुरू कर दिए हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी भी औद्योगीकरण के लिए एसीसी प्रबंधकों का खुला साथ देते हुए गांव वालों पर धौंस जमा रहे हैं और इन्हें जल्द से जल्द गांव से भाग जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. एसीसी द्वारा महगांव की जमीन लीज पर लेकर वहां बसे परिवारों को बेघर तो कर दिया गया, लेकिन इन्हें शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा नहीं दिया गया. मिले आधे अधूरे मुआवजे पर दलालों ने सेंध लगानी प्रारंभ कर दी जिससे गरीबों के हाथ मामूली राशि आई. इसे लेकर कुछ सड़क किनारे रहने लगे तो कुछ ने नया अमेहटा में आसरा ले लिया, लेकिन विस्थापितों को पुर्नस्थापित करने की दिशा में न तो एसीसी प्रबंधन और न ही प्रशासन ने कोई प्रयास किए जिससे लुटे पिटे विस्थापित आज भी मदद की उम्मीद लिए बैठे हैं. महगांव की वर्तमान महिला उपसरंपच विमला बाई केवट का आरोप है कि महगांव में एसीसी …

रीवा में फिर बसेगा सफ़ेद बाघ

… प्रदेश के पास एक भी सफेद बाघ नहीं बचा. मुख्य वन्यजीव संरक्षक एचएस पाबला ने मुताबिक सफेद बाघ सबसे पहले रीवा के जंगलों में देखे गए थे और यही कारण है कि स्थानीय लोग इस वन्यप्राणी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. सफेद बाघ हर चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसलिए हमारी 100 हेक्टेयर से भी बड़े क्षेत्र में एक चिड़ियाघर, बचाव केंद्र तथा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की योजना है. पाबला कहते हैं कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद अब हम चिड़ियाघर तथा प्रजनन केंद्र की स्थापना करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाएंगे.

विदेशी पर्यटकों का नहीं भाया भोपाल

शैल-शिखरों और प्राकृतिक झील, तालाबों की सुरम्य नगरी भोपाल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है. पर्यटन की सभी संभावनाओं से भरपूर भोपाल देश के पर्यटन नक्शे में आज भी उपेक्षित है, क्योंकि राज्य का पर्यटन उद्योग अविकसित और पिछड़ा हुआ है. भारत सरकार के पर्यटन विभाग और निजी पर्यटन उद्योग के प्रयासों से मध्य प्रदेश के खजुराहो, सांची, मांडू, कांहाकिसली, बांधवगढ़, भेड़ाघाट आदि पर्यटन केंद्रो में तो विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन भोपाल बहुत कम संख्या में ही रुकते हैं. कई विदेशी पर्यटक तो इंदौर …

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ एक का शेष

मध्य प्रदेश आर्थिक उपनिवेश बन गया है

feedback@chauthiduniya.com

सम्पन्न हैं फिर भी लाचार हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की माटी के सपूत हैं. वह राज्य का विकास और भला करना चाहते हैं. उनकी इस सदविचार इच्छा पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए. …

… मिर्ची, नर्मदाकछार के गांव के बैगन, टमाटर, लौंगी मिर्ची की प्रसिद्धी निजी संपर्कों के माध्यम से दिल्ली और मुम्बई तक अभिजात्य वर्ग में फैलाई थी. अंग्रेज अफसरों के संस्मरण …

पिपरिया की दाल का कमाल

पिपरिया की तुअर दाल अपने स्वाद के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और इस दाल का स्वाद चखने वाले विदेशी भी इसके दीवाने हो जाते हैं. इसलिए इसकी मांग इंग्लैंड, अमेरिका में भी बनी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज तक पिपरिया की दाल के उत्पादन और बाज़ार को बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं.

किसानों को उनकी उपज का बहुत अधिक लाभदायक मूल्य नहीं मिल पाता है. स्थानीय व्यापारी खेत में खड़ी फसल के दौरान ही भाव तय करके फ़सल ख़रीद लेते हैं और फिर दाल बेचने के बाद क़ीमत चुकाते हैं. स्थानीय व्यापारी दूसरे राज्यों के व्यापारियों से दाल का सौदा करते हैं और बिचौलिए की भूमिका अदा करके, थोड़े से मुनाफे पर बाहरी व्यापारियों को दाल बेच देते हैं.

बड़े शहरों के सुपर बाजार और उपभोक्ता भंडारों में पिपरिया की दाल का सौदा ऊंचे दामों …

… फसल आते ही दाल का सौदा बाहरी व्यापारी अपने क़ब्ज़े में ले लेते हैं.

विनय दीक्षित
feedback@chauthiduniya.com

सार –संक्षेप

दो दशक बाद अवैध क़ब्ज़े हटे

मध्य प्रदेश का प्रशासन भूमाफिया और शहरी भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा करने वालों के सामने लाचार और बेबस है. इसका यही उदाहरण पर्याप्त है कि राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास श्यामला हिल्स के पास वन विहार मार्ग पर एक दर्जन से अधिक अवैध मकानों को हटाने में सरकार को पूरे बीस साल लग गए. मुख्यमंत्री निवास के पास से बीस साल बाद अवैध कब्जा हटाने के बाद जिला प्रशासन ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी इस कार्यवाही की सूचना जनता को दी और अपने हाथों अपनी पीठ ठोककर वाहवाही लूटी. भोपाल में मनोरम श्यामला पहाड़ी पर बड़ी झील के पास मुख्यमंत्री निवास है और नीचे वन विहार, मानव संग्रहालय जैसे दर्शनीय स्थल भी झील किनारे ही है. लेकिन झील किनारे बने वोट क्लब के पास कीमती जमीन पर वर्षों से लोगों ने अवैध क़ब्ज़े कर रखे थे. कई लोगों ने तो बाक़ायदा पक्के मकान बना लिए थे और इनमें व्यवसायिक गतिविधियां भी चल रही थीं, लेकिन जिला प्रशासन और भोपाल नगर निगम ने इन अवैध कब्जो को हटाने में कोई रुचि नहीं ली. हाल ही अवैध कब्जा हटाने और भूमाफिया के हौसले पस्त करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने कार्यवाही शुरू की है. इस कार्यवाही में अवैध कब्जाधारियों को समझा बुझाकर और इन्हें अन्यत्र पुनर्वास देकर हटाया जा रहा है. वोट क्लब से हटाए गए एक दर्जन परिवारों को पीपलनेर में गंदी बस्ती उन्मूलन विभाग द्वारा बनाए गए मकानों में बसाया गया है, …

… और अम्मू खां. इन्हें पीपलनेर में बसाया गया है. लेकिन अभी भी राजधानी में राज्यमंत्रालय, विधानसभा के आसपास बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे हैं, जिन्हें हटाने में प्रशासन को पसीना आ रहा हैं. विधायक विश्राम गृह परिसर में तो विधानसभा के छोटे कर्मचारियों ने ही अवैध कब्जे कर रखे हैं और झुग्गियां किराये पर दे रखी हैं. इतना ही नहीं, अवैध कब्जों वाले क्षेत्र में सुअर पालन, गाय पालन जैसे नगर सीमा में प्रतिबंधित धंधे भी चल रहे हैं.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 90 प्रतिशत वर–वधू फ़र्ज़ी

आम जनता में अपनी छवि बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगह-जगह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकारी विवाह समारोह आयोजित कराने में पूरी रुचि लेते हैं, लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज़ कर देते हैं कि नौकरशाह इन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अधिक से अधिक विवाह संपन्न कराने के लिए कई फ़र्ज़ी वर-वधू जमा कर लेते हैं और सरकारी अनुदान की बंदरबाट करते हैं. बड़वा हके ग्राम बागोद में प्रस्तावित 201 जोड़ों के सामूहिक विवाह के फ़र्ज़ीवाड़े की जब जिला प्रशासन ने जांच कराई, तो 90 प्रतिशत वर-वधू फ़र्ज़ी पाए गए. बाबा साहेब अंबेडकर बलाई समाज समिति के तत्वावधान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह के प्रशासन ने जांच के बाद रोक दिया था. …

… प्रकार राज एक्सप्रेस की पहल पर शासन को 17 लाख 10 हज़ार रुपए की चपत लगने से बच गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भूमाफिया लील रहे हैं तालाब

पुष्पेन्द्र मोर्या

जल समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की जल संवर्धन और जल संरक्षण नीति में करोड़ों रुपए ख़र्च करने के बाद सतना ज़िले को पानी की समस्या से उबारा नहीं जा सका है. ये सभी नीतियां फ़िलवक़्त तक अप्रभावी हैं. 25 जुलाई 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी के पूर्व से अस्तित्व में रहे तालाबों को अतिक्रमणकारियों के क़ब्ज़े से मुक्त कराकर पुनः तालाब के रूप में विकसित किया जाने का फरमान जारी किया गया था. इस फ़ैसले के तहत माननीय न्यायालय ने पशु-पक्षी, आदमी की ज़रूरतों को प्रमाणित करते हुए शहर के पेयजल स्त्रोतों के …

… जगतदेव तालाब, बजरहा तालाब, रती तालाब, अमोधा तालाब अधिकतम सात हेक्टेयर तक की ज़मीन में फैले हुए थे. सरकारी दस्तावेजों में शहर की जल आपूर्ति के लिए तालाब एकमात्र स्त्रोत है और तालाबों के अस्तित्व का शहर से पूरी तरह समाप्त होना संकट की घंटी है. परिणामस्वरूप सतना शहर में पेयजल की स्थिति भीषण हो गई है. पिछले पांच सालों से गर्मी में सतना ज़िले से सर्वाधिक पलायन की घटना होती है.

ज़िला प्रशासन जब तक तालाबों की स्थिति को शहर में सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं करता तब तक सतना शहर के लिए पानी उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है. भूमाफ़ियाओं के कड़े नियंत्रणों की ज़रूरत ज़िले के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा बार-बार उठाई जाती है परंतु सतनावसियों को आज तक प्रशासन द्वारा उठाने जाने वाले सख्त कदमों का …

> सतना शहर में भूमाफ़िया के कसते शिकंजे से वहां रहे चौबीस तालाबों में से अधिकांश ख़त्म हो चुके हैं. भूमाफ़िया निजी फ़ायदे के लिए शहर के तालाबों के अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं और प्रशासन बेख़बर सो रहा है. यहां वर्तमान और भविष्य में होने वाले जल …

feedback@chauthiduniya.com

अवैध खनन के लिए

नक्सली डर पैदा करने की कोशिश

मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में असामाजिक घटनाओं के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मध्य प्रदेश पुलिस अब तक यह दावा करती आई है कि कटनी नक्सलियों के लिए राज्य में पहली पसंदीदा जगह है. लेकिन पुलिस का यह दावा कुछ ही वक़्त में बेपर्दा होता हुआ लग रहा है. ऐसी अप्रत्याशित घोषणा के तुरंत बाद ही दावा विवादास्पद लगने लगा है.

अरविंद शर्मा

मधु कुमार पी. वी. राजगोपाल

feedback@chauthiduniya.com

बहरा है प्रशासन

इंसानियत सबसे ऊपर

शंकराचार्य और इमाम एक मंच पर

जगतगुरु शंकराचार्य

इमाम अहमद इलयासी

हिन्दू मुसलमान भाईचारे के साथ मिल-जुलकर देश की तरक्की के लिए काम करेगें, तो दुनिया में एक मज़बूत और महान देश के रूप में भारत अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकेगा.

राजधानी भोपाल में हाल ही में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इमाम मुअज्जिन …

… एक विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिन्दू और मुस्लिम धर्माचार्य शामिल होगें. इस अवसर पर हिन्दू मुस्लिम …

कैलाश जोशी

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 5 जुलाई–11 जुलाई 2010

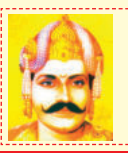

आधा साल बीत गया है लेकिन अभी भोज समारोह के कार्यक्रम नहीं बन पाए हैं. भोपाल में इस समारोह को आयोजित करने के पीछे भाजपा का सांप्रदायिक दृष्टिकोण ही काम कर रहा है.

सरकार ही प्रदूषित कर रही है नर्मदा

धार्मिक दृष्टि से अति पवित्र और प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को 15 करोड़ रुपयों की सहायता दी है. इसके अलावा राज्य सरकार भी नर्मदा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए कई प्रकार के ख़र्चीले उपाय कर रही है, लेकिन इस सबके बाद भी नर्मदा में जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है. कारण, सरकार स्वयं नर्मदा को गंदा कर रही है.

एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर बसे नगरों और बड़े गांवों के पास के लगभग 100 नाले नर्मदा नदी में मिलते हैं और इन नालों में प्रदूषित जल के साथ-साथ शहर का गंदा पानी भी बहकर नदी में मिल जाता है. इससे नर्मदा जल प्रदूषित हो रहा है. पिछले दिनों एक समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नर्मदा मैय्या की जय बोलने से नदी शुद्ध होने वाली नहीं है. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से जल प्रदूषण रोकने और नदी को शुद्ध बनाने के काम में सहयोग देने की अपील भी की, लेकिन इस सबके बाद भी नर्मदा में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार इस पवित्र नदी को प्रदूषण मुक्त करना ही नहीं चाहती है. नगरपालिकाओं और नगर निगमों द्वारा गंदे नालों के ज़रिए दूषित जल नर्मदा में बहाने पर सरकार रोक नहीं लगा पाई है और न ही आज तक नगरीय संस्थाओं के लिए दूषित जल के अपवाह की कोई योजना बना पाई है. राज्य के 16 ज़िले ऐसे हैं जिनके गंदे नालों का प्रदूषित पानी नर्मदा में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के कटाव से भी नर्मदा में प्रदूषण बढ़ रहा है. कुल मिलाकर नर्मदा में 102 नालों का गंदा पानी और ठोस मल पदार्थ रोज़ बहाया जाता है, जिससे अनेक स्थानों पर नर्मदाजल ख़तरनाक रूप से प्रदूषित हो रहा है.

होशंगाबाद में 29 नाले हैं, मंडला में 16 और जबलपुर ज़िले में 12 बड़े नाले हैं जो नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं. इनके अलावा खंडवा, बड़वानी और अनूपपुर ज़िलों में नौ-नौ, खरगौन में सात, डिंडौरी में छह और रायसेन ज़िले में पांच नाले नर्मदा को प्रदूषित करते हैं. अधिकृत सूत्रों के अनुसार गंदे पानी और ठोस मल पदार्थों के अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का पानी भी नर्मदा में बहाया जाता है. नर्मदा-कछार में अब पहले जैसा वनक्षेत्र नहीं रह गया है और कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है.

नगरपालिकाओं और नगर निगमों द्वारा गंदे नालों के ज़रिए दूषित जल नर्मदा में बहाने पर सरकार रोक नहीं लगा पाई है और न ही आज तक नगरीय संस्थाओं के लिए दूषित जल के अपवाह की कोई योजना बना पाई है. राज्य के 16 ज़िले ऐसे हैं जिनके गंदे नालों का प्रदूषित पानी नर्मदा में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है.

लाभकारी खेती के लिए किसान कई प्रकार के रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं. एक फसल के दौरान पांच से सात बार सिचाई भी होती है. इसके बाद भी खाद और कीटनाशकों के घातक रसायन खेत की मिट्टी में घुल-मिल जाते हैं जो वर्षाकाल में पानी के साथ बहकर नर्मदा नदी में मिलते हैं और इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. वनक्षेत्रों में कमी के कारण मिट्टी और मुलायम चट्टानों में कटाव से भी नदी में जमाव बढ़ रहा है और प्रदूषण फैल रहा है.

सरकार का जल संसाधन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल नदी जल में प्रदूषण की जांच करता है और प्रदूषण स्तर के आंकड़े काग़ज़ों में दर्ज कर लेता है, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कोई भी गंभीर उपाय नहीं कर रही है. सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरकंटक और ओंकारेश्वर सहित कई स्थानों पर नर्मदा जल का स्तर क्षारीयता पानी में क्लोराईड और घुलनशील कार्बनडाईऑक्साइड का आंकलन करने से कई स्थानों पर जल घातक रूप से प्रदूषित पाया गया. भारतीय मानक संस्थान ने पेयजल में पीएच 6.5 से 8.5 तक का स्तर तय किया है, लेकिन अमरकंटक से दाहोद तक नर्मदा में पीएच स्तर 9.02 तक दर्ज किया गया है. इससे स्पष्ट है कि नर्मदाजल पीने योग्य नहीं है और इस प्रदूषित जल को पीने से नर्मदा क्षेत्र में ग़रीब और ग्रामीणों में पेट से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है, इसे सरकारी स्वास्थ्य विभाग भी स्वीकार करता है. जनसंख्या बढ़ने, कृषि तथा उद्योग की गतिविधियों के विकास और विस्तार से जल स्त्रोतों पर भारी दबाव पड़ रहा है. गर्मी के मौसम में मध्य प्रदेश में नर्मदा तट के ही कई गांव और शहरों में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है. ऐसे में नर्मदा जल को प्रदूषण से बचाने के उपाय गंभीरता से नहीं हो रहे हैं, यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है. यह चिंता तब और भी बढ़ जाती है, जब जनता की सरकार, नर्मदा के धार्मिक-सामाजिक महत्व को अपनी राजनीति के लिए तो भुनाती है और नर्मदा जल को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर लाखों करोड़ों ख़र्च भी करती है, तो दूसरी ओर नगरीय संस्थाएं ग़ैर ज़िम्मेदारी से काम करते हुए गंदे नालों का पानी नर्मदा में बहाकर नदी की पवित्रता को रोज़ नष्ट करती हैं.

संध्या पांडे
feedback@chauthiduniya.com

राजाभोज के नाम पर दुकानदारी

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपने हिन्दू एजेंडे के नाम पर केवल हल्ला मचाना और तमाशा करना जानती है. इसे न तो हिन्दुत्व से कोई सरोकार है और न ही इसे प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की कोई समझ है. इस वर्ष प्रतापी राजाभोज के राज्यारोहण का एक हजारवां वर्ष है. उत्सव प्रिय मध्य प्रदेश सरकार ने राजाभोज का राज्यारोहण समारोह मनाना तय किया है. इस समारोह की आयोजन समिति में मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री का रहना तो समझ में आता है, क्योंकि आयोजन के लिए माल इन्हीं को ख़र्च करना है, लेकिन ढेर सारे भाजपा नेता, भाजपा समर्थक कथित बुद्धिजीवी, सरकार के नौकरशाह समिति में शामिल किए गए हैं. दो-तीन विद्धानों को भी शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक राजाभोज की याद में यह समिति क्या करेगी, तय नहीं हुआ है. आधा साल बीत गया है लेकिन अभी भोज समारोह के कार्यक्रम नहीं बन पाए है. भोपाल में इस समारोह को आयोजित करने के पीछे भाजपा का साम्प्रदायिक दृष्टिकोण ही काम कर रहा है, क्योंकि हिन्दू महासभा और जनसंघ के जमाने से भोपाल का नाम भोजपाल रखने की मांग हिन्दूवादी करते रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार को न तो राजाभोज के बारे में कुछ मालूम है और न ही इसे भोज में कोई गंभीर रुचि है. इसे तो केवल उत्सव करना हैं और पैसा ख़र्च करने हैं. थोड़े से भाजपा समर्थक कलाकारों, बुद्धिजीवियों को उपकृत करने का यह एक बहाना है. जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब धार में भोजशाला विवाद को साम्प्रदायिक रूप देते हुए भाजपा ने लंदन में रखी भोज की सरस्वती की मूर्ति भारत वापिस लाने की मांग उठाई थी, लेकिन भाजपा सरकार को शायद नहीं मालूम कि राजाभोज के दुर्लभ साहित्य का ख़ज़ाना गुजरात के पाटन शहर में उपेक्षित पड़ा हुआ हैं. यदि इसे सुरक्षित भोपाल लाकर, इसके पुनर्लेखन और नवलेखन का काम सरकार कराए, तो इस काम से राजाभोज की यशकीर्ति और भी बढ़ेगी और इनके साहित्य को पुनर्जीवन देकर सरकार उन्हें सच्ची श्रृद्धांजलि भी देने का पुण्य अर्जित कर सकती है. इतिहास प्रसिद्ध मालवा नरेश राजा भोज (1010-1055 ईसवी) प्रतापी नरेश होने के साथ ही विद्यानुरागी भी थे. इन्होंने न केवल ज्ञान विज्ञान विषयों के विद्वानों को संरक्षण दिया, अपितु स्वयं भी अनेक ग्रंथों की रचना की, जो विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है, लेकिन भोज रचित अनेक ग्रंथ आज भी पांडुलिपियों के रूप में जगह-जगह उपेक्षित पड़े हुए हैं.

भारत के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय के पूर्व डीन डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी के अनुसार राजा भोज के निधन के बाद धारा नगरी पर गुजरात के राजा भीम देव ने आक्रमण किया था और राजा के ख़ज़ाने के साथ-साथ ग्रंथालय को भी लूटा था. राजा भीम देव ने भोज रचित जिन ग्रंथों को लूटा था, वे आज भी गुजरात के पाटन नगर में उपेक्षित अवस्था में रखे हुए है.

डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी ने चौथी दुनिया संवाददाता को फोन पर दिए गये एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने स्वयं पाटन में भोज रचित ग्रंथों की पांडुलिपियां देखी है, लेकिन वह या कोई और विद्वान इन ग्रंथों के लेखन अथवा पुर्नलेखन के लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए सुविधा और स्वतंत्रता नहीं है. डॉ. द्विवेदी ने कहा कि आज दुनिया में जिस साहित्य शब्द का प्रचलन है, वह वास्तव में राजा भोज की ही देन है. राजा भोज का प्रभाव क्षेत्र मालवा से पंजाब तक और दक्षिण में केरल राज्य तक था. वह ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं के अनुरागी और विद्वानों के संरक्षक थे. पिछले वर्षों में अथक परिश्रम और शोध के बाद डॉ. द्विवेदी ने मलयालम भाषा में भोज रचित श्रृंगार प्रकाश या साहित्य प्रकाश ग्रंथ की पांडुलिपि प्राप्त की और फिर इसका संस्कृत भाषा में पुर्नलेखन किया है, इस दुर्लभ ग्रंथ का प्रकाशन भी हो गया है, जिसे दुनिया के संस्कृत और साहित्य मर्मज्ञों ने तो सराहा है लेकिन भोज की विरासत पर गर्व करने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने इस ग्रंथ के महत्व को ज़रा भी नहीं समझा है. गुजरात सरकार ने भी इस ग्रंथ को कोई महत्व नहीं दिया है. डॉ. द्विवेदी ने भोज के दुर्लभ साहित्य को लुप्त होने से बचाने के लिए इनकी पांडुलिपियों की सुरक्षा करने और इनके पुर्नलेखन का कार्य शीघ्र किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि बिना केंद्र और राज्य सरकारों के संरक्षण और सहयोग के यह काम नहीं हो सकता है. यदि इन ग्रंथों की उपेक्षा होती रही तो जल्दी ही यह ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे और ज्ञान का एक अमूल्य ख़ज़ाना सदा के लिए नष्ट हो जायेगा. डॉ. द्विवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में भोज की मूर्ति स्थापना के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि भोज अपने साहित्य के कारण अमर है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को इनके दुर्लभ साहित्य की सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए. डॉ. द्विवेदी ने इस दावे को ग़लत और भ्रामक बताया है कि 11वीं सदी के धारा नगरी के राजा भोज ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था. उन्होंने कहा कि भोज सभी धर्मों और सद्विचारों का आदर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया. यह हो सकता है कि भोज नाम के किसी और राजा ने भारत में मुस्लिम शासन के दौरान धर्म परिवर्तन किया हो, और इसका ज़िक्र सरकारी गजेटियर में किया गया हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इतना तो तय है कि 11वीं सदी के राजा भोज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था.

डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी

लक्ष्मीकांत शर्मा

भोज साहित्य में सरकार की रुचि नहीं

डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी ने राजाभोज रचित जिस श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ का पुनर्लेखन और संपादन किया है, यह ग्रंथ मलयालम भाषा में हैं और श्रृंगार प्रकाश नाम के ग्रंथ की मौलिकता संदिग्ध है, लेकिन डॉ. द्विवेदी द्वारा तैयार किए गए इस ग्रंथ को सरकार के संस्कृति विभाग, भाषा विभाग, शिक्षा विभाग या किसी और विभाग ने कोई महत्व नहीं दिया, जबकि सरकारी विभाग कामशास्त्र विषयक किताबें ख़रीदने पर हज़ारों रुपये ख़र्च कर देते हैं. अश्लील चित्रों वाली ये महंगी किताबें आज भी इस विभाग के ग्रंथालय की शोभा बढ़ा रही हैं. लेकिन भोज साहित्य पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com